www.indiamail.com

राष्ट्रीय साप्ताहिक समाचार पत्र

RNI NO. DELHIN/2008/26338

इंडिया मेल

नई दिल्ली प्रकाशित एवं उतरांखण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, मुंबई, हिमाचल, हरियाण, छत्तीसगढ, पंजाब, जम्मू कश्मीर एवं राजस्थान में प्रसारित

|| जैसा देखा-सुना, वैसा ही ||

वर्षः 17 | अंकः 49 | नई दिल्ली , रविवार, 26 जनवरी से 01 फरवरी, 2025 | पृष्ठः संख्या 8 | मूल्यः 3 रूपये

■ भारत के प्रमुख निवेश समझौते ... पृष्ठ 4

■ पर्शियन मूल का समोसा .... पृष्ठ 6

■ तबादलों के बावजूद इंस्पेक्टर.. पृष्ठ 8

■ जनतंत्र जनसेवा की आदर्श... पृष्ठ 2

जातिगत जनगणना पर राहुल गांधी ने बढ़ायी तेजस्वी की मुश्किलें

कुमार कृष्णन

संविधान सुरक्षा सम्मेलन के बहाने राहुल गांधी ने बिहार में चुनावी बिगुल फूंक दिया है। बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। बिहार विधानसभा चुनाव समय पर होंगे, यह तय है। सत्ता और विपक्ष अब दोनों ने इसकी पुष्टि कर दी है। बिहार में चुनावी माहौल के बीच जातिगत जनगणना पर राहुल गांधी के बयान से राजनीतिक तापमान गरमा गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बिहार में जातीय जनगणना को फर्जी करार दिया, जिससे तेजस्वी यादव और राजद के लिए नई मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं।

लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार राहुल गांधी संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करने बिहार पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय में पहुंचकर चुनावी साल में अपने कार्यकताओं को जीत का मंत्र देने के साथ उत्साह भी बढ़ाया। तेजस्वी यादव ने भले ही इंडिया गठबंधन को लोकसभा चुनाव तक सीमित रहने का बयान दिया था, लेकिन राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि बिहार में इंडिया गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ा जाएगा पर अब राहुल गांधी ने बिहार की जातीय जनगणना को फेक बताकर एक नए विवाद को जन्म दे दिया है।

राहुल गांधी ने जातीय जनगणना की मांग को दोहराते हुए स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी इसे किसी भी कीमत पर करवाकर रहेगी। उन्होंने बिहार में कराई गई जाति आधारित गणना को ह्यफर्जी' बताया और कहा कि यहां लोगों को बेवकूफ बनाया गया।

बिहार में सीट बंटवारे को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच पिछले दिनों काफी तल्खियां बढ़ी रहीं। लालू ने ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक का नेता बनाने की वकालत की तो तेजस्वी ने इंडिया गठबंधन को सिर्फ लोकसभा चुनाव तक सीमित रहने की बात की। इन सबके बीच राहुल गांधी से तेजस्वी यादव कुछ सेकेंड के लिए मिले और लालू यादव से मिलने के लिए आवास आने का आमंत्रण दिया।

बहरहाल राहुल गांधी,लालू यादव से मिलने उनके आवास भी पहुंच गए। साथ में शाम की चाय पी और चाय पर चर्चा भी हुई। तेजस्वी यादव भले ही इंडिया गठबंधन के लोकसभा चुनाव तक सीमित होने की बात कह चुके हैं लेकिन राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय में ऐलान कर दिया कि बिहार में चुनाव इंडिया गठबंधन के तहत ही लड़ा जाएगा।

इधर राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने भी साफ कर दिया है कि महागठबंधन यह विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लक्ष्य के साथ लड़ेगा।

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जातीय जनगणना को मुख्य मुद्दा बनाया था। तेजस्वी यादव ने बार-बार दावा किया था कि उनकी कोशिशों की वजह से ही बिहार में जातीय जनगणना संभव हो पाई। तेजस्वी ने इसे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपनी रणनीति का अहम हिस्सा बनाया था। तेजस्वी ने कहा था, 'हमने विकास के साथ-साथ जाति आधारित गणना कराई और आरक्षण की सीमा भी बढ़ाई। हमने जो कहा, वह किया।

बिहार चुनाव में जातीय जनगणना को तेजस्वी यादव के बड़े 'चुनावी हथियार' के रूप में देखा जा रहा था। माना जा रहा था कि जातीय जनगणना तेजस्वी की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। अब उसी हथियार की 'धार' को राहुल गांधी ने 'कुंद' कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में हुई जातीय जनगणना फर्जी थी। बिहार, लंबे अरसे से सामाजिक न्याय की लड़ाई का केंद्र है। भाजपा की शुरू से कोशिश रही है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में विपक्ष कमजोर रहे। बिहार आकर राहुल गांधी ने यह संदेश देने की कोशिश की कि सामाजिक न्याय की ताकत कमजोर नहीं हुई हैं, बल्कि पहले की तरह एकजुट है। बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण और राजनीतिक गठबंधन की साख पर राहुल गांधी की यह यात्रा क्या असर डालेगी, यह देखना दिलचस्प होगा।

पटना में 'संविधान सुरक्षा सम्मेलन' में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हम चाहते थे कि जैसे हर जगह गंगा का पानी बहता है, वैसे ही संविधान की विचारधारा भी देश के हर व्यक्ति, हर संस्था तक पहुंचे।

राहुल ने कहा कि जैसे हमारा संविधान इस हॉल के कोने-कोने तक पहुंच गया। वैसे ही हम संविधान को हिंदुस्तान के कोने-कोने तक पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि संविधान सिर्फ किताब नहीं है। इस किताब में हजारों साल की सोच है। इसमें हिंदुस्तान की सोच है। इस संविधान में भगवान बुद्ध, नारायण गुरु जी, बसवन्ना जी, फुले जी, गांधी जी, अंबेडकर जी की आवाज है। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, इसमें दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के साथ हुए अन्याय का दुख-दर्द भी है। हमारे संविधान ने इस दर्द को कम करने का काम किया है।

हम जाति जनगणना की अपनी मांग पर कायम रहेंगे, यह विकास योजनाओं के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों और दलितों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो मिला लेकिन उनके पास कोई शक्ति नहीं है।

जातीय जनगणना का श्रेय लेने की होड़ तेजस्वी यादव और एनडीए के बीच पहले से ही चल रही थी। 2020 में एनडीए सरकार ने जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया था। बाद में, नीतीश कुमार के महागठबंधन में आने के बाद यह प्रक्रिया पूरी हुई और रिपोर्ट भी जारी हुई। अक्टूबर 2023 में आनन-फानन में आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई, लेकिन हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस रोक को हटाने से इनकार कर दिया। तेजस्वी यादव लगातार भाजपा को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते रहे। अब राहुल गांधी का यह बयान राजद के लिए यह चुनौती बन सकता है। एनडीए इस बयान को तेजस्वी के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिहार की राजनीति के जानकार मानते हैं कि जातीय जनगणना के आंकड़े और आरक्षण का मुद्दा 2025 के चुनाव में असर डालेंगे।

महाकुंभ में मोनालिसा दर्शन

नवीन खाती

धन्य हैं वे श्रद्धालु जो कुंभ में गंगा दर्शन की जगह मोनालिसा की चितवन लीला की रील बनाने में व्यस्त हैं। स्त्री की आंखों की गहरी झील में डूबना मानवीय फितरत है। मेनका मिल जाएं तो ऋषि मुनियों के तप भी भंग हो जाते हैं। हिंदी लोकोक्तियाँ और कहावतें बरसों के अध्ययन और जीवन दर्शन, मनोविज्ञान पर आधारित हैं। ह्नआए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास' एक प्रचलित लोकोक्ति है। इसका अर्थ है कि किसी विशेष उद्देश्य से हटकर किसी अन्य कार्य में व्यस्त हो जाना। बड़े लक्ष्य तय करने के बाद छोटे-मोटे इतर कामों में भटक जाना ।

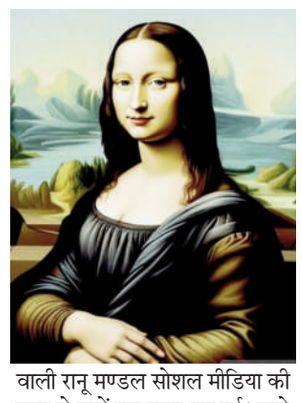

कुम्भ में इंदौर की जो मोनालिसा रुद्राक्ष और 108 मोतियों वाली जप मालाएं बेचती हैं। उनकी मुस्कान से अधिक उनकी भूरी आंखों की चर्चा है। वे शालीन इंडियन ब्लैक ब्यूटी आइकन बन गई हैं। यह सब सोशल मीडिया का कमाल है। एक विदेशी युवती सौ रुपए लेकर कुंभ यात्रियों के साथ सेल्फी खिंचवा रही है। दिल्ली में बड़ा पाव बेचने वाली सोशल मीडिया से ऐसी वायरल हुई कि रियलिटी शो में पहुंच गई। रेलवे स्टेशन व फुटपाथ पर लता मंगेशकर की आवाज में गाने वाली रानू मण्डल सोशल मीडिया की कृपा से रातों रात स्टार बन गई। जाने कितने उदाहरण हैं सोशल मीडियाई ताकत के कुछ भले, कुछ बुरे। आजकल बेरोजगारी का हल सोशल इन्फ्लूएंसर बन कर यू ट्यूब और रील से कमाई ने कर दिया है।

तो कुंभ में मिली मोनालिसा की भूरी चितवन इन दिनों मीडिया में है। यद्यपि इतालवी चित्रकार लियोनार्दो दा विंची की विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा सुन्दर मुस्कान के लिए सुप्रसिद्ध है। यह पेंटिंग 16वीं शताब्दी में बनाई गई। फ़्लोरेंस के एक व्यापारी फ़्रांसेस्को देल जियोकॉन्डो की पत्नी लीजा घेरार्दिनी को मॉडल बनाकर यह पेंटिंग बनाई गई थी। यह सुप्रसिद्ध पेंटिंग आजकल पेरिस के लूवर म्यूज़ियम में रखी हुई है। इस पेंटिंग को बनाने में लिओनार्दो दा विंची को 14 वर्ष लग गए थे। पेंटिंग में 30 से ज्यादा ऑयल पेंट कलर लेयर्स है। इस पेंटिंग की मुस्कान ही इसकी विशेषता है। वैसे भी कहा गया है कि अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द न मिलें तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिये। शब्द उलझा सकते है किन्तु मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है।

तो अपना कहना है कि मुस्कराते रहिए। माला फेरत युग गया, माया मिली न राम। तो कुंभ स्नान से अमरत्व मिले न मिले, पाप धुले न धुलें , किसे पता है पर रामनामी माला खरीदिए, मोनालिसा के संग सेल्फी सत्संग कीजिए, इसमें त्वरित प्रसन्नता सुनिश्चित है।

दिल्ली में चुनाव हार रही है बीजेपी: मनीष सिसोदिया

दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज होने के बीच भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने बीजेपी का संकल्प पत्र पार्ट 3 जारी किया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह के निशाने पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल रहे। अब इसको लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से पलटवार किया गया है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि अमित शाह ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है। उनकी भाषा और घोषणा को देखकर लगा कि वो दिल्ली चुनाव में हार रहे हैं। दिल्ली में कोई विजन नहीं है। इस बारे में कोई बात नहीं रखी गई है। 50 हजार नौकरी देने की बात कही है। ढाई करोड़ की जनसंख्या है और केवल 50 हजार नौकरी देने की बात कर रहे हैं। कोविड के दौरान और कोविड के बाद 12 लाख नौकरियां केजरीवाल ने दी है।

दिल्ली के पूर्व मंत्री सिसोदिया ने एक्साइज पॉलिसी घोटाला मामले पर कहा कि यह मामला अभी भी कोर्ट में है और वे ही अंतिम फैसला ले सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि शराब घोटाला मामला 'अंतहीन सुरंग' में है और बीजेपी जैसे-जैसे मामला अदालत के अंदर जा रहा था, उन्होंने अपनी 'मनोहर कहानियाँ' बनाईं। गौरतलब है कि अमित शाह ने आज बीजेपी का संकल्प पत्र भाग 3 जारी किया। इस दौरान उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा।

सिंधिया हाउस में अवैध निर्माण पर एनडीएमसी का शिकंजा

नवीन खाती

नई दिल्ली। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने कनॉट प्लेस स्थित सिंधिया हाउस के 10-बी, ग्राउंड और मेजेनाइन फ्लोर में अवैध निर्माण के मामले का गंभीरता से संज्ञान लिया है।एनडीएमसी ने इस मामले में नई दिल्ली नगर परिषद अधिनियम, 1994 की धारा 249 के तहत नोटिस जारी किया है।

याद दिला दें कि अगस्त 2022 में भी एनडीएमसी के वास्तुविद विभाग द्वारा कनॉट पैलेस स्थित सिंधिया हाउस 10बी की रिपेयर और रेनोवेशन के लिए दी गई अनुमति में अनियमितताएं पाई गई थीं। 31अगस्त,2022 को लोड किए गए नक्शे में दो दुकानों का उल्लेख था लेकिन उसके बाद मांगी गई अनुमति में इन दोनों दुकानों को एक कर दिया गया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रॉपर्टी मालिक ने गैरकानूनी तरीके से बीच की लोड बेयरिंग वाल और पिलर हटाकर दो दुकानों को एक किया है। इसके अलावा अवैध रूप से सार्वजनिक संपत्ति पर निर्माण कार्य भी किया गया है।

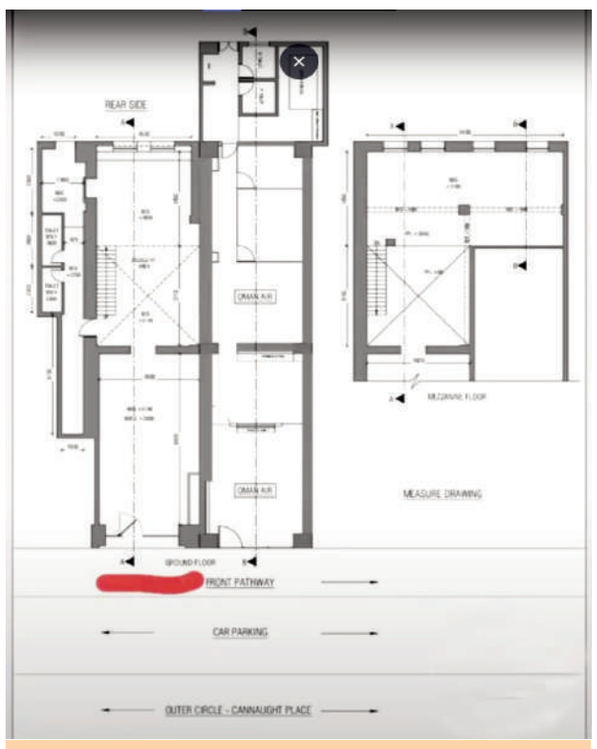

2022 का अपलोड नक्शा, जिसमें दो दुकान हैं, जिनमें एक दुकान का छज्जा हेतु अनुमति मांगी गई

सार्वजनिक भूमि पर ईंट की दीवार और शेड की मदद से अतिक्रमण

एनडीएमसी को पहले इस बदलाव का ध्यान रखना चाहिए था और बिना उचित जांच के अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। एनडीएमसी को इस मामले की पुनः जांच करनी चाहिए थी और दी गई अनुमति पर तत्काल रोक लगानी चाहिए थी।

अब पुनः एनडीएमसी द्वारा इस मामले पर संज्ञान लिया गया हैं और एक जनवरी 2025 को नोटिस जारी कर बताया हैं कि उक्त भवन में स्वीकृत योजना के विपरीत कई बदलाव किए गए हैं।

जिसमें साफ तौर पर बताया गया हैं कि एम एस फ्रेम के जरिए 4 ७ 2मीटर और 3.5 ७ 1मीटर का अवैध निर्माण किया गया है। स्वीकृति के बिना 1७ 2.1 मीटर का दरवाजा लगाया गया है। ग्राउंड फ्लोर पर प्रांगण के पीछे का दरवाजा भी बिना अनुमति के बंद कर दिया गया है।

नगरपालिका परिषद ने भवन स्वामी व अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे इन अवैध निमार्णों को स्वीकृत योजना के अनुरूप लाएं। साथ ही उन्हें नोटिस प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर उचित जवाब देने का निर्देश दिया गया है हालांकि समय बीत जाने के उपरांत भी प्रॉपर्टी ऑनर ने इसका जवाब नहीं दिया है।

शहरी नियोजन के जानकारों का कहना है कि यह मामला एनडीएमसी के नियमों और शहर की संरचना के साथ खिलवाड़ का है। यदि समय रहते ऐसे मामलों पर सख्ती नहीं दिखाई गई, तो दिल्ली का ऐतिहासिक और स्थापत्य अपना महत्व खो सकता है।

सिर्फ एक छज्जे की अनुमति मिली थी मगर अवैध रूप से दूसरी दुकान पर भी छज्जा डाल दिया गया..

लेकिन इस बार आर्किटेक्ट ईबीआर-एसटीसी ने इसे गंभीरता से लिया है, अब यदि भवन स्वामी एनडीएमसी के निदेर्शों का पालन नहीं करता है तो परिषद इस पर कठोरतम कार्रवाई कर सकती है। सिंधिया हाउस जैसे प्रतिष्ठित स्थान पर इस प्रकार की अनियमितताओं ने प्रशासन और आम जनता के बीच तीखी बहस छेड़ दी है। क्या एनडीएमसी इस मामले में अपना रुख और सख्त करेगी? यह देखना बाकी है।

गौरतलब है कि सन 2022 में जो प्लान दिया गया था वो आज भी परिषद के पोर्टल में मौजूद होगा लेकिन वर्तमान में वहां दो दुकानों की एक दुकान कैसे हो गई? क्या एनडीएमसी ने इस बात पर कोई नोटिस दिया, ये एक बड़ा सवाल है।

सूत्रों के अनुसार उक्त नोटिस का जवाब सात दिनों के भीतर दिया जाना था मगर अब तक नहीं दिया गया है। ऐसे में 2024 में एचसीसी द्वारा आई अनुमति, जिसका समय सात जनवरी को खत्म हो गया था, उसकी समयसीमा क्यों बढ़ा दी गई? यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जिस वास्तुविद ने बार-बार प्लान बदलकर अपलोड किया उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई, क्या उसे डी-बार किया गया या उस वास्तुविद को एनडीएमसी कार्यालय में बुलाकर पूछा गया कि ये प्लान उसने अपलोड किया या नहीं? हमारी सूचना के अनुसार एक वास्तुविद ने एनडीएमसी के अधिकारियों को लिखकर सूचित किया था कि कोई मेरे नाम या पोर्टल का दुरूपयोग कर रहा है, क्या ये वही वास्तुविद तो नहीं? इसी वास्तुविद के द्वारा ही एफ-20 और ई-1 कनॉट प्लेस, जिनका जिक्र हमने अपने पिछले अंकों में किया था, के नक़्शे भी अपलोड किए थे।

> एफ-१० और ई-1 कनॉट प्लेस के प्रॉपर्टी ऑनर को कुछ नोटिस जारी किए गए हैं जिसकी विस्तृत जानकारी हम अपने अगले अंक में देंगे और यह भी बताने का प्रयास करेंगे कि टेम्पर्ड नक़्शे के अलावा अपलोड किए गए दस्तावेजों के साथ भी किस हद तक छेड़छाड़ की गई है।

सूत्रों के अनुसार एफ-20 और ई-1 कनॉट प्लेस के प्रॉपर्टी ऑनर को कुछ नोटिस जारी किए गए हैं जिसकी विस्तृत जानकारी हम अपने अगले अंक में देंगे और यह भी बताने का प्रयास करेंगे कि टेम्पर्ड नक़्शे के अलावा अपलोड किए गए दस्तावेजों के साथ भी किस हद तक छेड़छाड़ की गई है।

इन तथ्यों की पूर्ण जानकारी के लिए 'इंडिया मेल' प्रयासरत है कि किस तरह एक ही व्यक्ति, जो कनॉट प्लेस स्थिति अधिकांश प्रॉपर्टीज की रेनोवेशन का काम कर रहा है, उस व्यक्ति के अधीन कितने आर्किटेक्ट कार्यरत हैं।

संपादकीय

अभिव्यक्ति व धर्म का स्वतंत्रता से नहीं संबंध

गाहे-बगाहे कोर्ट की सख्ती के बावजूद विभिन्न धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकरों का इस्तेमाल बंद नहीं हुआ। दिनभर के थके-हारे लोग जब घर में आराम करते हैं तो लाउडस्पीकरों की तीव्र ध्वनि उनकी शांति में खलल डालती है। डॉक्टर भी कहते हैं कि नींद में किसी भी तरह का व्यवधान व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। फिर जो लोग पहले से बीमार होते हैं,उनके लिये तो तेज शोर असहनीय होता है। लेकिन वर्तमान ध्रुवीकृत समाज में लाउडस्पीकरों का बेलगाम शोर प्रतिष्ठा का मुद्दा बन जाता है। लोग परेशान होने पर भी शिकायत नहीं करते। उन्हें डर होता है कि धार्मिक समूह उन्हें निशाना बना सकते हैं। विडंबना यह है कि नियामक एजेंसियां भी स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई नहीं करती। इस बाबत दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार शोर-शराबे पर काबू करे। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि लाउडस्पीकरों का इस्तेमाल किसी भी धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। इसलिए ध्वनि प्रदूषण के नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने पुलिस से कहा कि धार्मिक स्थलों पर लगाए गए लाउडस्पीकरों के शोर को मापने के लिए ऐप का प्रयोग करे ताकि नियम का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा सके। उन पर जुमार्ना लगे। फिर भी उल्लंघन होने पर प्रबंधकों व संचालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। यहां तक कि कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिए कि शिकायतकर्ता की सुरक्षा के मद्देनजर उसकी पहचान गोपनीय रखी जाए। साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों के भीतर ऐसा सिस्टम लगे, जो उसकी ध्वनि के स्तर को स्वतः नियंत्रित करे। न्यायाधीशों की दो सदस्यीय बेंच ने माना कि निर्धारित मानक से अधिक शोर सेहत पर प्रतिकूल असर डालता है। अतः कोई व्यक्ति इसके इस्तेमाल को अपना अधिकार नहीं बता सकता। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार धार्मिक स्थलों से होने वाले शोर पर नियंत्रण के लिये ठोस प्रयास करे।

कोर्ट ने राज्य सरकार से यह भी कहा कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों तथा जनसमूह को संबोधित करने वाले सिस्टम की शोर सीमा को नियंत्रित करे। नियामक एजेंसियां निगरानी व शोर नापने के लिये ऐप प्रयोग करे। नियमानुसार दिन में ध्वनि का स्तर 55 तथा रात में 45 डेसिबल से अधिक नहीं हो। दरअसल, मुंबई में कुर्ला क्षेत्र में एक धार्मिक स्थल से निर्धारित मानकों से अधिक स्तर का ध्वनि प्रदूषण रोकने में पुलिस की निष्क्रियता के खिलाफ यह याचिका दायर की गई थी। वास्तव में लोग तभी शिकायत करते हैं जब ध्वनि का स्तर सहने की सीमा पार कर जाता है। अदालत ने शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रख कर कार्रवाई करने को कहा ताकि उसे सांप्रदायिक आधार पर निशाना न बनाया जा सके। यदि जुमार्ना लगाने के बावजूद स्थिति नहीं सुधरती तो पुलिस धार्मिक स्थल पर लगे लाउडस्पीकर को जब्त करे। फिर उसके लाइसेंस को रद्द करने की कार्रवाई करे। साथ ही ध्वनि प्रदूषण नियंत्रक नियमों तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत भी कार्रवाई हो। कोर्ट माना कि कठोर कानून के अभाव में लाउडस्पीकरों के उपयोगकर्ता नियम-कानून को नजरअंदाज करने लगते हैं। नियामक एजेंसियों की निष्क्रियता पर चिंता जताते हुए अदालत का कहना था कि लोग ध्वनि प्रदूषण को लेकर संविधान में वर्णित अभिव्यक्ति व धार्मिक आजादी का तर्क देते हैं, लेकिन इस पर रोक लगाना किसी भी स्थिति मे मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण नहीं है। अतः ध्वनि की कर्कशता पर अंकुश लगाकर लोगों को राहत दी जानी चाहिए। दरअसल, पुलिस ऐसे मामलों में इसलिए भी उदासीन रहती है कि कहीं उन पर धार्मिक भावनाएं आहत होने का आक्षेप न लगा दिया जाए। कमोबेश यह स्थिति पूरे देश में और विगत में आए अदालत के फैसले की भी अनदेखी की जाती रही है। कई बार तो प्रशासन की अनुमति के बिना सार्वजनिक कार्यक्रमों का लाउडस्पीकरों से संबोधन बदस्तूर जारी रहता है। लोग इसलिये भी शिकायत नहीं करते हैं ताकि कोई टकराव न हो। धर्म विशेष के लोग उनके घरों के आसपास ही रहते हैं। ऐसे में उन्हें हिंसा की आशंका रहती है। निस्संदेह, नियंत्रण के लिए ढाई दशक पहले बनाये गए ध्वनि प्रदूषण विनियमन व नियंत्रण नियमों को बदलते वक्त के साथ प्रभावी बनाने की जरूरत है।

युद्धमुक्त विश्व के ट्रंप के संकल्पों की रोशनी

राष्ट्रपति के तौर पर अपने दूसरे कार्यकाल पर लौटने से पहले ट्रंप ने ह्यतीसरा विश्व युद्धह्ल रोकने की कसम खाकर दुनिया में शांति, अमन एवं अयुद्ध की संभावनाओं को बल दिया है। 47वें राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप ने शपथ से एक दिन पहले गाजा में हुए युद्ध विराम का क्रेडिट भी लिया। रूस और यूक्रेन युद्ध भी खत्म करने की प्रतिबद्धता दोहरायी गयी है। बावजूद इनके विश्व युद्ध के कयास तेजी से लग रहे हैं। इसे लेकर भी कई सवाल उठते हैं कि क्या सच में तीसरा विश्व युद्ध होना इतना आसान है? लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ह्यमैं यूक्रेन में युद्ध खत्म कर दूंगा। मैं मध्य पूर्व में अराजकता रोक दूंगा और मैं तीसरे विश्व युद्ध को होने से रोक दूंगा।ह्ल निश्चित ही ट्रंप के इन संकल्पों से अमेरिका में एक नए युग का आगाज हो रहा है, जो दुनिया में भी एक नई युद्ध मुक्त समाज-संरचना के बड़े बदलावों की ओर इशारा कर रहा है। राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से ही ट्रंप कई संकेत ऐसे दे चुके हैं, जिनसे लगने लगा है कि दुनिया बदलने वाली है। ये बदलाव इस बात पर केंद्रित रहेंगे कि अमेरिका को फिर एक बार महान बनना है। यह ह्यमेक अमेरिका ग्रेट अगेनह्ल का नारा डोनाल्ड ट्रंप की एक नई पहचान बन गया है और बहुत संभावना है कि इस बार ट्रंप अपने सपने को साकार करने के लिए दुस्साहस का भी परिचय देते हुए युद्ध की मानसिकता वाले देशों की सोच में बदलाव का कारण बन जाये। विश्व में अनेक देशों के बीच युद्ध चल रहे हैं एवं ऐसे ही युद्ध की व्यापक संभावनाएं बनी हुई हैं। विश्व युद्ध कई कारणों से शुरू हो सकते हैं। जैसे राष्ट्रवाद यानी अपने देश के प्रति अत्यधिक लगाव और अन्य देशों के प्रति घृणा। जब राष्ट्रवाद चरम पर पहुंच जाता है तो युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है या फिर एक शक्तिशाली देश दूसरे देशों पर अपना अधिकार जमाना चाहता है, तो इससे युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है। इसके अलावा देशों के बीच आर्थिक प्रतिस्पर्धा भी युद्ध का कारण बन सकती है। साथ ही धार्मिक मतभेद भी युद्ध का कारण बन सकते हैं और किसी देश में राजनीतिक अस्थिरता होने पर पड़ोसी देशों में भी अशांति

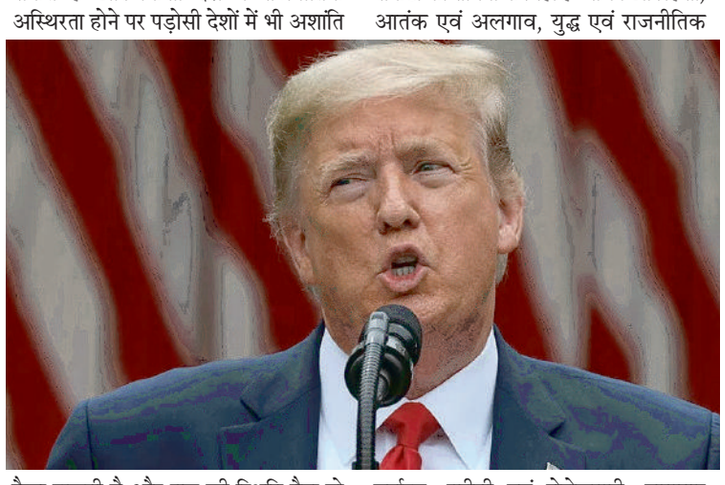

फैल सकती है और युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है। युद्ध की इन व्यापक संभावनाओं पर ट्रंप के संकल्प से विराम लगना विश्व की समाज-व्यवस्था, आर्थिक विकास एवं सह-जीवन के लिये एक शुभ संकेत है। क्योंकि विश्व युद्ध के परिणाम बहुत ही विनाशकारी होते हैं। इसमें लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। युद्ध से देशों की अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान पहुंचता है। साथ ही युद्ध से समाज में अस्थिरता फैल जाती है, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी बढ़ जाती है और युद्ध के बाद देशों के राजनीतिक नक्शे में बदलाव आ सकता है। अमेरिका दुनिया में अमन चाहता है और नये राष्ट्रपति ट्रंप ने यदि किसी भी देश के युद्ध में सेना नहीं भेजने का संकल्प लिया है तो इससे दुनिया में युद्ध की संभावनाओं पर विराम लगना तय है। क्योंकि अब तक शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका ही दुनिया मे युद्ध की भूमि तैयार करता रहा है, अपनी सेना एवं सैन्य सामान भेज कर युद्ध की भूमि को उर्वरा बनाता रहा है। विश्व समुदाय कई संकटों का सामना कर रहा है- संघर्ष और हिंसा, आतंक एवं अलगाव, युद्ध एवं राजनीतिक वर्चस्व, गरीबी एवं बेरोजगारी, लगातार सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ, पर्यावरणीय संकट और दुनिया भर के लोगों के स्वास्थ्य और भलाई के लिए चुनौतियाँ आदि जटिलतर स्थितियों के बीच ट्रंप के नये संकल्प एवं योजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। आज युद्ध और तनाव की समस्या बढ़ती जा रही है।

हथियारों का उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है। हर देश परमाणुशक्ति संपन्न बनने के लिए प्रयासरत है। यह एक अजीबोगरीब स्थिति है। युद्ध की आशंका को खत्म करने के लिए हथियारों का जखीरा बढ़ाया जा रहा है। पहले बीमारी पैदा की जा रही है, फिर उसके इलाज का उपाय ढूंढा जा रहा है। इसमें अब तक अमेरिका की ही सर्वाधिक भूमिका रही है, लेकिन अब उसके नये राष्ट्रपति की युद्धमुक्त विश्व संरचना की सोच से दुनिया में शांति एवं अमन कायम होगा। युद्ध से कभी किसी का भला नहीं होता। वह सदैव अपने पीछे दुख भरी यादें छोड़कर जाता है। युद्ध से किसी मां का बेटा उसे बिछड़ जाता है, किसी बहन का भाई उससे बिछड़ जाता है, कोई स्त्री अपने पति को खो देती है, कोई बेटी अपने पिता को खो देती है। इस तरह युद्ध केवल जान लेता है। इसके अलावा युद्ध से संपत्ति भी नष्ट होती है एवं विकास अवरूद्ध होता है। इसके विपरीत यदि सब जगह शांति हो, लोग आपस में नहीं लड़ें, देशों में आपस में युद्ध नहीं हो, तो विकास होता है। ट्रंप ने अमेरिकी राजनीति के तेवर-कलेवर को तो बदला ही है और वह वहां लोकतंत्र को भी बदलने जा रहे हों, तो कोई आश्चर्य नहीं। उनकी टीम के अनेक दिग्गज परिवर्तन के आकांक्षी हैं। न जाने कितने परिवर्तन ट्रंप के शासन में लागू होंगे। उम्मीद करनी चाहिए कि ट्रंप की नई टीम अमेरिकी परंपराओं का यथासंभव निर्वाह करते हुए ही देश को फिर से महान बनाएगी। लेकिन इस बार अमेरिकी परम्पराओं में युद्ध एवं हिंसा के स्थान पर शांति, विकास एवं हथियार मुक्ति के संकल्प होना बड़ी एवं राहतभरी बात है। हालांकि, अमेरिका को महान बनाने के अभियान पर कई सवाल भी हैं। क्या अमेरिकी निर्णायकों ने मान लिया है कि अमेरिका अब महान नहीं रहा? इस अभियान के नाम से तो शायद यही लगता है कि अमेरिकी विचारकों ने अपने देश के महान न रह पाने की वजहों का पता भी लगा लिया है। उनकी नजर उन अमेरिकी चालाकियों पर भी निस्संदेह पड़ी होगी, जिनकी वजह से अमेरिकियों की अक्सर आलोचना होती है। इन वजहों में युद्ध एवं हथियारों की होड़ बड़ी वजह रही है। अनेक राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि युद्ध, हिंसा, आतंकमुक्त नये अमेरिका को विकसित करने एवं विश्व में शांति के संकल्प को देखते हुए अमेरिका को शुरू से ही भारत के साथ खड़ा रहना चाहिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अमेरिका सबसे पुराना जीवित लोकतंत्र है, दुनिया में युद्ध एवं आतंक के खिलाफ भारत हमेशा अग्रसर रहा है, युद्ध का अंधेरा मिटाने, शांति का उजला करने एवं अहिंसा-सहजीवन की कामना ही भारत का लक्ष्य रहा है। इसीलिये भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लगातार युद्ध विराम की कोशिश करते रहे हैं। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत और अमेरिका के रिश्तों पर क्या असर होगा, इसे लेकर विशेषज्ञ कई तरह की उम्मीदें जता रहे। जानकारों के मुताबिक, ट्रंप के आने से भारत और अमेरिका के संबंध और गहरे होंगे। चीन को लेकर दोनों देशों की चिंता इन्हें करीब लाएगी। यह ट्रेंड पिछले पांच अमेरिकी राष्ट्रपतियों के कार्यकाल जैसा ही रहेगा। क्वाड और मजबूत होगा। प्रशासन के कई विभागों में भारत के अच्छे संबंध बनेंगे। राजनीतिक और वैचारिक तालमेल भी अच्छा रहने की उम्मीद की जा रही।

इसके साथ ही रक्षा, खुफिया और सुरक्षा मामलों में दोनों देशों के बीच भरोसा बढ़ेगा। टेक्नोलॉजी में सहयोग की संभावनाएं बढ़ने के आसार हैं। सबसे अहम है भारत की युद्ध एवं आतंक मुक्त विश्व बनाने की योजना, इसको लेकर ट्रंप भी आगे आये है जो नये सूरज का अभ्युदय है। लेकिन ट्रंप का नया दौर कहीं मौखिक हमलों या कटु उद्गारों तक ही सीमित न रह जाए। इसके लिये जरूरी है कि वह भारत की शांतिपूर्ण नीतियों एवं योजनाओं को अग्रसर करें। भारत सहित तमाम दुनिया यही उम्मीद करेगी कि ट्रंप दुनिया में चल रहे बड़े युद्धों और छद्म युद्धों को रोकने में सफलता हासिल करें साथ ही आतंकवाद के खिलाफ ईमानदार रवैया अपनाये ताकि नई उबरती उभरती दुनिया में अमेरिकी सचमुच महानता का वरन कर सके।

नये संकल्पों एवं नये प्रयोगों से समृद्ध होता गणतंत्र

गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है, इसी दिन 26 जनवरी, 1950 को हमारी संसद ने भारतीय संविधान को पास किया। इस दिन भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बना। इसने ब्रिटिश शासन के भारत सरकार अधिनियम 1935 को पूरी तरह खत्म कर दिया और अपना स्वतंत्र संविधान इसी दिन लागू किया। इस वर्ष 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबिआंतो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यह उनके राष्ट्रपति पद संभालने के बाद भारत की पहली आधिकारिक यात्रा होगी, जो दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी। इस वर्ष की थीम ह्यस्वर्णिम भारत- विकास के साथ विरासतह्ल है। यह थीम देश की विरासत को संभालते हुए भारत की प्रगति की यात्रा को दर्शाती है। किसानों, शिक्षकों, न्यायविदों, मजदूरों, वैज्ञानिकों, उद्योगपतियों, व्यापारियों और इंजीनियरों की विविध भूमिकाओं की सामूहिक शक्ति हमारे देश को ह्यजय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधानह्ल की भावना के अनुरूप आगे बढ़ने में सक्षम बना रही है। इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के साथ-साथ पूरे भारत से कई ऐसे लोगों को भी आमंत्रित किया जा रहा है जिन्होंने अपने गांव, समाज एवं राष्ट्र में विकास के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किया है, इस तरह इस बार गणतंत्र दिवस समारोह ऐसे अनेक नये प्रयोगों एवं प्रदर्शनों का साक्षी बन रहा है।

भारतीय संविधान दुनिया का सबसे विशिष्ट संविधान माना जाता है। भारत की संविधान सभा ने दुनिया के सभी संविधानों का अध्ययन किया और हर संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को अपने संविधान में शामिल किया। नागरिक स्वतंत्रता के जितने अधिकार भारतीय संविधान में हैं उतने दुनिया के किसी अन्य संविधान में नहीं। भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता संविधान की विशालता एवं समग्रता है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का प्रावधान तो है लेकिन इसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने धमार्नुसार आचरण करने की पूरी स्वतंत्रता है। इसमें नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य की स्पष्ट विवेचना है। इसमें संघात्मकता भी है और एकात्मकता भी है। भारतीय संविधान में सत्ता चयन के लिये संसदीय प्रणाली को सुनिश्चित किया है तथा संचालन के लिये विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे तीन अंग सुनिश्चित किये। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य सरकार के बीच विषयों और कार्यों का स्पष्ट विभाजन है।

केन्द्र सरकार को कुछ आपात अधिकार भी दिये गये हैं जिससे वह केन्द्र राज्य में हस्तक्षेप कर सकता है। इतने अनूठे, विलक्षण एवं समग्र संविधान के बावजूद छिहत्तर वर्षों में हमारा गणतंत्र कितनी ही कंटीली झाड़ियों में फँसा रहा। लेकिन अब इन राष्ट्रीय पर्वों को मनाते हुए संप्रभुता का अहसास होने लगा है।

गणतंत्र का जब हम जश्न मनाते हैं, तो उसमें कुछ कर गुजरने की तमन्ना भी जागती है तो अब तक कुछ न कर पाने की बेचैनी भी दिखती है। हमारी जागती आंखो से देखे गये स्वप्नों को आकार देने का विश्वास मुखर होता है तो जीवन मूल्यों को सुरक्षित करने एवं नया भारत निर्मित करने की तीव्र तैयारी सामने आती है। अब होने लगा है हमारी स्व-चेतना, राष्ट्रीयता एवं स्व-पहचान का अहसास। जिसमें आकार लेते वैयक्तिक, सामुदायिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राष्ट्रीय एवं वैश्विक अर्थ की सुनहरी छटाएं हैं।

राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस हमारी उन सफलताओं की ओर इशारा करता

है जो इतनी लंबी अवधि के दौरान अब जी-तोड़ प्रयासों के फलस्वरूप मिलने लगी हैं। यह हमारी विफलताओं पर भी रोशनी डालता है कि हम नाकाम रहे तो आखिर क्यों! क्यों हम राष्ट्रीय एकता और अखण्डता को सुदृढ़ता नहीं दे पाये हैं? क्यों गणतंत्र के सूरज को राजनीतिक अपराधों, घोटालों और भ्रष्टाचार के बादलों ने घेरे रखा है? यह सही है और इसके लिए सर्वप्रथम जिस इच्छा-शक्ति की आवश्यकता है, वह हमारी शासन-व्यवस्था एवं शासन नायकों में सर्वात्मना नजर आनी चाहिए और ऐसा होने लगा है तो यह सुखद अहसास है। बावजूद अभी भी देश की राजनीति अनेक विसंगतियों एवं विडम्बनाओं से घिरी है। यह विडंबना है कि आजादी की हीरक जयंती मना चुके देश में मतदाता को हम इतना जागरूक नहीं बना पाए कि वो अपने विवेक से मतदान कर सके। निस्संदेह, यदि देश में गरीबी और आर्थिक असमानता है तो हमारे नीति-नियंताओं की विफलता ही है। लेकिन हम में कम से कम इतना राष्ट्र प्रेम तो होना चाहिए कि निहित स्वार्थों के लिये हम राष्ट्रीय हितों की बलि न चढ़ाएं। दिल्ली के चुनाव में मुफ्त-मुफ्त का जो खेल विधानसभा चुनाव प्रक्रिया के दौरान चल रहा है, तीनों प्रमुख रजनीतिक दल नित नये राजनीतिक प्रलोभन देकर मतदाताओं को अपने पाले में लाने के प्रयास में जुटे हैं।

एक संकल्प लाखों संकल्पों का उजाला बांट सकता है यदि दृढ़-संकल्प लेने का साहसिक प्रयत्न कोई शुरू करे। अंधेरों, अवरोधों एवं अक्षमताओं से संघर्ष करने की एक सार्थक मुहिम हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 में शुरू हुई थी। उनके तीसरे प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सुखद एवं उपलब्धिभरी प्रतिध्वनियां सुनाई दे रही है, कुछ समय पूर्व हमने मयार्दा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम के मन्दिर के शिलान्यास का दृश्य देखा। काशी में विश्वनाथ धाम का जो विकास हुआ है, उसे देखा। इनदिनों प्रयागराज में महाकुंभ का दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक अनुष्ठान होते हुए हम देख रहे हैं। मोदी ने अपने अब तक के कार्यकाल में जता दिया है कि राजनीतिक इच्छाशक्ति वाली सरकार अपने फैसलों से कैसे देश की दशा-दिशा बदल सकती है। कैसे देश को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर किया जा सकता है। कैसे राष्ट्र की सीमाओं को सुरक्षित रखते हुए पडौसी देशों को चेता सकती है, कैसे दुनिया की महाशक्तियों के बीच भी अडिग खड़ी रह सकती है? कैसे स्व-संस्कृति एवं मूल्यों को बल दिया जा सकता है। गणतंत्र दिवस समारोह मनाते हुए भारत में धर्मस्थलों और तीर्थों के विकास की किसी भी पहल की भी प्रशंसा होनी ही चाहिए। महाकुंभ की एक चमत्कारपूर्ण एवं विलक्षण आभा सामने आयी है, जो हमे गर्वित कर रही है।

भारत के गणतंत्र में और भी चार-चांद लग रहे हैं, जैसे प्रयागराज हो, काशी हो या अयोध्या या ऐसे ही धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्रांति के परिदृश्य- ये अजूबे एवं चौंकाने वाले लगते हैं। इन परिदृश्यों को केवल चुनावी नफा-नुकसान के नजरिये से नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक सशक्त होते राष्ट्र के नजरिये से देखा जाना चाहिए।

सदियों की गुलामी के चलते भारत को जिस हीनभावना से भर दिया गया था, आज का भारत उससे बाहर निकल रहा है। यह स्थिति इस वर्ष का गणतंत्र दिवस समारोह मनाते हुए विशेष रूप से गौरवान्वित करेंगी। वाकई यहां अब कोई संदेह शेष नहीं है कि मोदी सरकार देश व समाज को बदल रही है, लोगों का जीवनस्तर उन्नत कर रही है।

धार्मिक स्थलों को भव्य रूप ही नहीं दिया जा रहा है बल्कि उनसे देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, सीमाओं की सुरक्षा भी बेखूबी हो रही है, समुंदर में हजारों किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर भी बिछाया जा रहा है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज भी बनाये जा रहे हैं, उन्नत सड़कों का जाल बिछ रहा है, गरीबों को पक्के मकान भी बनाकर दिये जा रहे हैं, रोजगार, पर्यावरण-सुरक्षा, चिकित्सा, शिक्षा की अनूठी व्यवस्थाएं भी हो रही है। मतलब वर्तमान शासन-नायकों को विरासत और विकास की समन्वित चिंता है। हिंदुत्व की चिंता है, तो विकास की भी पूरी फिक्र है। अब सुधार, सुशासन, स्व-संस्कृति, स्व-पहचान के दीपक जल उठे हैं, तो उसकी रोशनी तमाम देशवासियों को नया विश्वास, नया आश्वास, नया विकास एवं सुखद जीवनशैली दे रही है।

भारत के संवैधानिक एवं संप्रभुता सम्पन्न राष्ट्र बनने की 76वीं वर्षगांठ मनाते हुए हम अब वास्तविक भारतीयता का स्वाद चखने लगे हैं, आतंकवाद, नक्सलवाद, जातिवाद, क्षेत्रीयवाद, अलगाववाद की कालिमा धूल रही है, धर्म, भाषा, वर्ग, वर्ण और दलीय स्वार्थों के राजनीतिक विवादों पर भी नियंत्रण हो रहा है। इन नवनिर्माण के पदचिन्हों को स्थापित करते हुए हम प्रधानमंत्री के मुख से नये भारत-सशक्त भारत-विकसित भारत को आकार लेने के संकल्पों की बात सुनते हैं।

गणतंत्र दिवस का उत्सव मनाते हुए यही कामना है कि पुरुषार्थ के हाथों भाग्य बदलने का गहरा आत्मविश्वास सुरक्षा पाये। एक के लिए सब, सबके लिए एक की विकास गंगा प्रवहमान हो।

जनतंत्र जनसेवा की आदर्श व्यवस्था है

वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था के संदर्भ में अमेरिकन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को उद्धृत करते हुए कहा जाता है कि ह्यजनतंत्र जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता का शासन है। सिद्धान्ततः यह कथन आंशिक रुप से सत्य भी है क्योंकि इसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जनता के लिए कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित करते हैं। इस दृष्टि से समस्त शासन व्यवस्थाओं में यह व्यवस्था सर्वोत्तम भी है और इसीलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमने इस व्यवस्था को चुना, किन्तु आज हमारे लोकतन्त्र में बढ़ती अविवेकपूर्ण एवं अनुत्तरदायित्व भरी कार्यशैली, जनमन में बढ़ता असंतोष जनित आक्रोश और यत्र-तत्र घटित अराजकतायुक्त दुर्घटनाएं विश्व के इस विशालतम लोकतन्त्र के समक्ष अनेक यक्षप्रश्न उपस्थित कर रही हैं। भारतीय गणतंत्र की इस 76 वें वर्षगाँठ पर इस संदर्भ में गंभीर और विस्तृत विमर्श अपेक्षित है।

सैद्धान्तिक रुप से जनतन्त्र में व्याख्यायित ह्यजनता एक इकाई है। जनतन्त्र की उपर्युक्त लिंकन कृत परिभाषा से ध्वनित होता है कि एक इकाई के रुप में संगठित जनता सम्पूर्ण समाज में से सर्वसम्मति से सुयोग्य नेतृत्व का चयन कर जनकल्याण का पथ प्रशस्त करती है, किन्तु व्यावहारिक रुप से जनतन्त्र में प्रयुक्त जनता एक इकाई नहीं होती। वह अनेक विचारधाराओं, दलों और धर्म-क्षेत्र-जाति-भाषा- व्यवसाय आदि की संकीर्णताओं में बँधे छोटे-छोटे समूहों का समुच्चय होती है, जो मनुष्यता और राष्ट्रीयता की उदार एवं समावेशी हितग्राहिता को हाशिए पर डालकर सत्ता हथियाने की दलीय प्रतिबद्धता के प्रति दुराग्रह प्रकट करती है।

निजी निहित स्वार्थों के लिए सचेष्ट ये संकीर्ण समूह परस्पर कीचड़ उछालते हुए सत्ता के गलियारों में आधिपत्य के लिए निरन्तर संघर्ष करते हैं। इसलिए जनतंत्र में शासन ह्यजनता द्वारा जनता के लिए न रहकर ह्यदल द्वारा दल के लिए हो जाता है और इसी कारण जनता में असन्तोष और आक्रोश जन्म लेता है। जनतंत्र की उदार दृष्टि दलीय महत्त्वाकांक्षाओं की दलदल में धँसकर जनकल्याण से दूर चली जाती है। सत्ताधारी दल जनकल्याण के नाम पर प्रचारित योजनाओं के माध्यम से अपनी भावी चुनावी विजय की रूपरेखा रचता है; वोट-बैंक तैयार करता है और राष्ट्रीय-हितों के नाम पर दलीय-हितों के साधन में अपनी ऊर्जा नियोजित करता है। विपक्षीदल भी उचित-अनुचित का विचार किए बिना सत्ता हथियाने के लिए हर संभव कूट रचना रचते रहते हैं। भारतीय जनतंत्र की लगभग सात दशक लम्बी यात्रा इस बिडम्बना की साक्षी है। गत शताब्दी के आठवें दशक में घटित जनता पार्टी का उद्भव और पराभव इस तथ्य का ज्वलन्त

प्रमाण है।

मनुष्य की प्रकृति सामन्तवादी है। वह शासन करना चाहता है। औरों को अपने अधीन अपने नियन्त्रण में रखना चाहता है। परिवार का मुखिया, संस्था का प्रमुख, संगठन का नेता- सब वर्चस्व चाहते हैं और इस वर्चस्व कामना में निहित ह्यराजस भाव स्वयं के लिए एवं अपने जाति-वर्ग के लिए सुख-सुविधाएँ जुटाने का उद्यम करता है। राजतंत्र में राजा लोग अपने लिए, अपने राजपरिवार के लिए, अपने पक्ष के सामन्तों-सरदारों आदि के लिए सुख-सुविधाएं जुटाते थे और जनता के हितों की उपेक्षा करते थे, वर्तमान जनतंत्र में भी यही दुष्प्रवृत्ति दूर-दूर तक दिखाई देती है। भाई-भतीजावाद, वंशवाद, वोट बैंक सुदृढ़ करने की मानसिकता, जनता की गाढ़ी कमाई पर ऐश करने की ऐसी ही दुरभिलाषाओं के कारण आज हमारा जनतंत्र अपना वास्तविक अर्थ खोकर असंतोष और अराजकता की ओर अग्रसर हो रहा है।

संज्ञा बदल जाने से स्वभाव नहीं बदल जाता। इसी प्रकार सामन्ती मानसिकता भी जनतांत्रिक संज्ञा धारण करने से नहीं बदल सकती। अभावों और संकटों से जूझते ऋणग्रस्त देश के जनतांत्रिक ध्वजवाहक के वस्त्रों का पेरिस से धुलकर आना हमारी सामन्ती मानसिकता को मौन समर्थन देने की चूक थी। यदि अपने जनतांत्रिक नेतृत्व की इस सामन्ती प्रवृत्ति को हमने समय रहते समझ लिया होता तो हमारा जनतंत्र भ्रष्टाचार का शिकार न बनता। उसका स्वरूप अधिक लोकमंगलकारी होता। उसकी छवि अधिक उज्ज्वल होती। जनता सदा नेता का, प्रजा सदा राजा का अनुसरण करती है। रावण के राजा रहते राम से युद्धरत रहने वाले लंकावासी विभीषण के राजा बनते ही राम के शरणागत हो जाते हैं।

महात्मा गाँधी जब अपने दीवान परिवार की ऐश्वर्य और वैभवपूर्ण सुख-सुविधाओं को त्यागकर देश सेवा के लिए लंगोटी धारणकर आजादी की लड़ाई में उतरते हैं तो लाखों-करोड़ों भारतीय अपनी व्यक्तिगत सुविधाओं और पारिवारिक उत्तरदायित्वों की परवाह किए बिना उनके पीछे चलकर देशहित में हर संभव त्याग करते हैं किन्तु जब स्वतंत्र भारत का शीर्ष नेतृत्व विलासितापूर्ण जीवनशैली अपनाता है तो धीरे-धीरे हमारे नेता भी बड़ी संख्या में विलासी जीवन जीने के अभ्यस्त हो जाते हैं जिसकी परिणिति व्यापक भ्रष्टाचार के रूप में सामने आती है। सत्ता सेवा का नहीं व्यक्तिगत सुविधाएं संचित करने का साधन बनकर बोफोर्स, हवाला, चारा, व्यापम आदि असंख्य घोटालों का शिकार हो जाती है।

जनतंत्र जनसेवा की आदर्श व्यवस्था है। उसके सम्यक संचालन के लिए अनुभवी, ईमानदार और ऐसे न्यायप्रिय निर्भीक नेतृत्व की आवश्यकता है जो समस्त संकीर्णताओं और दलीयस्वार्थों से ऊपर उठकर सम्पूर्ण समाज के लिए उचित निर्णय ले और जिसे सब स्वीकार करें, किन्तु विडम्बना यह है कि वर्तमान जनतांत्रिक व्यवस्था का आधार दलगत राजनीति है और दलगत राजनीति की कोख से जनमे नेतृत्व का सर्वस्वीकृत होना प्रायः असंभव है।

तथापि अब यह नितान्त आवश्यक है कि हम वोट-बैंक और दलीय-स्वार्थों की ओछी कूटनीतियाँ छोड़कर ह्यसर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सच्ची राजनीति के प्रति प्रतिबद्ध हों अन्यथा ह्यसर्वोदय, ह्यअन्त्योदय और ह्यसबका साथ, सबका विकास जैसे नारे सार्थक न हो सकेंगे और भारतीय समाज में बढ़ती विषमताएं, विसंगतियाँ असंतोष और आक्रोश को उग्रकर लोकतन्त्र का मार्ग कंटकाकीर्ण कर देंगीं। समय रहते हमें और हमारे नेतृत्व को यह कटु यथार्थ समझ लेना चाहिए कि नेतृत्व की शुचिता पर ही जनतंत्र का निर्वाह संभव है।

दिल्ली विधानसभा चुनाव में गंदी यमुना बनी अहम मुद्दा, विपक्षी दलों ने 'आप' पर साधा निशाना

देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है। इसके साथ ही राज्य में चुनाव की गर्माहट देखने को मिल रही है। सभी राजनीतिक दल जनता को अपने वादों से लुभाने की कोशिश कर चुकी हैं। इसके अलावा राजनीतिक

दल सत्तारूढ़ सरकार को प्रदूषित यमुना नदी के मुद्दे पर घेर रही है। बता दें दिल्ली में इन दिनों प्रदूषित यमुना नदी केंद्रीय मुद्दा बन चुका है।

ऐसे में सवाल यह है कि क्या दिल्ली का बढ़ता प्रदूषण और यमुना की गंदगी के आधार पर जनता वोट देगी या फिर यह मुद्दे जनता के लिए मायने नहीं रखते हैं। प्रदूषित यमुना नदी का मुद्दा दरअसल, भारतीय जनता पार्टी यमुना सफाई का मुद्दा जोर-शोर से उठा रही है। इसके साथ ही दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी जमकर निशाना साधा जा रहा है। वहीं दिल्ली की जनता का कहना है कि यमुना नदी पूरी तरह से प्रदूषित हो चुकी है। सिर्फ चुनावी मौके पर या फिर छठ पूजा के मौके पर तमाम राजनीतिक दलों को यमुना नदी की याद आती है। जबकि लोगों की पानी की आपूर्ति पूरी करने में यमुना नदी अहम भूमिका निभा सकती है। लेकिन वर्तमान समय में यमुना नदी इतनी ज्यादा दूषित है कि उसके पानी में हाथ भी नहीं डाला जा सकता है।

दिल्लीवासियों का कहना है कि चाहे आप पार्टी हो या भाजपा या फिर कांग्रेस पार्टी हो। सभी दलों ने यमुना साफ करने का वादा किया था। दिल्लीवासियों को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त दिल्ली देने का वादा किया था। लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने ऐसा नहीं किया है।

ऐसे में इस बार जनता बहुत सोच-समझकर वोट करेगी। लोगों का मानना है कि अब फ्री की रेवड़ी नहीं चलेगी। दिल्ली की जनता जागरुक हो चुकी है और जनता यह भी देख रही है कि दिन-प्रतिदिन दिल्ली रहने के लायक नहीं बची है।

इसलिए अगर दिल्ली में रहकर खुलकर सांस लेना है, तो दिल्ली की जनता को एक अच्छी सरकार चुनना होगा।

यमुना की सफाई बनी राजनीतिक मुद्दा दिल्लीवासियों के लिए यमुना नदी का प्रदूषण एक गंभीर चिंता का विषय है। ऐसे में चुनाव प्रचार के दौरान यमुना नदी का मुद्दा राजनीतिक दलों का सत्तारूढ़ पार्टी पर हमला करने का हथियार बन गई है। सत्तारूढ़ आप पार्टी अपने वादे अनुसार, कई सालों से प्रदूषित नदी को 2025 तक साफ करने में विफल रही है। ऐसे में विपक्षी दल इस मुद्दे को जोर-शोर से उठा रही है और इस प्रदूषित पानी से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं को गिना रहे हैं।

दिल्ली में मुफ्त चुनावी उपहारों के शोर में असल मुद्दे दब कर रह गये हैं

अक्सर आपने देखा होगा कि किसी राज्य में विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक और सामाजिक समीकरण हावी हो जाते हैं लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में हालात एकदम अलग हैं।

विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में राजनीतिक चर्चा में मुफ्त उपहारों की चर्चा हावी है जिससे प्रदूषण, कानून व्यवस्था, महिलाओं के खिलाफ अपराध और बुनियादी ढांचा सहित अन्य प्रमुख मुद्दे पीछे रह गए हैं।

आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में सत्तारुढ़ आम आदमी पार्टी मुफ्त बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और महिलाओं के लिए निःशुल्क सार्वजनिक परिवहन पहल पर जोर देते हुए रेवड़ी पर चर्चा जैसे अभियानों का नेतृत्व कर रही है। इसने नयी योजनाओं की भी घोषणा की है, जिनमें महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये देने के वादे के साथ मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना और बुजुर्गों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल संबंधी संजीवनी योजना शामिल है।

कांग्रेस ने जवाब में प्यारी दीदी योजना की घोषणा की है जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये देने की बात कही गई है। इसने 25 लाख रुपये तक की बीमा कवरेज का वादा करते हुए जीवन रक्षा योजना की घोषणा भी की है। वहीं भाजपा ने भी अपने संकल्प पत्र के दो चरण अब तक जारी किये हैं जिनमें हर वर्ग के लिए योजनाओं की भरमार है। देखा जाये तो इन मुफ्त योजनाओं को एक बार मुफ्त की रेवड़ी करार देने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भी दिल्ली के लोगों को आश्वस्त करना पड़ा है कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो इस तरह की योजनाएं जारी रखी जाएंगी।

इस बीच, मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त उपहारों की घोषणाओं के चलते दिल्ली में वायु प्रदूषण जैसा महत्वपूर्ण मुद्दा गौण हो गया है। हालांकि राजधानी के ज्यादातर निवासियों ने गंभीर स्वास्थ्य खतरा बने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ठोस कार्य योजनाओं की कमी पर चिंता

जताई है। हम आपको बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) पिछले साल नवंबर में 490 के अंक को पार कर गया, जो अत्यंत गंभीर श्रेणी में आता है। जहरीली हवा के कारण अनेक लोगों को विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा, यमुना नदी में अमोनिया के उच्च स्तर के कारण पूरे शहर में पानी की कमी भी देखी गई क्योंकि जलशोधन संयंत्र पानी का शोधन करने में असमर्थ थे। यही नहीं, खराब जल निकासी के चलते दिल्ली के राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग सेंटर में तीन यूपीएससी अभ्यर्थियों की डूबने से मौत को लेकर राष्ट्रीय राजधानी में आक्रोश देखा गया था।

बहरहाल, देखा जाये तो मुफ्तखोरी की संस्कृति को बढ़ावा देने की वजह से शासन एवं नीति-निर्माण पंगु हो गये हैं। अपने अब तक के कार्यकाल में आम आदमी पार्टी की सरकार ने रोजगार सृजन और संविदा कर्मचारियों के लिए समाधान खोजने जैसे अन्य प्रमुख मुद्दों की अनदेखी की है।

आम आदमी पार्टी ने मुफ्त योजनाओं की जो आदत जनता को लगाई है उसको देखते हुए अन्य पार्टियां भी इसी नीति पर चलती नजर आ रही हैं। यह नीति राजनीतिक दलों को सत्ता तो दिला देगी लेकिन सरकारी खजाने को और राज्य की आर्थिक सेहत को खासा नुकसान पहुँचाएगी। यहां सवाल यह भी उठता है कि हम 2047 तक भारत को विकसित बनाने की बात कर रहे हैं लेकिन जब देश की राजधानी ही विकसित नहीं होगी तो यह लक्ष्य आखिर कैसे हासिल होगा?

संक्षिप्त समाचार

डब्ल्यूईएफ का मकसद सिर्फ समझौते करना नहीं, संपर्क बढ़ाना भी है: चंद्रबाबू नायडू

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने शनिवार को कहा कि स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की यात्रा का उद्देश्य सिर्फ समझौतों पर हस्ताक्षर करना नहीं है, बल्कि प्रभावशाली लोगों के साथ संपर्क बढ़ाना भी है। दावोस की अपनी हालिया यात्रा पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी सहित कुछ वर्गों की

आलोचना को दरकिनार कर दिया। आलोचकों का आरोप है कि नायडू के नेतृत्व में उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल खाली हाथ लौट आया और उसने केवल नायडू के आत्म-प्रचार पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि अन्य राज्य सौदे करने में कामयाब रहे। नायडू ने कहा, ह्लदावोस नेटवर्किंग के लिए एक जगह है। पूरी दुनिया चार दिन के लिए वहां जाती है। राष्ट्राध्यक्ष और मंत्री वहां जाते हैं। न केवल सरकारें, बल्कि सभी निगम वहां होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि दावोस के बारे में एक मिथक है कि लोग वहां केवल समझौता ज्ञापनों (एमओयू) की संख्या और निवेश की राशि पर विचार करते हैं। नायडू के अनुसार, दावोस में आयोजित डब्ल्यूईएफ ज्ञान संवर्धन और नवीनतम रुझानों को सीखने के लिए सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्कों को एक साथ लाता है। तेलगू देशम पार्टी (तेदेपा) प्रमुख ने कहा कि उन्होंने शिखर सम्मेलन के दौरान माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स सहित कई प्रमुख लोगों से बात की। यहां केवल तीन दिन में एक ही छत के नीचे विश्वस्तर पर प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ बातचीत की जा सकती है।

संकल्प को सिद्धी तक लेकर जाएंगे, बहुत खुशी की बात, बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर क्या बोलीं दिल्ली की सांसद

दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज होने के बीच भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने बीजेपी का संकल्प पत्र पार्ट 3 जारी किया। जिसमें यमुना को साफ करने, 1,700 अनधिकृत कॉलोनियों में पूर्ण मालिकाना हक

प्रदान करने और गिग श्रमिकों तथा मजदूरों के लिए कल्याणकारी उपाय करने का शनिवार को वादा किया। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार अपने संकल्प पत्र के एक-एक संकल्प को सिद्धी तक लेकर जाएगी। हमारे संकल्प पत्र में बहुत दूरगामी और दृष्टि वाले संकल्पों को लिया गया है। महिलाओं को मात्र 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा और सालाना 2 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। महिलाओं को 2500 रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। भाजपा सांसद कमलजीत सेहरावत ने कहा कि आज दिल्ली वालों के लिए बहुत खुशी की बात है क्योंकि दिल्ली का अनाधिकृत हिस्सा बहुत है और लोग यहां अपनी मेहनत का पैसा लगाते हैं। सरकार की लापरवाही की वजह से ये अनाधिकृत कहलाता है। आज गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को भवन निर्माण उपनियम लागू करके अपना घर बनाने का अधिकार होगा। इन लोगों को मकान बनाते वक्त किसी चीज की टेंशन नहीं होगी। अब ये लोग अपना मकान बेच भी पाएंगे।भाजपा के घोषणापत्र में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड योजना के तहत जरूरतमंद छात्रों को दिल्ली मेट्रो में सालाना 4,000 रुपये तक की मुफ्त यात्रा का भी वादा किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने पांच फरवरी को होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के संकल्प पत्र का तीसरा और अंतिम भाग जारी करते हुए कहा कि पार्टी के सत्ता में आने पर 1,700 अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को संपत्तियों का पूर्ण मालिकाना हक मिलेगा, जिससे बिक्री, खरीद और निर्माण का रास्ता साफ हो जाएगा। उन्होंने यह भी दोहराया कि भाजपा दिल्ली में गरीबों के लिए चल रहे किसी भी कल्याणकारी उपाय को नहीं रोकेगी।

बजट सत्र 31 जनवरी से 4 अप्रैल तक चलेगा, निर्मला सीतारमण इस दिन पेश करेंगी बजट

देश की संसद में कुछ ही दिनों में बजट सत्र की शुरूआत होने वाली है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होने वाला है। इसका समापन 4 अप्रैल को होगा। इस बजट सत्र में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। इस वर्ष बजट सत्र 31 जनवरी से 4 अप्रैल तक चलने वाला है। इस बजट सत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। ये बजट सत्र काफी खास होने वाला है जिसमें निर्मला सीतारमण अपना आठवां बजट पेश करेंगी।

इस वर्ष बजट सत्र की शुरूआत 31 जनवरी को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक से होगी। इस बजट सत्र की शुरूआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से होगी, जिसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा।

बजट सत्र के पहले भाग में 31 जनवरी से 13 फरवरी तक नौ बैठकें होंगी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे। बजट सत्र और सीतारमण बजट पर चर्चा का जवाब देंगी। इसके बाद संसद बजट प्रस्तावों की जांच के लिए अवकाश ले लेगी और विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर चर्चा करने तथा बजटीय प्रक्रिया पूरी करने के लिए 10 मार्च से पुनः बैठक करेगी। सत्र के पहले भाग में नौ बैठकें होंगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे तथा सीतारमण बजट पर चर्चा का जवाब देंगी। इसके बाद संसद बजट प्रस्तावों की जांच के लिए अवकाश ले लेगी और 10 मार्च से पुनः बैठक करेगी। सत्र 4 अप्रैल को समाप्त होगा। पूरे बजट सत्र में 27 बैठकें होंगी।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, माननीय राष्ट्रपति 31 जनवरी 2025 को सुबह 11 बजे लोकसभा कक्ष में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। केंद्रीय बजट 2025-26 1 फरवरी, 2025 को लोकसभा में पेश किया जाएगा।

अपराध आदत और भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया, मोकामा को लेकर तेजस्वी का नीतीश पर वार, JDU का पलटावर

बिहार में एक हालिया घटनाक्रम में, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने पूर्व विधायक अनंत सिंह से जुड़े मोकामा गोलीबारी की घटना से निपटने के लिए मुख्यमंत्री की तीखी आलोचना की है।

यादव ने एएनआई से बात करते हुए राज्य सरकार पर बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार के प्रति उदासीन होने का आरोप लगाया। नीतीश कुमार पर वार करते हुए तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री बेपरवाह हो गये हैं। अब 'अपराध' 'आदत' और 'भ्रष्टाचार' 'शिष्टाचार' बन गया है।

राजद नेता ने कहा कि वर्तमान सरकार के तहत, आत्मा को कुचलने वाली चीजें आदर्श बन गई हैं। इस घटना पर सीएम चुप हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के अपराधी खुले तौर पर स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने गोलीबारी की। लेकिन अब तक किसी को नामजद करते हुए प्राथमिकी दर्ज नहीं करायी गयी है। इसलिए, सरकार उन्हें बचा रही है।' केंद्रीय मंत्री ने दोनों से मुलाकात की। तो फिर पुलिस को किसी के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत कैसे होगी?

तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि इससे कुछ भी नहीं निकलने वाला है। ये सभी सरकार के संरक्षण में हैं। सरकार सुर्खियां बटोरने की कोशिश करती है, इसलिए यह मामला भी कुछ दिनों में गायब हो जाएगा। यह सामान्य हो जाएगा। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार में बैठे लोग उनकी रक्षा करेंगे और पुलिस के पास कोई शक्ति नहीं है।

वहीं, तेजस्वी के आरोपों पर जदयू ने पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन (ललन) सिंह ने कहा कि बिहार में कुछ नहीं हो रहा है। बिहार में कानून अपना काम कर रहा है। अगर कुछ भी होता है तो कानून अपना काम करता है और पुलिस अपना काम करती है। जब बिहार में तेजस्वी के माता-पिता का शासन था, तब 'जंगल राज' था। बिहार की जनता उन पर दोबारा भरोसा करने वाली नहीं है।

सही समय पर करेंगे फैसला, दिखा देंगे घायल शेर क्या कर सकता है, निकाय चुनाव को लेकर बोले उद्धव

शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को संकेत दिया कि उनकी पार्टी राज्य में आगामी स्थानीय निकाय चुनाव अपने दम पर लड़ सकती है, उन्होंने कहा कि उनके कार्यकर्ता इसके लिए उत्सुक हैं और वह उचित समय पर इस पर निर्णय लेंगे। पिछले साल के विधानसभा चुनावों में हार पर महा विकास अघाड़ी (एमवीए) की आलोचना करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि किसी को भी उनकी पार्टी के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और भाजपा को कम से कम एक चुनाव मतपत्र से कराने की चुनौती दी। शिव सेना के संस्थापक बाल ठाकरे की 99वीं जयंती पर पार्टी

कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वह सभी नगर निगमों में पार्टी कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं और वे चाहते हैं कि पार्टी आगामी स्थानीय निकाय चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़े।

उन्होंने कहा कि क्या आप गद्दारों को उनकी जगह दिखाने के लिए तैयार हैं? चुनाव की घोषणा अभी बाकी है। मुझे अपनी तैयारी देखने दीजिए और मैं आपकी इच्छा के अनुसार निर्णय लूंगा। मैं उचित समय पर निर्णय लूंगा। मैंने यह देखने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया कि कितने लोग मेरे साथ हैं।

जब तक आप शिवसैनिक हैं, मैं आपकी पार्टी का अध्यक्ष रहूंगा। हम गद्दारों को सबक सिखाएंगे। जब कोई आकर मुझसे कहेगा कि मैंने विचारधारा छोड़ दी है। बालासाहेब ठाकरे की, मैं अलग हट जाऊंगा। शिवसेना (यूबीटी) कांग्रेस और एनसीपी (एसपी) के साथ विपक्षी एमवीए का घटक है।

ठाकरे का यह बयान पार्टी नेता संजय राउत की घोषणा के कुछ दिनों बाद आया है कि उनकी पार्टी स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़ेगी, जिससे विपक्षी गुट की एकता पर सवालिया निशान लग गया है। स्थानीय निकाय चुनाव इस साल की शुरूआत में होने वाले हैं।

श्वेत क्रांति 2.0: मोटरसाइकिल पर दूध बेचती नजर आई लड़की, क्यों चर्चा में है पशुपालन विभाग की झांकी?

भारत ने 26 जनवरी को अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जो 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को अपनाने की याद दिलाता है। हालांकि भारत को 1947 में औपनिवेशिक शासन से आजादी मिली, लेकिन भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज कर्तव्य पथ से 76वें गणतंत्र दिवस का जश्न मनाते देश का नेतृत्व किया। इस वर्ष के समारोह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता, एकता, समानता, विकास और सैन्य कौशल का एक अनूठा मिश्रण नजर आया।

इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबिआंतो मुख्य अतिथि थे। राष्ट्रीय महत्व के आयोजनों में 'जनभागीदारी' बढ़ाने के सरकार के उद्देश्य के अनुरूप, परेड देखने के लिए लगभग 10,000 विशेष मेहमानों को आमंत्रित किया गया था। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में पशुपालन विभाग की झांकी में भारत की स्वदेशी गायों पर प्रकाश डाला गया। इसने भारतीय संस्कृति और परंपरा में उनकी स्थायी

विरासत का जश्न मनाते हुए, कृषि, आजीविका और पर्यावरण में उनके योगदान पर जोर देते हुए सतत ग्रामीण विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को प्रदर्शित किया।

इस दौरान कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस के परेड में पशुपालन विभाग की झांकी ने भी सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। इस झांकी की सबसे खास झलक मोटरसाइकिल पर दूध बेचती लड़की रही, जो यह दशार्ती है कि खेती-किसानी और पशुपालन अब सिर्फ पुरुषों का काम नहीं रहा। झांकी में एक महिला किसान को भैंस की देखभाल करते हुए दिखाया गया। इस दौरान एक पशु चिकित्सक टीके की एक खुराक तैयार कर रहा था, जो विभाग के प्रमुख सार्वभौमिक खुरपका और मुंहपका रोग टीकाकरण कार्यक्रम को रेखांकित करने के लिए था।

दो महिलाओं को पारंपरिक ह्यबिलोनाह्न विधि से घी निकालते दिखाया गया और साथ ही घी की एक बोतल दिखाई गई। झांकी के पिछले हिस्से में कामधेनु/सुरभि की एक मूर्ति प्रदर्शित की गई। कामधेनु को एक पवित्र गाय माना जाता है जो इच्छाओं को पूरा कर सकती है और समृद्धि का भी प्रतिनिधित्व करती है। साइकिल और बायो-सीएनजी मोटरसाइकिल पर झांकी के साथ आने वाले सवारों ने भारत के हर कोने से दूध को सहकारी संग्रह केंद्रों या उपभोक्ताओं तक पहुंचाने वाले पुरुषों और महिलाओं के परिश्रम को दर्शाया।

भारत के प्रमुख निवेश समझौते और डब्लूईएफ 2025 दावोस में विकास

मुकेश टम्टा

भारत ने 20 से 24 जनवरी, 2025 तक स्विट्जरलैंड के दावोस-क्लोस्टर्स में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 55वीं वार्षिक बैठक में निवेश के अवसरों और रणनीतिक सहयोग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण छलांग देखी। इस उच्च-स्तरीय आयोजन में प्रमुख व्यावसायिक नेताओं और नीति निमार्ताओं ने भाग लिया।

इस वर्ष की थीम ₹बौद्धिक युग के लिए सहयोग₹है, जो हमारे वैश्विक भविष्य को आकार देने वाली पाँच महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं पर केंद्रित है- विश्वास का पुनर्निर्माण, विकास की पुनर्कल्पना, लोगों में निवेश,ग्रह की सुरक्षा, बौद्धिक युग में उद्योग बैठक में कई विशिष्ट व्यक्तियों ने भाग लिया, जिनमें सुनील कुमार गुप्ता, एसएआरसी एसोसिएट्स और इंडो यूरोपियन बिजनेस फोरम के संस्थापक, और उनका प्रतिनिधिमंडल शामिल था। प्रतिनिधिमंडल में राजेंद्र बगड़े, निदेशक, इंडिया ग्लोबल चैंबर ऑफ बिजनेस, चंद्र शेखर अकुला, एसएआरसी एसोसिएट्स के संस्थापक साझेदार,श्री प्रोबीर रॉय, पेमेट के सह-संस्थापक और नजारा टेक और अलीज कैपिटल के संस्थापक स्वतंत्र निदेशक और श्री आशुतोष वर्मा, संस्थापक और सीईओ, एएनवीआई, शामिल थे। अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्री, देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उदय सामंत, महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री अश्विनी भिड़े, मेट्रो की सीईओ मनोज सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव शारदा मुरलीधरन, केरल की मुख्य सचिव ने चर्चा में भाग लिया। इन चचाओं का उद्देश्य रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना और निवेश के नए अवसर तलाशना था। इंडो यूरोपियन बिजनेस फोरम के संस्थापक सुनील कुमार गुप्ता ने ई-स्पोर्ट्स, गेमिंग, संगीत, इवेंट्स जैसी उभरती हुई उद्योगों (सनराइज इंडस्ट्रीज) को तुरंत मान्यता देने और इनसे संबंधित वैश्विक स्तर का बुनियादी ढांचा विकसित करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने इसे भारतीय युवा बाजार के केंद्र (हब) के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य आने वाले वर्षों में अपनी जीडीपी को दोगुना करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं।इस अतिरिक्त वृद्धि का 20प्रतिशत डिजिटल अर्थव्यवस्था से आएगा। इस एजेंडा का मुख्य उद्देश्य भारत के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश और व्यावसायिक अवसरों की खोज करना था। कार्यक्रम की एक प्रमुख विशेषता ₹मेक इन इंडिया (तीसरा संस्करण)₹ पुस्तक का विमोचन था, जिसे सुनील कुमार गुप्ता ने लिखा है। प्रोबीर रॉय (पेमेट - एक पब्लिक लिमिटेड फिनटेक कंपनी, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करती है, के सह-संस्थापक और नजारा टेक्नोलॉजीज - एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध यूनिकॉर्न कंपनी, जहां वे ऑडिट कमेटी के अध्यक्ष हैं, के स्वतंत्र निदेशक) ने कहा।

उन्हें 2022 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स, वेस्टमिंस्टर, लंदन में आईबीपीएफ डिजिटल बिजनेस लीडर का पुरस्कार दिया गया था। जब भारत आने वाले वर्षों में अपनी जीडीपी को दोगुना करेगा, तो मुझे उम्मीद है कि इस अतिरिक्त जीडीपी वृद्धि का पांचवां हिस्सा गेमिंग, ई-स्पोर्ट्स और पेमेंट्स जैसे क्षेत्रों से आएगा, जो उपभोग और बी2बी (बिजनेस टू बिजनेस) केंद्रित हैं। मैं इसे 'एफएमबी' (फास्ट मूविंग टेक ड्रिवन बिजनेस) कहता हूं। ये पहल भारत की एक मजबूत निवेश माहौल को बढ़ावा देने और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं।

रणनीतिक साझेदारियों और नवीन उपक्रमों के साथ, देश खुद को एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित करना जारी रखता है। श्री राजेंद्र बगड़े, निदेशक, इंडिया ग्लोबल चैंबर ऑफ बिजनेस, ने कहा कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों को नई बाजारों के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभानी होगी, जो तेजी से बढ़ती मिलेनियल पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करें। ये बाजार जीवनशैली, मनोरंजन और माइक्रोपेमेंट्स की प्रवृत्तियों के संगम पर स्थित हैं। आशुतोष वर्मा, संस्थापक और सीईओ, एएनवीआई ने कहा, दावोस में एआई हाउस में विभिन्न वैश्विक भागीदारों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रतिभागियों के साथ मेरी बातचीत विशेष रूप से एएनवीआई के 'पर्सन-लेस बैंक' की दृष्टि को स्पष्ट करने में मूल्यवान रही। इसका उद्देश्य अपने ग्राहकों को सस्ती क्रेडिट प्रदान करना है, जिन्हें वर्तमान में अनौपचारिक साहूकार ऊंची ब्याज दरों पर सेवा प्रदान कर रहे हैं। एआई का उपयोग करके, एएनवीआई 1.3 ट्रिलियन डॉलर के बाजार को बाधित करने का लक्ष्य रखता है, जो फिलहाल अनौपचारिक साहूकारों के नियंत्रण में है, और एक बिलियन से अधिक भारतीयों को वित्तीय समावेशन प्रदान करने का प्रयास कर रहा है। सुनील कुमार गुप्ता के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने दावोस के यूपी पवेलियन में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार के साथ लाभदायक बैठक की।

दावोस यह दिखाता है कि यदि हमें निर्धारित समय सीमा के भीतर 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था प्राप्त करनी है, तो हमें बड़े विचार करने होंगे। बिना किसी बहाने के कार्यान्वयन करना होगा और केवल सतह पर हलचल करने की बजाय वास्तविक बदलाव लाना होगा।₹ चंद्र शेखर अकुला, संस्थापक साझेदार, एसएआरसी एसोसिएट्स महाराष्ट्र सरकार ने पिछले वर्ष के ₹3.5 लाख करोड़ के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए लगभग ₹6.25 लाख करोड़ तक पहुँचने के साथ 31 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जो सभी क्षेत्रों में फैले हुए हैं ! शायद यह सभी राज्यों में सबसे उच्चतम है !

महाराष्ट्र नए युग के व्यवसायों जैसे फिनटेक और गेमिंग हब के रूप में उभर रहा है, जहां कई यूनिकॉर्न कंपनियों का मुख्यालय स्थित है।

इस बैठक में जिन समझोतों पर हस्ताक्षर हुए उनमें निम्न प्रमुख हैं-

महाराष्ट्र: ऐतिहासिक टङ्कव२ पर हस्ताक्षर

1. कल्याणी ग्रुप
- निवेशः ₹5250 करोड़
- रोजगारः 4000 नौकरियां
- क्षेत्रः रक्षा, स्टील, इलेक्ट्रिक वाहन (एस)

2. रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
- निवेशः ₹16,500 करोड़
- रोजगारः 2450 नौकरियां
- क्षेत्रः रक्षा

3. बालासोर अलॉयज लिमिटेड
- निवेशः ₹17,000 करोड़
- रोजगारः 3200 नौकरियां
- क्षेत्रः स्टील और धातु

4. विराज प्रोफाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
- निवेशः ₹12,000 करोड़
- रोजगारः 3500 नौकरियां
- क्षेत्रः स्टील और धातु

1. कोका-कोला साझेदारी
- निवेशः ₹2500 करोड़
- मून बेवरेजेस और एसएलएमजी बेवरेजेस के साथ सहयोग
- उद्देश्यः बॉटलिंग संयंत्र और वितरण नेटवर्क का विस्तार
- प्रमुख प्रतिभागीः मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह, कोका-कोला के ईवीपी श्री हेनरिक ब्राउन, और अन्य

2. एबी इनबेब पर हस्ताक्षर
- निवेशः ₹1000 करोड़
- उद्देश्यः पेय पदार्थ क्षेत्र को मजबूत करना और निवेश के अवसरों को सुनिश्चित करना

तेलंगानाः विकास का केंद्र

1. यूनिलीवर के नए यूनिट्स
- घोषणाः दो निर्माण इकाइयों की स्थापना
- महत्वः तेलंगाना के लिए औद्योगिक विकास का एक नया अध्याय

2. रणनीतिक चर्चा में अमेजन वेब सर्विसेज, स्काईरुट ऐरोस्पेस, अगिलिटी यूपीएल, सायफाई टेक्नोलॉजीज और ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी कम्पनियों ने भागीदारी निभाई।

- क्षेत्रः स्टील और धातु

उत्तर प्रदेशः नए अवसरों की ओर बढ़ते कदम

केजी से पीजी तक फ्री एजुकेशन और मुफ्त इलाज- कब साकार होगा यह सपना ?

भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर 21 जनवरी 2025 को जारी किए गए अपने दूसरे संकल्प पत्र में यह वादा किया है कि दिल्ली की सत्ता में आने पर पार्टी जरूरतमंद छात्रों को केजी से पीजी तक फ्री शिक्षा देगी। इस पर पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि दिल्ली की सत्ता में आने पर भाजपा मुफ्त शिक्षा और मुफ्त इलाज बंद कर देगी।

राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से अलग हटकर देखा जाए तो फ्री एजुकेशन का यह मसला अपने आप में बहुत ही गंभीर मसला है और दुर्भाग्य से इस परिस्थिति के लिए इस देश के सभी राजनीतिक दल जिम्मेदार है। आज कोई भी राष्ट्रीय या बड़ा क्षेत्रीय दल सार्वजनिक शिक्षा और स्वास्थ्य की बदहाली के लिए अपने आपको जिम्मेदार से मुक्त नहीं बता सकता है क्योंकि लगभग सभी राजनीतिक दलों ने कभी न कभी सत्ता का सुख जरूर भोगा है। गठबंधन राजनीति के दौर में, देश की राजनीति में सक्रिय ज्यादातर राजनीतिक दल या तो केंद्र की सत्ता में भागीदार रहे हैं या किसी ना किसी राज्य में सरकार चला चुके हैं या वर्तमान में भी चला रहे हैं।

वास्तविकता तो यह है कि भारत जैसे कल्याणकारी राज्य में मुफ्त शिक्षा और मुफ्त इलाज जैसे बेसिक दायित्वों से लगभग सभी सरकारों ने पल्ला झाड़ लिया है। मुफ्त शिक्षा में कई तरह की शर्तें लगा दी गईं हैं। सरकारी स्कूलों की हालत हर गुजरते दिन के साथ खराब होती जा रही है। देश की राजधानी

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जब साइंस और मैथ्स जैसे विषयों के अध्यापकों की भारी कमी है तो देश के अन्य राज्यों के स्कूलों का अंदाजा आप लगा सकते हैं। देशभर के सरकारी स्कूलों में मिलने वाली ड्रेस की गुणवत्ता और किताबों पर लगातार सवाल उठते रहते हैं। एनसीईआरटी तो समय पर किताब छपवाना ही भूल गई है। मिड डे मील ने तो स्कूलों में पढ़ाई की हालत और ज्यादा खराब कर दी है लेकिन इसके विकल्प की भी कोई तलाश नहीं की जा रही है।

सरकारी अस्पतालों की हालत भी कितनी दयनीय हो चुकी है, यह सब जानते हैं। दिल्ली के एम्स जैसे अस्पताल में भी ऑपरेशन की डेट कई-कई साल बाद मिलने की खबरें लगातार आती हैं। एम्स और सफदरजंग जैसे अस्पतालों के इर्द-गिर्द खुल चुके सैकडों प्राइवेट लैब्स यह बताने के लिए काफी है कि इन दोनों सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की आस में आने वाले लोगों को हजारों रुपए खर्च कर बाहर से ही जांच करवाना पड़ता है। सरकारी अस्पताल में पूरी दवाई मिल जाए, इसकी उम्मीद तो अब लोग वर्षों पहले ही छोड़ चुके हैं लेकिन अब उचित जांच और उचित इलाज की उम्मीद भी दम तोड़ती नजर आ रही है। जब दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की हालत इतनी खराब है तो आप देश के अन्य राज्यों के सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा का अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं।

विडंबना देखिए कि, सरकारों ने इस बारे में अब सोचना तक छोड़ दिया है, कार्रवाई के बारे में तो भूल ही जाइए। आंकड़े बताते हैं कि देश में डॉक्टरों की बड़े पैमाने पर कमी है लेकिन एमबीबीएस जैसे बेसिक डॉक्टरी की पढ़ाई पर भी सरकार का फोकस नहीं है , जिससे इस कमी को दूर किया जा सकता है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पिछले साल 13 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा को क्वॉलिफाई किया था लेकिन देश में एमबीबीएस की सीटें एक लाख 8 हजार के लगभग ही है।

इसमें से भी सरकारी सीटें सिर्फ 56 हजार के लगभग ही है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में एक साल की फीस एक से डेढ़ करोड़ के बीच है यानी एमबीबीएस की चार सालों की पढ़ाई के लिए प्राइवेट कॉलेजों में 4 करोड़ से लेकर 6 करोड़ तक सिर्फ फीस ही देनी होगी। अब इसमें बाकी खर्चों को भी जोड़ लीजिए। सोचिए, इस हालत में भला मिडिल क्लास का कौन सा परिवार अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने के बारे में सोच सकता है ? सरकारों ने लोगों को मुफ्त और उचित इलाज नहीं दे पाने की अपनी नाकामी को छिपाने के लिए बीमा योजनाओं का सहारा लेना शुरू कर दिया है। जिन योजनाओं का फायदा आम लोगों से ज्यादा प्राइवेट अस्पतालों को ही हो रहा है।

फ्री, फ्री और रेवड़ियों के इस दौर में सरकारों ने अपनी प्राथमिक जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया है। यह अपने आप में सबसे बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन कभी न कभी तो इस देश के बड़े तबके खासतौर से लाभार्थी वर्ग के लोगों को आगे बढ़कर सरकारों से और राजनीतिक दलों से यह कहना ही होगा कि, आप हमें बेवकूफ बनाना बंद कीजिए।

सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों की हालत ठीक कीजिए, सरकारी अस्पतालों की हालत ठीक कीजिए, अध्यापकों और डॉक्टरों की कमी को दूर कीजिए, बिना किसी भेदभाव के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और सरकारी अस्पतालों में जाने वाले सभी लोगों के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था को हर कीमत पर और हर हाल में सुनिश्चित कीजिए।

सैफ अली खान पर हमले पर उठते सवाल

राकेश अचल

सैफ अली खान एक अभिनेता हैं इसलिए उनकी हर गतिविधि क्या अभिनय होती है ? ये सवाल हमने-आपने नहीं बल्कि महाराष्ट्र के सियासतदानों ने उठाया है। सैफ पर हमला ही अब सियासी मुद्दा हो गया है। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा कि जानलेवा हमले के बाद सैफ मात्र पांच दिन में तंदुरुस्त होकर अपने घर आ सकते हैं। क्योंकि आम आदमी तो ऐसे में कम से कम एक पखवाड़े तक पलंग नहीं छोड़ सकता। आम आदमी में किसी अभिनेता जितनी कूबत ही नहीं होती।

मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारे मुल्क में सियासत मुद्दों पर नहीं, हर एक बात पर होती है और जब होती है तो होती ही चली जाती है। सियासत का ये चरित्र बदलना आसान नहीं है और इसके लिए किसी एके को जिम्मेदार भी नहीं ठहराया जा सकता।

अभिनेता सैफ अली खान की अस्पताल से छुट्टी के बाद प्रदेश सरकार के एके मंत्री नितेश राणे ने सवाल उठाए हैं। उनका मानना है कि सैफ पर हमला संदिग्ध हो सकता है। राणे ने राजनीतिके नेताओं पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए हिंदू कलाकारों की उपेक्षा की बात कही और बढ़ते बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुद्दे पर चिंता जताई।

सैफ के ऊपर सवाल खड़े करने वाले राणे अकेले नहीं है। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने भी एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। उन्होंने हमले की घटना का जिक्र करते हुए इतनी जल्दी ठीक होने पर कहा कि सैफ को 16 जनवरी की घटना के बारे में बताना चाहिए। निरुपम भले ही दलबदलू हों किन्तु वे अनुभवी नेता हैं इसलिए उन्होंने अपना सवाल बड़ी ही नजाकत के साथ किया है। निरुपम ने कहा कि 16 जनवरी को सैफ अली खान के साथ जो कुछ भी हुआ, वह बेहद चिंताजनक है। हम उनके परिवार के साथ हैं।

सैफ को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और बाहर वह ऐसे दिखे हैं जैसे वह शूटिंग करने के लिए फिट हैं। यह देखना आश्चर्यजनक है। डॉक्टरों ने कहा था कि चाकू उनकी पीठ में 2.5 इंच तक घुस गया था, जिसके लिए छह घंटे का ऑपरेशन करना पड़ा। चिकित्सकीय रूप से इतनी जल्दी ठीक होना कैसे संभव है ?

सैफ पर हमला पहले ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है, क्योंकि महाराष्ट्र की पुलिस ने सैफ पर हमले के आरोप में जिस आरोपी को पकड़ा है वो संयोग से बांग्लादेशी है। भाजपा के लिए बांग्लादेशी घुसपैठिये चुनावी मुद्दा रहे हैं ।

नेशनल कांफ्रेंस के सदर और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. फारुख अब्दुल्ला ने सैफ के जल्द ठीक होने पर तो कोई बात नहीं की लेकिन उन्होंने सैफ के कथित हमलावर के बहाने पूरे बांग्लादेशियों को अपराधी माने जाने की निंदा की है। उनका कहना है कि किसी एक व्यक्ति की गलती का ठीकरा पूरे देश पर नहीं फोड़ा जा सकता है।

सैफ अली के माता-पिता से इस देश की आधी से अधिक आबादी का जुड़ाव है,और इस जुड़ाव की वजह भी साफ है। सैफ के पिता मंसूर अली खान पटौदी एक बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ी थे और सैफ की माँ शर्मिला टैगौर एक बेहतरीन अदाकारा। इस जोड़ी की अपनी-अपनी उपलब्धियां हैं, इसमें किसी राजनीतिक दल का कोई योगदान नहीं है। हम जिस पीढ़ी से आते हैं उस पीढ़ी के लिए नवाब पटौदी और शर्मिला टैगौर देश के लिए गर्व का विषय रहे है। पटौदी और टैगौर की संतान सैफ अली और उनकी पत्नी करीना भी देश की एक पीढ़ी में लोकप्रिय अभिनेता रहे हैं, इसलिए कम से कम आम आदमी तो सैफ की रिकवरी को लेकर कोई सवाल नहीं करना चाहेगा लेकिन नेतागण नहीं मानने वाले।

सैफ के लिए एक और बुरी खबर आई है। सैफ अली खान के पटौदी परिवार की 15,000 करोड़ रुपये की संपत्ति सरकार शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत अपने नियंत्रण में ले सकती है। ये संपत्ति मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। दरअसल, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए 2015 में इन संपत्तियों पर लगायी गयी रोक को हटा दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 के तहत इन संपत्तियों के अधिग्रहण का रास्ता खुल गया है।

इस मामले को सैफ की आने वाली फिल्म ₹ज्वेलथीफः द रेड सन चैप्टर₹ से भी जोड़कर देखा जा रहे है। कहा जा रहा है कि सैफ का अभिनय कैरियर अब ढलान पर है और उनकी यह फिल्म आगामी कुछ दिनों में रिलीज होने जा रही है।

बहरहाल हम सियासत के लिए किसी के स्वास्थ्य को हथियार बनाये जाने के खिलाफ है। इस मामले में आप अपने मन से पूछिए, शायद सही जबाब मिल जाये। क्योंकि सच्चाई से साक्षात्कार कोई सियासी दल, कोई धर्म नहीं करा सकता, दिल ही सच का अहसास करा सकता है।

क्या अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चे भारतीय होंगे? या लागू होने से पहले ही रद्द हो जाएगा ट्रंप का नागरिकता वाला कानून

आप जब कभी भी एयरपोर्ट पर जाते हैं तो आपको हर पल अपनी फ्लाइट का इंतजार रहता है और नजरें विमानों के आगमन/प्रस्थान की जानकारी देने वाली डिस्प्ले बोर्ड पर रहती है। ये अनुभव थोड़ा हटकर होता है। हवाई अड्डे पर आपको हर तरह के लोग देखने को मिलते हैं। कुछ अपनी यात्रा को लेकर उत्साहित होते हैं तो कई खाते-पीते और शॉपिंग करते दिखते हैं। आप किसी ऐसे इंसान के बारे में जानते हैं जो सालों से एयरपोर्ट पर रह रहा हो। ये बात सच है कि मेहरान करीमी नासेरिक ने पेरिस एयरपोर्ट के टर्मिनल वन पर 18 साल गुजारे। लेकिन क्या वास्तविक जीवन में अमेरिका में कुछ ऐसा ही संभव हो सकता है ? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने की दिशा में अपने कदम बढ़ा दिए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि एच-1बी और एल1 जैसे अस्थायी वीजा पर अमेरिका में काम करने वाले भारतीयों के अमेरिका में पैदा हुए बच्चों का क्या होगा? वो किस देश के कहलाएंगे ?

जन्मजात नागरिकता खत्म

अमेरिका के नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बात चल रही है। उन्होंने कहा है कि हम इस मुद्दे को लेकर बेहद ही गंभीर हैं और भारत सरकार को इसे हल करना होगा। ऐसे में 18 से 20 हजार भारतीयों को वापस भेजा जा सकता है। इसके अलावा ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि भारत चाहता है कि एच1बी वीजा प्रोग्राम सरलता से चलता रहे। भारत से बड़ी संख्या में स्किल्ड वर्कर अमेरिका जाते हैं। एच1बी वीजा का सबसे ज्यादा फायदा भारत को ही मिलता रहा है।

जन्मजात नागरिकता क्या है ?

अमेरिकी जमीन पर पैदा हुए किसी भी बच्चे को अपने आप ही नारिकता मिल जाती है, चाहे उसके माता-पिता का इमिग्रेशन या फिर नागरिकता का स्टेटस कुछ भी हो। ट्रंप के आदेश के लागू होने के नाद अमेरिका में पैदा हुए सच्चे को नागरिकता उसी हालत में मिलेगी, जन उसके माता- पिता में से कोई एक अमेरिकी नागरिक हो, ग्रीन कार्ड होल्डर या फिर अमेरिकी सेना में हो।

आदेश को तत्काल चुनौती भी मिल गई है। वहां के 18 राज्यों ने बोस्टन के फेडरल कोर्ट में आदेश को इस आधार पर चुनौती दी है कि यह अमेरिकी संविधान का उल्लंघन करता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि बहुत संभव है कोर्ट के निर्णय की बदौलत यह आदेश लागू होने से पहले ही रद्द हो जाए, लेकिन यह एक अनुमान ही है।

20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में ट्रम्प द्वारा हस्ताक्षरित पहले कार्यकारी आदेशों में से एक जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने से संबंधित था। आदेश में 30 दिन का बफर था, और 19 फरवरी के बाद गैर-नागरिक जोड़ों से पैदा हुए बच्चों को अमेरिकी नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। डेमोक्रेटिक पार्टी शासित कई राज्यों द्वारा अपील किए जाने के बाद, एक संघीय न्यायाधीश ने इसे स्पष्ट रूप से असंवैधानिक बताते हुए जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने वाले कार्यकारी आदेश को अस्थायी रूप से अवरुद्ध कर दिया। ट्रम्प ने कहा कि उनका प्रशासन जन्मजात नागरिकता को प्रतिबंधित करने के उनके प्रयास को अस्थायी रूप से रोकने के संघीय न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ अपील करेगा। न्याय विभाग ने कहा कि हम न्यायालय और अमेरिकी लोगों के सामने पूर्ण योग्यता वाले तर्क प्रस्तुत करने के लिए उत्सुक हैं, जो हमारे देश के कानूनों को लागू होते देखने के लिए बेताब हैं।

अवैध प्रवासियों का मसला

राष्ट्रपति ट्रंप के इस आदेश से जुड़े तकनीकी पहलुओं से ज्यादा बड़ा सवाल उन स्थितियों का है, जिनसे इस आदेश की जमीन तैयार हुई।

अगर अमेरिका में अवैध प्रवासियों का मुद्दा लगातार बड़ा होता गया तो उसमें भारत से जाने वाले अवैध प्रवासियों का योगदान भी कम नहीं है। ऐसे भारतीयों की संख्या 7,25,000 बताई जाती है, जो मेक्सिको और अल सल्वाडोर के बाद सबसे बड़ी संख्या है।

भारतीय मूल के लोगों पर क्या असर

अमेरिका में फिलहाल 4.8 मिलियन यानी 48 भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं जो अमेरिका की कुल आबादी का 1.47% है। जबकि 34% लोग अमेरिका में ही पैदा हुए हैं। इनमें से ज्यादातर इस नए बदलाव से प्रभावित होंगे। बड़ी तादाद में भारतीय मूल के वे लोग भी है, जिन्होंने अमेरिकी नागरिकता जन्म के वक्त ही हासिल की है। अगर यह नीति लागू होती है तो एच-1बी जैसे अस्थायी वर्क वीजा के तहत काम कर रहे और ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे लोगों के बच्चों को जन्म के आधार पर अमेरिका की नागरिकता नहीं मिलेगी।

डंकी रूट पर रोक जरूरी

संख्या उन भारतीयों के लिए भी मुश्किल खड़ी करती है जो वहां वैध तरीकों से पहुंचे हैं और अपनी शिक्षा व काबिलियत से दोनों देशों की शान बढ़ा रहे हैं। अमेरिका की नागरिकता नीति क्या होगी यह उसका घरेलू मसला है, लेकिन भारत के लिए जरूरी है एक लोगों को अवैध तौर पर विदेश पहुंचाने वाले डंकी रूट पर प्रभावी रोक लगे ताकि विकसित देशों में वाइट कॉलर और ब्लू कॉलर जॉब्स के लिए श्रम शक्ति की सप्लाई के वैध, सुरक्षित और सम्मानपूर्ण रास्ते पर आवाजाही बढ़ती रहे।

किस देश के नागरिक ?

अमेरिका में भारतीयों के जीवन को घेरने वाली यह अराजकता ट्रम्प के अमेरिकी नागरिकता के अर्थ और मूल्य की रक्षा₹ शीर्षक वाले कार्यकारी आदेश के बाद आई है। यह आदेश अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन की पुनर्व्याख्या है। अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन में कहा गया है संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मे या प्राकृतिक रूप से जन्मे सभी व्यक्ति, और उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और उस राज्य के नागरिक हैं जहां वे रहते हैं। कार्यकारी आदेश इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि कौन ₹उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं है और इसमें अवैध अप्रवासियों और अस्थायी कार्य वीजा धारकों के बच्चों को शामिल नहीं किया गया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामकता नए संघर्ष को जन्म देगी..

डा. उदयभान सिंह
आर्थिक एवं राजनीतिक विश्लेषक

डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभाल चुके हैं। पद संभालते ही अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। उल्लेखनीय है कि डोनाल्ड ट्रंप आक्रामक नीतियों के लिए जाने जाते हैं। वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को लेकर के वैश्विक जगत में आर्थिक और गैर आर्थिक दोनों ही क्षेत्र में संघर्ष के एक नए दौर के शुरू होने की पूरी संभावना दिख रही है। यही नहीं यह अभी का जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से विस्तारवाद को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक क्षेत्र में भी व्यापार युद्ध शुरू हो सकता है, इस कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में महामंदी का दौर उत्पन्न हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी प्रथम का नारा बुलंद किया है और अमेरिकी राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अमेरिकी हितों की रक्षा करना उनका कर्तव्य है और होना भी चाहिए परंतु डोनाल्ड जिस तरीके से अमेरिकी प्रथम का नारा बुलंद कर रहे हैं उसको लेकर चिंताएं उभर रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर न केवल अमेरिका विरोधी देशों में प्रतिक्रियाएं हो रही है बल्कि अमेरिका के मित्र और समर्थक देशों में भी उनकी नीतियों को लेकर के एक नया माहौल उत्पन्न हो रहा है, यहां तक कि नाटो के सदस्य डेनमार्क और कनाडा में भी भय का माहौल उत्पन्न हो चुका है। जहां डेनमार्क इसलिए चिंतित है कि डोनाल्ड ट्रंप उसे ग्रीन लाइन को बेचने का दबाव बना रहे हैं वहीं दूसरी तरफ कनाडा इस बात को लेकर चिंतित है कि यदि वह अमेरिकी नीतियों के अनुसार कार्य नहीं करता है तो डोनाल्ड ट्रंप कनाडा को 51वॉं अमेरिकी राज्य घोषित कर सकते हैं, इससे कनाडा के स्वतंत्र अस्तित्व को ही चुनौती उत्पन्न हो जाएगी और कनाडा का एक सार्वभौमिक देश के रूप में अस्तित्व समाप्त हो जायेगा।

डोनाल्ड ट्रंप की वापसी को लेकर के यूरोपीय विदेशी परिषद ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के माध्यम से एक विशेष सर्वेक्षण कराया। सर्वेक्षण से बहुत चौंकाने वाले नतीजे सामने आए, जहां जापान, दक्षिण कोरिया, डेनमार्क और ब्रिटेन जैसे देशों में लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप की वापसी पर सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी वहीं डोनाल्ड ट्रंप की वापसी को लेकर के सबसे अधिक सकारात्मक प्रक्रिया भारत में देखने को मिली है डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति बनने को लेकर के जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देश अधिक चिंतित नजर आ रहे हैं जिनकी सुरक्षा को लेकर अमेरिका द्वारा गारंटी दी गई है। इन देशों को यह लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप हमारी सुरक्षा को लेकर कितना आर्थिक बोझ हमारे ऊपर डालेंगे?

उल्लेखनीय है कि संयुक्त राज्य अमेरिका जिन देशों को सुरक्षा की गारंटी देता है बदले में उनसे वह खर्च वसूल करता है। डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति बनने से न केवल उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के पूरे वैश्विक क्षेत्र की सामरिक परिदृश्य में बदलाव की आशंका व्यक्त की जा रही है, लोग इसको लेकर चिंतित भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर के अमेरिकी खाड़ी करने का आदेश जारी कर दिया, यही नहीं पनामा भी विशेष चिंतित नजर आ रहा है। उसे लगता है कि यदि वह संयुक्त राज्य अमेरिका की नीतियों के अनुसार कार्य नहीं करेगा तो संयुक्त राज्य अमेरिका पनामा नहर पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लेगा।

डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रीय सुरक्षा और अमेरिका की अर्थव्यवस्था को लेकर काफी अधिक सतर्क नजर आ रहे हैं और ऐसा होना भी चाहिए परंतु वर्तमान दौर में वैश्विक समुदाय के साथ तालमेल भी बैठाना जरूरी है। परंतु डोनाल्ड ट्रंप ऐसा करते फिलहाल नहीं दिख रहे हैं।

उनकी नीतियों को लेकर के नाटो अभी से चिंतित होने लगा है। ट्रंप नाटो को दी जाने वाली आर्थिक सहायता और सामरिक सहयोग में भी कटौती करना चाहते हैं। यदि अमेरिका द्वारा नाटो को आर्थिक और सामरिक सहायता नहीं दी जाती है तो नाटो का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि नाटो का गठन पूर्व सोवियत संघ को संतुलित करने के लिए किया गया था। ट्रंप रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर के भी एक अलग नीति पर चलना चाहते हैं। वह यूक्रेन युद्ध से अपने को अलग करने का भी कोई रास्ता तलाश रहे हैं।

यदि अमेरिका रूस-यूक्रेन युद्ध से अपने को अलग कर लेता है अर्थात वह यूक्रेन को मदद देना बंद कर देता है तो यूक्रेन की पराजय निश्चित है और इसके साथ ही एक लम्बे समय से चला आ रहा यह युद्ध भी समाप्त हो जाएगा। अमेरिका रूस को भी खुली छूट देने के पक्ष में नहीं है। यहीं पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों में विरोधाभास दिखाई पड़ता है। अपने प्रथम राष्ट्रपति उद्बोधन में डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की आर्थिक और विस्तारवादी नीतियों पर कड़ा प्रहार किया और चीन का नाम लिए बिना उसे संयमित होकर कार्य करने की सलाह भी दी।

पश्चिम एशिया के संदर्भ में भी डोनाल्ड ट्रंप अपने पूर्व राष्ट्रपति बाइडन की नीतियों से हटकर कार्य करना चाहते है। इजराइल और फिलीस्तीन के बीच चल रहे युद्ध को समाप्त करवाने की पक्ष में नजर आ रहे हैं उनकी पहल पर यहां युद्ध विराम हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए पश्चिम एशियाई चुनौती पूर्ण रहेगा क्योंकि पश्चिम एशिया में इजरायल और ईरान के मध्य भी संघर्ष की संभावना काफी प्रबल दिखती है। सीरिया के एपिसोड का समाधान भी खोजना होगा वहीं ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षा और पाकिस्तान में आतंकी संगठनों की प्रभावी उपस्थिति पर भी डोनाल्ड ट्रंप नियंत्रण लगाना चाहेंगे।

जहां तक भारत का संबंध है तो डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में भारत और अमेरिका के बीच अच्छे संबंध रहे है। डोनाल्ड ट्रंप के पुनः राष्ट्रपति बनने के बाद नव नियुक्त अमेरिकी विदेश मंत्री ने सबसे पहले बातचीत के लिए भारत के विदेश मंत्री को आमंत्रित किया और भारत के साथ द्विपक्षी एवं बहुपक्षी मुद्दों पर बातचीत की।

यह हमारे लिए एक सकारात्मक पहलू है परंतु हमें सतर्क रहने की भी जरूरत है। यह सही है कि भारत और अमेरिका के संबंधों में निरंतर परिपक्वता और सामरिकता देखने को मिल रही है जो समय की मांग और आवश्यकता दोनों ही है परंतु भारतीय राजनेताओं और कूटनीतिज्ञों को सोच समझकर इस दिशा में आगे बढ़ना होगा, जिसे वह करते हुए भी दिखाई पड़ रहे है। हिन्द प्रशांत क्षेत्र वर्तमान में भारत और अमेरिका दोनों के लिए ही काफी महत्वपूर्ण है।

हिन्द प्रशांत क्षेत्र में चीन की प्रभावी उपस्थिति के कारण तनाव बना हुआ है। उल्लेखनीय है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की शक्ति को संतुलित करने के लिए ही भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्वॉड का गठन किया है। भारत अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में लगातार अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहा है और प्रशांत महासागर के तटीय देशों के साथ विशेष सामरिक समझौता कर रहा है। भारत के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के साथ प्रभावी सहयोग जरूरी दिखाई पड़ता है। अमेरिका के लिए भी ऐसा जरूरी है इसलिए दोनों की अपनी-अपनी आवश्यकता है जो एक दूसरे को सामरिक सहयोग के लिए प्रेरित करती है।

ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद केवल सामरिक क्षेत्र में ही परिवर्तन की संभावना या संघर्ष की संभावना नहीं दिखाई पड़ रही है बल्कि इसका सबसे अधिक प्रभाव आर्थिक क्षेत्र पर पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति विभिन्न देशों से आयातित होने वाली वस्तुओं पर काफी वृद्धि करने का विचार कर रहे हैं। देश से होने वाले आयातों पर 25 प्रतिशत से अधिक सीमा शुल्क में वृद्धि करने की घोषणा कर चुके हैं, बदले में अन्य देश भी अमेरिकी वस्तुओं पर आयात शुल्क में वृद्धि करने की तैयारी कर रहे हैं। यदि ऐसा होता है तो इससे वैश्विक स्तर पर नया व्यापार युद्ध शुरू हो जाएगा, जिसके कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में मांग में कमी आएगी और महामंदी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अनेक अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में दिए जाने वाले अमेरिकी आर्थिक सहयोग की भी समीक्षा करने का निर्णय लिया गया है। इस क्रम में विश्व स्वास्थ्य संगठन को अमेरिका द्वारा दी जाने वाली सहायता को पूर्णतया बंद करने की भी बात कही गई है, यही नहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका अपने को अलग भी कर रहा है। यह वैश्विक परिदृश्य के लिए चिंता का विषय है। यदि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को दिए जाने वाली आर्थिक सहायता में कटौती की जाती है तो इसका प्रभाव उनकी कार्य प्रणाली और क्षमता पर पड़ेगा और इसके कारण संपूर्ण वैश्विक व्यवस्था नकारात्मक रूप में प्रभावित होगी।

यही नहीं डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में विदेशियों की संख्या को निरंतर कम करने पर भी बल दे रहे हैं और अमेरिका की वीजा प्रणाली को भी और अधिक कठोर बनाने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने इस दिशा में कदम उठाना शुरू भी कर दिया है, इस कारण भी वैश्विक जनशक्ति की गतिशीलता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हालांकि अमेरिका को यह अधिकार है कि वह अपने हितों की रक्षा के लिए हर कदम उठा सकता है।

किसी भी देश के शासक का पहला कर्तव्य अपने देश के लोगों के हितों की रक्षा करना है, इस आधार पर अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय कहीं से भी गलत नहीं है। परंतु संयुक्त राज्य अमेरिका एक महाशक्ति है वह वैश्विक राजव्यवस्था और अर्थव्यवस्था दोनों को ही नियंत्रित, निर्देशित और संचालित करता रहा है अतएव उससे यह अपेक्षा स्वभाविक है कि वह न केवल अमेरिकी हितों का संरक्षण करेगा बल्कि संपूर्ण वैश्विक समाज के हितों का भी संरक्षण करेगा।

भारत में आस्था का महाकुंभ और विदेशों में बढ़ती नास्तिकता

सुभाष आनंद

इन दिनों प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, जहां देश विदेश से करोड़ों लोग आ रहे हैं और पुण्य स्नान का लाभ उठा रहे हैं। यहां आने वाले लोग सनातन धर्म में भरपूर आस्था रखते हैं। एक ओर प्रयागराज के महाकुंभ में आस्था का समुन्दर उमड़ रहा है वहीं दूसरी ओर शेष विश्व में नास्तिकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है।

प्रोफेसर डेविड बूथ का कहना है कि पिछले 40-50 वर्षों में पश्चिमी देशों में धर्म के नाम पर आस्था निरंतर कम हुई है, लेकिन भारत, पाकिस्तान, ईराक, ईरान में धर्म पर आस्था बढ़ती दिख रही है। वैसे यह भी सत्य है कि दुनिया में आस्था कभी भी समाप्त नहीं हो सकती कम अवश्य हो सकती है।

भारत से बाहर शेष विश्व में जिस प्रकार नास्तिक लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है तो क्या वहां धार्मिक होना अतीत की बात हो जाएगी, इस प्रश्न का उत्तर मुश्किल ही नहीं बल्कि बहुत मुश्किल है।

कैलिफोर्निया में क्लेरमांट के पिटजुर कालेज में सामाजिक विज्ञान के प्रोफेसरों ने एक सर्वे किया है और उनका कहना है कि दुनिया भर में नास्तिक लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है और धार्मिक आस्था में कमी आ रही है। इस तथ्य की पुष्टि गैल्प इंटरनेशनल ने भी की है। गैल्प इंटरनेशनल ने 2020 से 2024 तक 97 देशों में एक लाख से अधिक लोगों को अपने सर्वे में शामिल किया।

सर्वे में कहा गया है कि जिन 100 देश के लोगों को शामिल किया गया, उनके अनुसार धर्म के नाम पर उनकी आस्था बहुत तीव्रता से कम हो रही है। धर्म को मानने वालों की संख्या 76 फीसदी से कम होकर अब 64 फीसदी तक रह गई है। खुद को नास्तिक बताने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। विश्व में नास्तिकों की

संख्या 26 प्रतिशत को पार कर चुकी है।

सर्वे से पता चला है कि चीन में 90 फीसदी लोग नास्तिक है, जापान में 86 फीसदी, स्वीडन में 78 फीसदी , चैक रिपब्लिकन में 75 फीसदी, यूके में 72 फीसदी, बेल्जियम में 71फीसदी, एस्टोनिया में 70.8 फीसदी, ऑस्ट्रेलिया में 70 फीसदी, नार्वे में 70 फीसदी, डेनमार्क में 68 फीसदी नास्तिक हैं। सर्वे के अनुसार नास्तिकों की संख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि उन देशों में हुई है जो अपने नागरिकों को आर्थिक, राजनीतिक और अस्तित्व की ज्यादा सुरक्षा देते हैं।

100 वर्ष पहले जापान, ब्रिटेन, नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस जैसे देशों में धर्म को उच्च स्थान दिया जाता था, अब इन देशों में ईश्वर को मानने वालों की संख्या बड़ी तेजी से कम हो रही है। दूसरी ओर रूढ़िवादी देशों में धर्म के नाम पर आस्था बढ़ रही है। वही, ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों का कहना है कि नास्तिकों के बढ़ने के कारण धर्म कभी समाप्त नहीं होगा, हां शनैः शनैः कम जरूर हो जाएगा।

मौलवी, पंडित ,धर्मगुरु, प्रचारकों और पादरियों का कहना है कि जैसे-जैसे विश्व में नास्तिकों की संख्या बढ़ रही है त्यों-त्यों धरती पर पाप बढ़ रहे हैं जिससे आगे दुःख बढ़ेगा।

धर्मगुरुओं का कहना है कि भविष्य में जलवायु परिवर्तन से विश्व पर संकट बढ़ेगा और प्राकृतिक संसाधनों की कमी होगी। वह चाहते हैं कि दुनिया की परेशानियां चमत्कारिक ढंग से दूर हों, हम शांतिपूर्वक ढंग से जीवन का निर्वाह करें, ऐसा तब ही होगा जब धर्म हमारे आसपास रहेगा। ऐसा इसलिए है कि मानव के विकास के दौरान ईश्वर की जिज्ञासा हमारी प्रजाति के तांत्रिका तंत्र से बची रहती है। इसको समझने के लिए दोहरी प्रक्रिया के सिद्धांत को समझने की जरूरत है ।

मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि हमारे दो विचार सिस्टम है, सिस्टम एक और सिस्टम दो। सिस्टम दो अभी-अभी विकसित हुआ है, यह अपने-अपने दिमाग की उपज है जो हमारे दिमाग में बार-बार गूंजती है। कभी चुप हो जाती है कभी योजना बनाने और यांत्रिक रूप से सोचने को मजबूर करती है।

दूसरा सिस्टम एक सहज, स्वाभाविक और ऑटोमेटिक है। यह बातें इंसान के जीवन में नियमित विकसित होती रहती है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंसान कहां पैदा हुआ है वह अस्तित्व का तंत्र या सिस्टम बिना सोचे समझे हमें बिना ज्यादा प्रयास किये सजीव और निर्जीव चीजों की पहचान करने की क्षमता देता है। बच्चों को माता-पिता की पहचान कराता है। यह दुनिया को बेहतर ढंग से समझने, प्राकृतिक आपदाओं या अपने करीबियों की मौत की घटनाओं को समझने में मदद करता है। इंसान स्वाभाविक तौर पर मानना चाहता है कि वह किसी बड़ी तस्वीर का हिस्सा है और जीवन पूर्ण रूप से निरर्थक नहीं है।

हमारा मन उद्देश्य और स्पष्टीकरण के लिए लालायित रहता है, धार्मिक विचारों को अपनाना मनुष्य के लिए सबसे कम प्रतिरोध का रास्ता है। धर्म से छुटकारा पाने के लिए आपको मानवता में कुछ मूलभूत बदलाव लाने होंगे। ईश्वर के प्रति आस्था की बात करें तो 25 प्रतिशत अमेरिकन किसी चर्च से संबंध नहीं रखते, लेकिन सर्वे में 62 फीसदी ने बताया कि वह ईश्वर में विश्वास रखते हैं, 32 फीसदी ने बताया कि वह धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं। दुनिया भर के सर्वे के पश्चात कुछ लोगों ने कहा है कि उन्हें ईश्वर में कोई यकीन नहीं, अभी तक उसे किसी ने देखा नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अलौकिक शक्ति एक परिकल्पना है तो वहीं मुल्ला, मौलवियों, पादरियों, पंडितों, धर्म गुरुओं का कहना है कि धर्म इंसानों से कभी दूर नहीं जा सकता, धर्म मनुष्य के दिलों में डर और प्रेम दोनों बनाए रखता है।

एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया है कि भारत में 90 फीसदी लोग आस्तिक हैं और केवल 10 फीसदी लोग नास्तिक हैं। भारत में लोग धर्म गुरुओं और डेरों से भी जुड़े हुए हैं। सिखों का गुरुद्वारे में अथाह विश्वास है। उसी प्रकार इस्लाम धर्म से जुड़े मुस्लिम समाज भी मस्जिदों में सजदा करते है। ईसाई लोग अपने पवित्र गिरजाघर में जबकि हिंदू किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ने के बजाए अपने घरों में और धार्मिक स्थलों पर ईश्वर आराधना में विश्वास रखते हैं। हर समाज में अनेक धर्मगुरु हैं। धर्मगुरु अपने-अपने धर्म का प्रचार करने में लगे हुए हैं, केवल 10 प्रतिशत लोग ही यहां नास्तिक हैं।

मानव जीवन और सूर्य

डॉ. गुलाबचंद कोटडिया

प्रकृति का सबसे महान घटक सूर्य है जिसके बारे में आज भी हम बहुत कम जानते हैं। अनुमान ही अधिक लगाते हैं। चांद पर तो मानव चढ़ भी गया,यात्रा करके आ भी गया, पर सूर्य से लाखों मील दूर ही वह खड़ा रह सकता है अन्यथा भस्म हो जाएगा। हमारे वैदिक व हिन्दू पूर्वज अध्येताओं ने समय नापने की एक सीमा बांधी थी उसका नामकरण भी सूर्य पर ही किया है। 4.32 मिलियन सूर्य वर्ष अर्थात उसे एक महायुग माना। खगोलशास्त्री लाखों वर्षों से शोध में लगे है और समय समय पर शून्याकाश या अंतरिक्ष के रहस्यों की थोड़ी थोड़ी जानकारी देते रहते हैं, अंतरिक्ष में अवस्थित स्पेस शटल प्रयोगशाला से विकसित देश इस सूर्य ज्ञान की ओर अग्रसर है। भौतिक विज्ञानी और रसायनशास्त्री भी इस बारे में नए नए प्रयोग करते रहते हैं। पर हमारी भारतीय संस्कृति व पूर्वज ऋषि मुनिगण हिमालय जैसे हिम प्रदेश में निवास कर ऐसे ज्ञान का विकास कर चुके थे जो आज भी प्रासंगिक है। विविध क्षेत्रों में उन्होंने कई पद्धतियां अपनाई व सिद्धांतों का प्रतिपादन भी किया।

पाश्चात्य विज्ञानी पोल ब्रंट ने भारत में भ्रमण कर प्राचीन ऋषि मुनियों के बारे में खूब जानकारी हासिल की और एक किताब लिखी 'ए सर्च इन सीक्रेट इंडिया' उसमें उन्होंने महायोगी स्वामी विशुद्धानंदजी का खास उल्लेख किया जो सूर्य विज्ञान या सिद्धांत के मर्मज्ञ थे। उनको सूर्य की साधना द्वारा कई सिद्धियां प्राप्त हो चुकी थी। महर्षि पतंजलि के जीयंतर परिणाम अर्थात एक वस्तु के दूसरे वस्तु में परिवर्तन या रूपांतरण की वैज्ञानिक जानकारी उन्होंने प्रस्तुत की।

स्वामी विशुद्धानंद के मतानुसार विश्व में हर स्थान पर सभी वस्तुएं शाश्वत रूप से विद्यमान रहती हैं परंतु सभी वस्तुएं एक समय में व्यक्त नहीं होती। पदार्थ मात्रा या गुण धर्म अधिक विकसित हो तभी प्रस्फुटित होकर प्रगट हो सकती है। सूर्य विज्ञान का मतलब भी यही है कि एक पदार्थ में परिवर्तन या रूपांतरण करने का विज्ञान या शास्त्र।

उदाहरण स्वरूप लोहे का टुकड़ा है। वह मात्र लोहे का टुकड़ा नहीं होता। उसमें कई अन्य तत्व या पदार्थ अव्यक्त रूप से उपस्थित रहते हैं। उसमें थोड़ी मात्रा या अंश में स्वर्ण भी मौजूद रहता है परंतु सूक्ष्म स्वरूप की सुषुप्त अवस्था को जागृत किया जाए, उसमें स्वर्ण मात्रा बढ़ाई जाए तो लौह का अस्तित्व या लौह भाव दब जाता है और स्वर्ण भाव बढ़ जाने से लौह खंड का टुकड़ा सोने का हो जाता है। पारस पत्थर की कल्पना पूर्वजों ने ऐसे ही नहीं की थी। लोहे का पारस पत्थर छूकर वह सोने का बन जाना इसी सिद्धांत के अनुरूप है। हमारे शास्त्रों में कहा भी है कि दुनिया में जितने भी नाम पदार्थ या शब्द हैं वे सभी अस्तित्व में है। यह अलग बात है कि कुछ चीजें अदृश्य व अव्यक्त रहती हैं कुछ दृश्यमान व

व्यक्त हो जाती हैं या हो सकती हैं। इसी सिद्धांत को लेकर विज्ञानी आगे बढ़े और अध्ययन व प्रयोग से इतनी वस्तुओं का आविष्कार कर पाए हैं और कई नई नई चीजें हमारे सामने प्रगट हो रही हैं।

जैन शास्त्रों में त्रिपदी है। उत्पन्ने इवा, विगमेईवा, धूवे ईवा अर्थात उत्पन्न होता है, नष्ट होता है व स्थिर रहता है। जगत का यही शाश्वत स्वभाव है।

सुषुप्त व जागृत अवस्था साथ साथ चलती है। लोहे का टुकड़ा नष्ट नहीं हुआ सोना नहीं बना पर दोनों तत्व उसमें मौजूद है। मात्रा में घनत्व का अंतर हो सकता है। अगर तत्व या पदार्थ की मात्रा किस प्रकार परिवर्तित की जाए उसका ज्ञान किसी को हो जाए तो कहीं भी कभी भी कोई भी वस्तु हाजिर की जा सकती है। योग शास्त्र की परंपरा मात्र हमारे देश में ही थी। योग शक्ति द्वारा पदार्थ का रूपांतरण इसी प्रकार होता है तथा उसमें सूर्य विज्ञान सहायक होता है। उसकी सहायता आवश्यक होती है।

महर्षि पतंजलि ने सूर्य विज्ञान के बारे में बहुत ही गंभीर विशिष्ट संशोधन किया था। उनके अनुसार सूर्य की किरणों में अलग अलग रंग या रश्मियां विद्यमान रहती है। उसका समन्वित रंग मात्र श्वेत है जिसे विशुद्धात्मक तत्व कहा जाता है। इस श्वेत रश्मि को 24 कोणीय स्फटिक मणि के माध्यम से देखा जा सकता है। इस स्फटिक का प्रत्येक कोना वतुर्लावस्था में होता है ज्यों ही सूर्य की किरणें स्फटिक लेंस पर पड़ती हैं तब घनीभूत होकर एक वर्तुल दूसरे वर्तुल में प्रवाहमान बनकर 24 वें वर्तुल में प्रवेश करती है तब हमें संपूर्ण शुभ्र या श्वेत रंग दिखने लगता है। इस स्थिति में ये रश्मियां पदार्थ पर पड़ती हैं तो उसमें से इच्छित पदार्थ का परिवर्तन शक्य बन सकता है।

सूर्य सिद्धांत में उपासना द्वारा निष्णात बनने वाले योगियों को इस बात का ज्ञान था कि किसी पदार्थ के कितने वर्तुल हो सकते हैं। स्वामी अखिलेश्वरानंदजी के पास भी यह ज्ञान था।

जिस प्रकार एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में रूपांतरण करने की प्रक्रिया में सूर्य सिद्धांत कार्य करता है उसी तरह योग बल द्वारा कोई भी कार्य स्फटिक यंत्र की सहायता के बिना भी किया जा सकता है। स्वामी अखिलेशवरानंदजी ने हिमालय के 'महायोगियों की गुप्त सिद्धियां' किताब में लिखा है कि प्रत्यक्ष रूप से हम जिस दैदीप्यमान सूर्य को देखते हैं उससे भी करोड़ गुना अधिक शक्ति व तेजवाला सूर्य हमारे अंदर विद्यमान है पर हमारे मन में बिखरा हुआ रहता है। योग साधना द्वारा अगर उसे घनीभूत बनाकर नेत्रों के माध्यम से किसी पदार्थ पर फेंका जाए तो इच्छित वस्तु के रूप में रूपांतर किया जा सकता है। यहां एकाग्रता की जरूरत होती है। थोड़े समय के लिए जादूगर यह करते दिखाई दे सकते हैं पत्थर को फूल या मिश्री बना सकते हैं। योगी सिद्धियां प्राप्त करने पर यही काम कर सकते हैं।

हिमालय क्षेत्र मानसरोवर और कैलाश के पूर्व में पुराणों में वर्णित कायालग्राम आश्रम नामक ऐसी दिव्य जगह का उल्लेख मिलता है, जहां हजारों सिद्ध योगी सूक्ष्म शरीर में विचरण करते हैं तथा अपनी साधना में लीन रहते हैं। परंतु उस स्थल के दर्शन दिव्य दृष्टि संपन्न कुछ कृपापात्र व्यक्ति कर सकते हैं। स्थूल आंखों से उसे देख पाना असंभव है।

हिमालय सिद्धयोगियों का प्रिय स्थान रहा है। तपस्थल किसी प्रयोगशाला से कम नहीं होता। वहां बसने वाले महान योगी परकाया प्रवेश, आकाशगमन, जलगमन अर्थात जल पर चलना, साधना, समाधि में अवस्थित होना जैसे सिद्धांतों का जीवंत वर्णन स्वामी अखिलेश्वरानंदजी महाराज ने अपनी किताब में किया है। भारत में इण्डियन प्लेनेटरी सोसाइटी, मुंबई के एमेटर एस्ट्रोवाकर एसोसिएशन, गोवा की नेशनल सेंटर फार अंटार्कटिक एंड ओसियन रिसर्च, अहमदाबाद की स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, बैंगलूर की अस्ट्रोफिजिक्स इन्स्टीट्यूट, नैनीताल की वेधशाला, स्पेशल टेलीस्कोप, स्प्रेक्टोमीटर और सी सी डी कैमरा ये सब सूर्य विज्ञान का अध्ययन करने वाली संस्थाएं कार्यरत हैं।

बाल कहानी

दादा की सूझ

वीरेंद्र बहादुर सिंह

दादा को कुश बहुत प्यारा था। कुश भी दादा को बहुत चाहता था। दादा की कही वह हर बात मानता था। दादा होमवर्क करने को कहते तो वह कैसे भी फटाफट होमवर्क कर लेता था। दादा की हर छोटी-बड़ी चीज रखने में मदद करता था।

कुश को कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता था। इसलिए वह दादा से बारबार कहानियां कहने के लिए कहता। रात होती नहीं कि कुश दादा के पास कहानियां सुनने के लिए बैठ जाता।

एक दिन कुश होमवर्क कर रहा था तो उसके पीछे खड़े देख रहे थे। दादा ने देखा कि कुश होमवर्क तो करता है, पर उसकी एक गलत आदत है। वह बारबार पेंसिल छील कर उसकी नोक निकालता था। दो पेज के होमवर्क में सात-आठ बार पेंसिल छील कर नोक निकाली। इस तरह उसकी पेंसिल आधी हो गई। कुश ने वह पेंसिल कचरे के डिब्बे में डाल दी और नई पेंसिल निकाल कर लिखने लगा। दादा मन ही मन कुछ तय कर के वहां से चले गए।

रात होते ही रोज की तरह कुश दादा के पास कहानी सुनने पहुंच गया। उसने कहा, दादा... दादा कहानी कहो न।

दादा ने कहा, मैं कहानी जरूर कहूंगा। आज तुम्हें मैं एक वैज्ञानिक खोज की कहानी सुनाऊंगा।

खोज शब्द सुन कर कुश खुश हो गया। उसने कहा, दादा जल्दी सुनाओ ना।

दादा ने कहा, आज हम पेंसिल की खोज और ऊसकी बनावट के बारे में बात करेंगे।

कुश दादा की गोद में बैठ कर उनकी बातें ध्यान से सुनने लगा। दादा ने कहानी शुरू की, पुराने जमाने में जब आदमी के पास पेंसिल नहीं थी, तब वह काले कोयले या किसी वनस्पति के रंग का उपयोग कर के चीजों पर निशान लगाता था। बाद में ग्रेफाइट नाम के पदार्थ की खोज हुई। यह ऐसा पदार्थ था, नरम होते हुए भी कड़ा था। किसी सख्त आवरण में लपेट कर इसका उपयोग लिखने के लिए हो सकता था। यह समझ में आते ही इसका उपयोग लिखने के लिए किया जाने लगा।

पर आज की पेंसिल कैसे बनी? कुश ने पूछा।

दादा ने कहा, पेंसिल की बनावट में ग्रेफाइट के साथ पहाड़ी पेड़ों की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। यह लकड़ी छीलने और पकड़ने में आसान होती है। इस लकड़ी से आसानी से पतली पट्टी बनाई जा सकती है। इसे विविध आकार में काटा जा सकता है। इसलिए पेंसिल के आवरण के लिए उन लकड़ियों का उपयोग होने लगा।

दादा, ये लकड़ियां कहां मिलती हैं? कुश ने पूछा।

ये लकड़ियां पहाड़ी जंगलों में मिलती हैं। दादा ने कहा, हिमालय के जंगलों में इसके पेड़ अधिक दिखाई देते हैं। और कुश तुम्हें पता है, पेंसिल बनाने में कितनी मेहनत और समय लगता है? इससे पर्यावरण का कितना नुकसान होता है?

कैसे? कुश ने पूछा।

दादा ने कहा, एक बात तो यह कि यह लकड़ी पहाड़ी जंगलों में होती है। इसे वहां से लाना मुश्किल होता है। दूसरी बात यह कि पेड़ काटने से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। कंपनी के लोग खूब मेहनत कर के इसे बनाते हैं। इसलिए इसका उपयोग बहुत संभाल कर करना चाहिए।

दादा की बात सुन कर कुश सोच में पड़ गया। वह जब भी होमवर्क करने बैठता है, बारबार पेंसिल छील कर नोक निकालने के चक्कर में छोटी कर देता है। यह विचार मन में आते ही उसने कहा, दादाजी, अब मैं पेंसिल का उपयोग खूब संभाल कर करूंगा।

यह सुन कर दादाजी मन ही मन खुश हो उठे।

व्यंग्य

गणतंत्र दिवस और ट्राई कलर बैलून्स इन स्काई

विवेक रंजन श्रीवास्तव

तिरंगे की छाया में खडे , बंद गले का जोधपुरी सूट पहने,सफेद टोपी लगाये गर्व से अकड़े हुये मुख्य अतिथि ने परेड की सलामी ली। उद्घोषणा हुई कि आकाश की असीम ऊंचॉईयों तक ट्राई कलर का संदेश पहुंचाने के लिये गैस के गुब्बारे ₹बंच आफ ट्राई कलर बैलून्स₹ छोड़ कर हर्ष व्यक्त किया जायेगा। सजी संवरी दो सुंदर लड़कियों ने केसरिया, सफेद , हरे गुब्बारों के गुच्छे मुख्य अतिथि की ओर बढ़ाये। शौर्य, देश भक्ति और साहस के प्रतीक ढ़ेर सारे केसरिया गुब्बारे सबसे अधिक ऊंचाई पर थे, सफेद गुब्बारों के धागे कुछ छोटे थे। उद्घोषक की भाषा में सफेद रंग के ये गुब्बारे शांति, सदभावना और समन्वय को प्रदर्शित करते इठला रहे थे। इन्हीं सफेद गुब्बारों में एक गुब्बारा गहरे नीले रंग का भी था जो तिरंगे के अशोक चक्र की अनुकृति के रुप में गुच्छे में बंधा था। वही अशोक चक्र जो सारनाथ के अशोक स्तंभ से समाहित किया गया है, हमारे तिरंगे में। यह चक्र राष्ट्र की गतिशीलता , समय के साथ प्रगति तथा अविराम बढ़ते रहने को दशार्ता है। सबसे नीचे हरे रंग के खूब सारे फुग्गे थे। देश के कृषि प्रधान होने, विकास और उर्वरता के प्रतीक का रंग है तिरंगे का हरा रंग।

मुस्कुराते हुये मुख्य अतिथि ने बंच आफ ट्राई कलर बैलून्स छोड़ दिये। कैमरा मैन एक्शन में आ गया, लैंस जूम कर,आकाश में गुब्बारों के गुम होते तक जितनी बन पड़ी, उतनी फोटो खींच ली गईं। समाचार के साथ ऐसी फोटो न्यूज को आकर्षक बना देती है। नीले आसमान के बैकग्राउंड में, सूरज की सुनहरी धूप के साथ, बंच आफ ट्राई कलर बैलून्स इन स्काई की फोटो खबर में देशभक्ति का जज्बा पैदा कर देती है।

किन्तु कोई अदृश्य हाथ तो हैं जो तिरंगे की तीनों रंग की पट्टियों की सिलाई उधेड़कर उन्हें अलग अलग करने पर आमादा है? कौन सी ताकतें हैं जो जगह जगह जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय की कैंचियां उगाने में जुटी हुई हैं ? ये आवाजें कहां से आ रही है कि समाज के इस हिस्से को उस हिस्से से अलग कर दो? झंडे का साया तो हमेशा से एकता का पाठ पढ़ाता आया है। संविधान में केवल अधिकार नहीं कर्तव्य भी तो दर्ज हैं। देश का जन गण मन तो वह है,जहां फारूख रामायणी अपनी शेरो शायरी के साथ राम कथा कहते हैं। जहां मुरारी बापू के साथ ओस्मान मीर, गणेश और शिव वंदना गाते हैं। फिल्म बैजू बावरा का भजन है मन तड़पत हरि दर्शन को आज, इस गीत के संगीतकार नौशाद, गीतकार शकील बदायूंनी तथा गायक मोहम्मद रफी हैं।

तिरंगे ने कभी भी इन संगीत के महारथियों से उनकी जाति नहीं पूछी। आज के हालात पर बेचैन तिरंगे ने उस भीड़ से पूछा जो उसे हिला हिला कर आजादी की मांग कर रही थी कि मेरे साये में यह जातिगत भीड़ क्यों? तो किसी से उत्तर मिला कि ऐसा केवल सोशल मीडिया पर है, जन गण मन तो आज भी वैसा ही है। आसमान के अनंत सफर पर निकले ट्राईकलर बैलून बंच ने कहा आमीन! काश ऐसा ही हो! यदि ऐसा है तो समझ लो कि इस भ्रामक सोशल मीडिया की उम्र ज्यादा नहीं है क्योंकि झूठ की जड़े नहीं होती,यह शाश्वत सत्य है। व्हाट्सअप,फेसबुक, यू ट्यूब अपना भरोसा खुद ही खत्म कर रहे है।

बंच आफ ट्राई कलर बैलून्स इन स्काई, साहस, शांति, अविराम प्रगति और विकास का संदेशा लिये कुछ और ऊपर उड़ चला। आयोजन में बच्चे ड्रिल कर रहे थे और बैंड बजा रहा था इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के।

दुनिया में लग्जरी ब्रांड्स के 5 करोड़ ग्राहक घटे

वीरेंद्र बहादुर सिंह

रुपए 385 अरब डालर - यह आंकड़ा है पिछले साल के ब्रांडेड प्रोडक्ट के व्यापार का। साल 2024 के अंत तक लग्जरी प्रोडक्ट का मार्केट घट कर 369 अरब डालर रह गया है। गिरने का यह क्रम अभी रुकने वाला भी नहीं है। इटली के अल्टागामा लग्जरी एसोसिएशन का कहना है कि 2025 में लग्जरी प्रोडक्ट का मार्केट और घटेगा और यह 363 अरब डालर तक आ जाएगा। चीन और अमेरिका जैसे देशों में लग्जरी प्रोडक्ट का क्रेज घटने से ग्लोबल लग्जरी मार्केट को बड़ा झटका लगा है।

प्रतिष्ठित बिजनेस अखबार फोर्ब्स की मानें तो 2020 में कोविड के दौर में भी लग्जरी प्रोडक्ट की बिक्री इतनी कम नहीं हुई थी। 2024 में अचानक 5 करोड़ ग्राहकों ने लग्जरी प्रोडक्ट खरीदना बंद कर दिया है। 2025 में 4 प्रतिशत की दर से यह कमी आएगी तो एकाध करोड़ ग्राहक और घट जाएंगे। 2008 में वैश्विक मंदी आई थी तब भी लग्जरी मार्केट पर असर पड़ा था और ग्लोबल मार्केट में 8 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई थी। उसके बाद इतने सालों में लग्जरी प्रोडक्ट की बिक्री में इतना बड़ा झटका नहीं लगा था।

ग्लोबर लग्जरी मार्केट में गिरावट के पीछे रूस-यूक्रेन और इजराइल-हमास के युद्ध के अलावा राता समुद्र के व्यापारिक मार्ग का बंद होना भी है। 2025 में मार्केट घटेगा तो इसके पीछे ट्रम्प का टेरिफ टेरर जिम्मेदार माना जाएगा। दुनिया में विश्वयुद्ध का खतरा मंडराने की वजह से अमारिकी धनिकों ने खर्च कम कर दिया है। चीन का अर्थतंत्र धीरे धीरे मंदी की ओर बढ़ रहा है, इसलिए चीनी कस्टमर्स ने भी खर्च घटा दिया है। दुनिया में इस समय अनिश्चितता का माहौल है। संभावना है कि महंगाई खूब बढ़ेगी। पिछले साल आईटी सेक्टर में बड़ी छंटनी हुई है। ग्लोबल लग्जरी मार्केट पर इसका भी असर पड़ा है।

वैभव, समृद्धि, संपन्नता, ऐश्वर्य यानी क्या?

बिना मेहनत की लाइफस्टाइल, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, उत्तम सुख-सुविधा, घूमने-फिरने के लिए सुगम वाहन, सेवा-चाकरी-मदद के लिए मददगार - धन-संपत्ति हो तभी वैभवी लाइफस्टाइल वश में होगी। इस तरह की धन-दौलत एक जमाने में राजा-महाराजा, उमरावों और बड़े व्यापारियों के नसीब में थी। इसलिए यह सुख-सुविधा उनके भाग्य में ही लिखी थी। सामान्य आदमी सेना में भरती हो जाता था या खेती कर के जीवनयापन करता था।

एक जमाने में राजाओं-महाराजाओं के लिए 32 तरह का व्यंजन परोसा जाता था। मधुर पेय हाजिर रहता था। वे महंगे कपड़े पहन सकते थे। सुख-सुविधाजनक महलों में रह सकते थे। नौकर-चाकर की सेवा ले सकते थे।

उस समय इस तरह का सुख-सुविधाजनक जीवन यानी वैभवशाली जीवन। उस समय इस तरह की लाइफस्टाइल के लिए 'लग्जरियस' शब्द का उपयोग नहीं होता था। 'लग्जरी' शब्द लेटिन भाषा के 'लग्जुरिया' से निकल कर आया है, जिसका अर्थ होता था- जरूरत से अधिक। आज उत्तम लाइफस्टाइल के संदर्भ में उपयोग में आता लग्जरी शब्द रोम के लिए निगेटिव था। शाहखर्ची जीवन जीने वाले लोगों को रोम में 'लग्जरिया' कहते थे। लेटिन से लग्जरी शब्द फ्रेंच बना तो इसका अर्थ थोड़ा बदला था। पुरानी फ्रेंच लग्जरी का अर्थ होता था वासना। 1340 में पुरानी अंग्रेजी में लग्जरी शब्द के शारीरिक संबंध के संदर्भ में भी उपयोग होने के प्रमाण हैं। 17वी सदी की अंग्रेजी की लिखावट में भोगविलास, समृद्धि, ऐश्वर्य के पर्याय के रूप में 'लग्जरी' शब्द का उपयोग होता था।

पर महंगी चीजों को 'लग्जरी प्रोडक्ट' कहना तो 19वीं सदी के अंत में शुरू हुआ। 19वीं सदी में निश्चित रूप से, अमुक संख्या में तमाम चीजवस्तुएं बनने लगीं। जिसे हम 'लिमिटेड एडीशन' कहते हैं, इस तरह के प्रोडक्ट को उस समय लग्जरी प्रोडक्ट कहते थे। खास बनाए चित्रों से ले कर तलवारें, सिंहासन, मुकुट, जूता, मद्यपान के लिए बनाया गया प्याला, राजा-रानी के नहाने लिए बनते सुगंधित द्रव्य आदि उस जमाने में लग्जरी प्रोडक्ट कहलाते थे और यह व्याख्या विश्वयुद्ध के बाद तेजी से बदल गई

आज लग्जरी कंपनियों का जो दुनियाभर में दबदबा है, इसकी शुरूआत बियर और शराब की कंपनियों से हुई। 1777 में स्थापित कंपनी बास ब्रिवेरी ऐसी पुरानी कंपनियों में से एक है। आज यह पूरी दुनिया में बियर बेचती हैं। 1837 में फ्रांस के धनवानों को ध्यान में रख कर हर्मिस नाम की कपड़ा की एक कंपनी बनी थी। यह सब से पुराना लग्जरी ब्रांड है। लुई बिट्टोन 1854 में बनी थी और आज यह दुनिया का सब से बड़ा लग्जरी ब्रांड

है। एलवी के लेबल के साथ यह कंपनी कपड़ा, जूता, परफ्यूम, घड़ी, ज्वेलरी, सनग्लासिस सहित कई लग्जरी प्रोडक्ट बनाती है। ग्लोबल लग्जरी प्रोडक्ट का बड़ा हिस्सा इसके पास है।

फिर तो चाय-कॉफी से ले कर कपड़ा-जूता, ब्यूटी प्रोडक्ट, ज्वेलरी, एससरीज, वेलनेस केट, कार, शराब तक सैकड़ो प्रोडक्ट लग्जरी ब्रांड के टैग के साथ बिकते हैं। यहां तक कि आब तो लग्जरियस टैग से मकानों की भी मार्केटिंग होती है। हाई

ज्वेलरी, फाइन वॉच, लग्जरी कार, लग्जरी होटल्स, फाइन फूड, गुड वाइन जैसी मार्केटिंग से लग्जरी प्रोडक्ट धनवानों में पॉपुलर हुए। सामान्य लोगों से हट कर लाइफस्टाइल। इस तरह धनवानों की पसंद से लग्जरी प्रोडक्ट को ग्लोबल मार्केट मिला।

दूसरे विश्वयुद्ध तक अमुक प्रोडक्ट ही लग्जरी माने जाते थे। परंतु विश्वयुद्ध के बाद दुनिया का मार्केट ओपन हुआ। एक देश का प्रोडक्ट आसानी से दूसरे देश में पहुंचने लगा। दो-ढाई दशक तक तो लग्जरी मेकर कंपनियां धनवानों के लिए ही लिमिटेड एडीशन में प्रोडक्ट बनाना चालू रखा। परंतु 1980 के बाद इसमें बड़ा परिवर्तन आया। अमेरिकी मध्यम वर्ग के पास इतना पैसा आया कि वह अच्छा खर्च कर सके। शहरीकरण बढ़ा। सोशल स्ट्रक्चर बदला। घर में स्त्री-पुरुष दोनों की कमाई आने लगी। इसलिए मध्यमवर्ग में लग्जरी प्रोडक्ट खरीदने का आकर्षण बढ़ा। परिणामस्वरूप कंपनियों ने लग्जरी कपड़ा-जूता आदि के प्रोडक्शन में बदलाव किया। और फिर इस तरह पूरी दुनिया में लग्जरी प्रोडक्ट का दबदबा बढ़ा।

2023 तक दुनिया में 55 करोड़ लग्जरी ग्राहक थे। परंतु 2024 के अंत तक इसमें 5 करोड़ ग्राहक घट गए हैं। 2025 में भी यह ट्रेंड यथावत रहा तो आने वाले साल में 42 करोड़ ही लग्जरी कस्टमर्स रह जाएंगे।

शायद इसीलिए अब लग्जरी मार्केट को भारत से बड़ी उम्मीद है। ग्लोबल लग्जरी कंपनियां दुनिया में आए लग्जरी कस्टमर्स की कमी को भारत से भरपाई करने की उम्मीद लगाए बैठी हैं। अब लग्जरी मार्केट की ग्रोथ की स्ट्राइक भारत के पास है। दुनिया की नजर इस बात पर है कि भारतीय लग्जरी कस्टमर्स कैसा स्ट्राइक रेट दिखाते हैं।

ग्लोबल लग्जरी मार्केट डाउन हुई, भारत की अप हो रही है। भारत में मध्यमवर्ग की खरीदशक्ति तेजी से बढ़ रही है। देश में एक बड़े वर्ग अपर मिडिल क्लास में धनवानों जैसा कपड़ा-जूता, ब्यूटी प्रोडक्ट का क्रेज बढ़ता जा रहा है। देश की मार्केट में दुनिया भर का लग्जरी सामान आसानी से मिल रहा है। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में तो ठीक, छोटे शहरों में भी अब देशी-विदेशी ब्रांडेड चीजवस्तुओं के शोरूम बन चुके हैं। एक ओर लग्जरी सामान मेकर कंपनियों में जबरदस्त प्रतिद्वंद्विता मची है तो दूसरी ओर ई-कॉमर्स कंपनियों के बीच प्रतियोगिता होने से डिस्काउंट प्राइस में ब्रांडेड चीजवस्तुएं मिल रही हैं, जो मध्यमवर्ग और लोअर वर्ग को आकर्षित करती हैं।

विदेशी कंपनियां तीन-चार दशक पहले भारत जैसे देश को ध्यान में रख कर प्रोडक्ट नहीं बनाती थीं। अब भारत का विशाल मार्केट उन्हें आकर्षित कर रहा है। भारत के इस विशाल मार्केट को कोई भी कंपनी इग्नोर नहीं कर सकती। ये सभी कंपनियां अब 'लाइन' में आ गई हैं और भारतीयों की खरीदशक्ति को ध्यान में रख कर प्रोडक्शन, मार्केटिंग करने लगी हैं। अभी मार्केट की स्थिति ऐसी है कि लोकल मार्केट के प्रोडक्ट में 80 प्रतिशत मिला दो तो ब्रांडेड प्रोडक्ट डिस्काउंट कीमत में मिल जाता है। जबकि विदेशी कंपनियां तो भारत के प्रोडक्ट और भारत के बाहर के प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अलग रखती हैं। प्रोडक्ट, नाम, पैकेजिंग वही होती है, पर प्राइस और क्वालिटी में अंतर होता है। इसलिए भारत की मार्केट में बेचना आसान होता है।

इन सभी कारणों से देश का लग्जरी मार्केट तेजी से विकसित हो रहा है। दुनिया में लग्जरी प्रोडक्ट का डाउनफॉल शुरू हुआ है तो भारत में इसका मार्केट लगातार अप हो रहा है। लेटेस्ट जानकारी के अनुसार भारत का लग्जरी मार्केट 3.16 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है।

भारत में धनवान ग्राहकों की संख्या तेजी से बढ़ी है। आरबीआई के डाटा के अनुसार क्रेडिट कार्ड धारकों की संख्या में 25 प्रतिशत की दर से बढ़ोत्तरी हो रही है। इस साल के प्रथम क्वार्टर में ही भारत में क्रेडिट कार्ड धारकों की संख्या 10 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। इन क्रेडिट कार्ड धारकों में से 65 प्रतिशत अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग लग्जरी प्रोडक्ट खरीदने के लिए कर रहे हैं। लग्जरी प्रोडक्ट की शापिंग और क्रेडिट कार्ड का सीधा संपर्क है। गोल्डमैन रिसर्च की जानकारी के अनुसार कहा गया है कि भारत में 2023-24 में 6 करोड़ समृद्ध ग्राहक थे, जो 2027 तक बढ़ कर 10 करोड़ हो जाएंगे। संभावना है कि 2030 तक देश में समृद्ध ग्राहकों की संख्या 20 करोड़ तक पहुंच जाएगी। ये समृद्ध ग्राहक लग्जरी सामान खरीदते हैं, इसलिए भारत में इसकी मार्केट में वृद्धि हो रही है।

पर्शियन मूल का समोसा भारतीयों का फेवरिट कैसे बना

वीरेंद्र बहादुर सिंह

देश में यह स्ट्रीट फूड सभी राज्यों में मिलता है। कहीं सुबह के नाश्ते में खाया जाता है तो कही दोपहर के भोजन के साथ लोग खाते हैं। कहीं-कहीं शाम को जलेवी और रबड़ी के साथ जोड़ी जमाता है तो कहीं रात के भोजन में एक कोने में समोसा रखा जाता है।

उत्तर, मध्य और पश्चिम भारत में तो समोसा बेहद पॉपुलर व्यंजन है। यहां तक कि समोसा बनाने वाले कारीगर दिन भर समोसा बनाते बनाते थक जाते हैं। उत्तर भारत का समोसा इतना लोकप्रिय हुआ कि अन्य राज्यों में इसकी फ्रेंचाइजी खूब चल रही हैं। शायद इसीलिए इसे उत्तर भारत का व्यंजन मान लिया गया।

उत्तर भारत में तो रोजाना लाखों नग समोसा खप जाता है। दक्षिण भारत में भी अन्य तमाम उत्तर भारतीय व्यंजनो की तरह स्वाद में थोड़ा-बहुत फेरबदल के साथ समोसा मिल जाता है। देश में यह इतना पॉपुलर है कि लोग इसे भारतीय व्यंजन मानते हैं।

जबकि हकीकत यह है कि समोसा मूल भारतीय फूड नहीं है। सैकड़ों साल पहले भारत में आकर अब पूरी तरह से भारतीय लगने वाले समोसे का इतिहास मजेदार है। रंग-रूप और स्वाद में भारतीय बन गए समोसे का जन्म आज के मध्य-पूर्व में हुआ था।

हिंदी, गुजराती, उर्दू, अंग्रेजी जैसी भाषाओं में 'समोसा' के नाम से पहचाने जाने वाले इस स्ट्रीट फूड का मूल नाम था - संबोसाग। इसका अर्थ था त्रिकोणीय पेंट्री। 'संबुसाग' शब्द पर्शियन भाषा से अरेबिक में उतरा तो 'संबुसाक' बना। उसके बाद 'संबुश्क' हुआ। अरेबिक रेसिपी बुक्स में 10वीं-11वीं सदी में 'संसुसाज' के नाम से इसका उल्लेख हुआ है।

ईराक के इतिहासकार, कवि, संगीतकार, गायक इशाक-अल-मावसिली ने 9वीं सदी में राजाओं के गुणगान लिखे तो उसमें लिखा कि खुशबूदार, चटकारेदार, स्वादिष्ट संबुसाज (समोसा) राजा के दरबार में परोसा जा रहा था। समोसा का उल्लेख होने का यह सब से पुराना रेफरेंस है।

इसके बाद अरब इतिहासकारों, राजकवियों ने भी अपनी रचनाओं में समोसा का बखान लिखा है। 10 से 13वीं सदी की तमाम अरब रेसिपी बुक्स में संबुसाक, संबुसाग, संबुसाज, संबोसाग जैसे शब्दों में त्रिकोणीय समोसा व्यंजन का उल्लेख है। ईरान के इतिहासकार अबुलफजल बेचहाकी ने 11वीं सदी में ईरान के राजाओं के शाही दरबार में पेश किए जाने वाले व्यंजनों के बारे में लिखा है। उसमें समोसा की पूरी जानकारी लिखी है। यह किस तरह बनता था और इसमें कितनी चीजों का उपयोग होता था, यह सब उसमे लिखा था। इसके मसाले में मांस के साथ ड्राइफ्रूट भी पड़ता था। ऊपर का आवरण आटे से बनता था। इस व्यंजन को सख्त और कुरकुरा बनाने के लिए तेल में तला जाता था। इस तरह का वर्णन उस पुस्तक में किया गया था।

परंतु फूड हिस्टोरियन का मानना है कि समोसा इसके पहले मध्यपूर्व में प्रचलित होना चाहिए। आज का ईरान ढ़ाई हजार साल पहले पर्शिया के नाम से जाना जाता था। तब समोसे का 'मसालेदार पेस्ट्री' के रूप में जन्म हुआ था। वह समोसा वेज नही था। मसाले में आलू की जगह मांस का उपयोग होता था और तेल में डीप फ्राई के बजाय तंदूर में सेंका जाता था। इस तरह समोसा नॉनवेज पफ जैसा था। बनावट में थोड़ा अंतर था। पफ की रेसिपी तब विकसित नहीं हुई थी। अंदाज है कि 5-7 सौ साल बाद ईरान या ईराक में समोसे को सेंकने के बजाय तला जाने लगा था।

उस समय पर्शिया का जमाना था। उसका साम्राज्य एक ओर तुर्की, इजिप्त तक और दूसरी ओर अफगानिस्तान तक फैला था। इन सभी इलाकों में पर्शिया की संस्कृति और खानपान का गहरा प्रभाव पड़ा। उसी समय समोसा भी मध्यपूर्व में फैला और अफगानिस्तान तक आ गया। वहां से आक्रमणकारियों के साथ समोसे ने भारत तक का सफर किया और हमेशा के लिए यहां बस गया।

13वीं सदी में अमीर खुशरो ने दिल्ली के सुलतान के दरबार में कैसा समोसा परोसा जाता था, इसका वर्णन किया है- मांस और प्याज को मिला कर तीखे मसाले से बने समोसे को धीमी आंच पर तला जाता था। उसमें से मनोहर सुगंध आती थी। उसका दरबारी और मेहमान तिथि-त्योहार पर आनंद उठाते थे।

14वीं सदी में विश्व की यात्रा करने वाले इब्नबतूता ने दिल्ली के सुलतान मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में

परोसे जाने वाले समोसे के बारे में लिखा था- मिर्च-मसाले से भरपूर मांस मिश्रित मसाले में पिस्ता, अखरोट, बादाम डाल कर बनाया गया समोसा मुख्य व्यंजन पुलाव के पहले परोसा जाता था। पर्शियन भाषा में 15वीं सदी में लिखी गई भारतीय व्यंजनों की पुस्तक 'निमतनामा' नासिर-अल-दिन शाही में मालवा के सुलतान कैसा समोसा बनाने का आग्रह करते थे, उसकी बात लिखी है। 16वीं सदी के 'आइने-अकबरी' में तेल में तल कर बनता हिंदुस्तानी 'सांबुसाह' का वर्णन है।

मध्यपूर्व का यह समोसा नॉनवेज था और राजा-महाराजा और अमीर-उमरावों का व्यंजन था। हिंदुस्तान के साधारण लोगों के लिए मांस-मसाला से बनने वाला यह व्यंजन उस समय मुश्किल था। पर यह पॉपुलर हुआ पुर्तगाल के कारण। भारत में पुर्तगाली आए और आलू साथ लाए। आलू ने राजा से ले कर रंक तक सभी की थाली में जगह बना ली। समय के साथ किसी ने बदलाव कर के मांस की जगह आलू का मसाला भरा। इस तरह पर्शियन मूल के समोसे में यूरोप का थोड़ा रंग लगा और इसका स्वाद भारतीयों के मुंह लग गया। वह भी इस हद तक कि आज दुनिया में सब से अधिक समोसा भारतीय ही खाते हैं।

भारत में एक दिन में अंदाजा है कि 6 करोड़ समोसा बिकता है। डीप फ्राई समोसा रोजाना खाने से हेल्थ को नुकसान पहुंचता है। फिर भी समोसा की लोकप्रियता वैसी ही बनी हुई है। मैदे के समोसे के विकल्प में कहीं कहीं गेहूं के आटे का भी समोसा बनता है।

समोसा आज किंग आफ स्ट्रीट फूड कहा जाता है। तमिल फूड हिस्टोरियन तो समोसा को दुनिया का 'प्रथम फास्टफूड' का भी टैग देते हैं। हमारे देश में समोसा असंख्य किसानों और मजदूरों के एक समय के भोजन का जरिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब में समोसा सब से सस्ता नाश्ता है। मिठाइयों के राज्य पश्चिम बंगाल में तो मीठा समोसा भी बहुत अच्छा बनता है।

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बड़ी साइज का समोसा बहुत बिकता है। गुजरात मे देश के सब से छोटी साइज के समोसे को भी खूब पसंद किया जाता है।

समोसा ज्यादातर राज्यों में हरी-लाल चटनी के साथ परोसा जाता है। कहीं समोसा को तोड़ कर उसके ऊपर चटनी डाल कर दिया जाता है तो समोसा को तोड़ कर चटनी में डुबो कर दिया जाता है।

और हां, पूरे भारत में इसका नाम समोसा ही नहीं है। पूर्व के राज्यों में इसे सिंघाड़ा भी कहा जाता है। दक्षिण के राज्यों में कहीं कहीं चमुसा के नाम से जाना जाता है।

समोसा की तह खोलने पर अंदर काफी कुछ मिलता है। भारतीय उपखंड में समोसा का दबदबा जगविख्यात है। पर अब यूरोप-अमेरिका में भी भारतीय स्वाद का समोसा पॉपुलर हो रहा है। इस तरह समोसा को 'ग्लोबल फास्टफूड' का टैग मिलना चाहिए।

हिमाचल में समोसा का विचित्र विवाद

बात यह हुई कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिं सुक्खू सीआईडी के हेडक्वार्टर में आयोजित एक कार्यक्रम में गए थे। अंतिम समय में अधिकारियों ने सीएम की प्लेट में निर्धारित व्यंजनों के अलावा समोफा और केक भी रखने का निर्णय लिया। इसके लिए जानेमाने होटल से टैक्स सहित 450 रुपए में इस तरह की 7 प्लेट का आर्डर दिया गया। एक प्लेट में 3 समोसे थे। इस हिसाब एक समोसा 150 रुपए का पड़ा। होटल को आर्डर सीआईडी हेडक्वार्टर से गया था। जिन अधिकारियों ने समोसा रिसीव किया, उन्हें पता नहीं था कि ये समोसे सीएम को परोसे जाने वाले हैं। उन अधिकारियों ने समोसों को कहीं और रख दिया और वे समोसे घूमते घूमते अधिकारियों की प्लेट के पहुंच कर उनके पेट में पहुंच गए। कार्यक्रम के बाद जिन अधिकारियों ने समोसों का आर्डर दिया था, उन्होंने सोचा कि सीएम की प्लेट में समोसे क्यों नहीं आए? उन्होंने पता लगाया तो पता चला कि सही ढ़ंग से कम्युनिकेशन न होने से सीएम तक आर्डर किए गए समोसे और केक नहीं पहुंचे '। सारे समोसे सीआईडी हेडक्वार्टर के कर्मचारियों को परोस दिए गए थे।

पूरी बात विपक्ष की भाजपा तक पहुंची तो इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया। मुद्दा उठा कि समोसा सीएम ने नहीं खाया तो खाया किस ने? मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि वह समोसा खाते ही नहीं है। खुलासा हुआ कि उनके मेन मैन्यू में समोसा और केक नही था। सीआईडी हेडक्वार्टर ने अपनी तरह से आंतरिक जांच की होगी। कांग्रेस का कहना है कि इसे ही विपक्ष के नेताओं ने सीआईडी जांच करा कर अफवाह फैलाई है। बात तब इतनी बढ़ गई कि भाजपा के विधायकों ने सीएम के लिए ऑनलाइन समोसे का आर्डर कर दिया। भाजपा युवा मोर्चा भी इस विवाद में शामिल हो गया और समोसा मार्च तक निकाल डाला।

इस तरह हिमाचल प्रदेश में सत्तापक्ष और विपक्ष सारे काम छोड़कर हाथ धो कर समोसे के पीछे पड़ गया। इसलिए वह पूरा सप्ताह समोसा और समोसा विवाद में ही बीता। विवाद राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा और समोसा सोशल मीडिया पर भी छा गया।

अमेरिका की अदालत का फैसला अच्छा, तहव्वुर राणा की याचिका खारिज करने के कदम का रामदास अठावले ने किया स्वागत

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा तहव्वुर हुसैन राणा की याचिका खारिज किए जाने पर कहा कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई के ताज होटल समेत अन्य स्थानों पर हमले हुए थे। उसमें कई लोगों की जान गई थी। तहव्वुर हुसैन राणा 26/11 हमले का सूत्रधार था। अमेरिका की अदालत का यह एक अच्छा फैसला है। अमेरिकी कोर्ट ने तहव्वुर राणा को भारत भेजने का तय किया है। हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं।

अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने मुंबई हमले के दोषी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी देते हुए इस कदम के खिलाफ उसकी पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी है। पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक राणा 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के मामले में वांछित है और भारत उसके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा था। भारत

प्रत्यर्पण से बचने के लिए राणा के पास यह अंतिम कानूनी मौका था इससे पहले, वह सैन फ्रांसिस्को में नॉर्थ सर्किट के लिए अमेरिकी अपील न्यायालय समेत कई संघीय अदालतों में कानूनी लड़ाई हार चुका है। राणा ने 13 नवंबर को अमेरिकी उच्चतम न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की थी। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के एक दिन बाद 21 जनवरी को उच्चतम न्यायालय ने उसकी अपील खारिज कर दी। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि याचिका को खारिज किया जाता है।

राणा को वर्तमान में लॉस एंजिलिस के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में हिरासत में रखा गया है। इससे पहले अमेरिकी सरकार ने अदालत में दलील दी थी कि पुरीक्षण याचिका को खारिज किया जाना चाहिए। अमेरिकी सॉलिसिटर जनरल एलिजाबेथ बी. प्रीलोगर ने 16 दिसंबर को उच्चतम न्यायालय में दाखिल अपने दस्तावेज में यह बात कही।

36 ग्रेनेड, आग्नेयास्त्र...गणतंत्र दिवस से पहले कहां बरामद हुआ विस्फोटकों का जखीरा?

उत्तरी त्रिपुरा में अवैध आग्नेयास्त्रों के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि असम पुलिस ने गणतंत्र दिवस समारोह से पहले एक तलाशी अभियान के दौरान शनिवार को बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया। पुलिस अधिकारी ने कहा कि बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले नीरज कुमार और इंदर मुखिया को शनिवार को त्रिपुरा के धर्मनगर उपमंडल के एक होटल से पकड़ा गया।

उनके कब्जे से मैगजीन सहित एक पिस्तौल बरामद की गई। दोनों पर शस्त्र अधिनियम के तहत आरोप लगाया जाएगा। हम यह पता लगाने के लिए जांच कर रहे हैं कि यह (पिस्तौल) किसने ऑर्डर किया था। अधिकारी ने कहा कि ये यह ऑपरेशन जिला खुफिया शाखा और धर्मनगर उप-विभागीय पुलिस द्वारा किया गया था।

इस बीच, असम पुलिस ने शनिवार को तलाशी अभियान चलाकर 36 हथगोले और पांच डेटोनेटर बरामद किए। ढेकियाजुली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत बताशीपुर के ख्वाबरा गांव के पास जंगल क्षेत्र में भूमिगत छिपे अवैध हथियारों और गोला-बारूद के गुप्त भंडारण के बारे में विश्वसनीय जानकारी के आधार पर, 25/1/2025 को एक तलाशी अभियान चलाया गया था। साइट की खुदाई के बाद विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। पॉलिथीन बैग में लिपटी हुई पाई गई वस्तुओं को प्रक्रिया के अनुसार जब्त कर लिया गया।

सोनितपुर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) बरुण पुरकायस्थ ने कहा कि ऑपरेशन के दौरान एक ग्रेनेड का पिन क्षतिग्रस्त हो गया।

क्षतिग्रस्त पिन/लीवर वाले ग्रेनेड को सुरक्षा में रखा गया है। सेना का बम निरोधक दस्ता जल्द से जल्द इसका निपटान करेगा।

असम पुलिस गणतंत्र दिवस समारोह से पहले राज्य के विभिन्न

हिस्सों में तलाशी अभियान चला रही है, क्योंकि प्रतिबंधित उग्रवादी समूह यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम-इंडिपेंडेंट (उल्फा-आई) ने एक बयान जारी कर इस साल गणतंत्र दिवस का बहिष्कार करने का आह्वान किया है।

वाईएसआरसीपी नेता के इस्तीफे पर नायडू ने कहा: यह पार्टी की वर्तमान स्थिति को दशार्ता है

अमरावती । राज्यसभा से वी. विजयसाई रेड्डी के इस्तीफा देने के बाद वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की ओर इशारा करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि किसी पार्टी से नेताओं का लगातार बाहर निकलना उसकी वर्तमान स्थिति को दशार्ता है। विपक्षी पार्टी का नाम लिए बिना मुख्यमंत्री ने कहा कि उसे (वाईएसआर कांग्रेस पार्टी) ऐसी स्थिति का नियमित रूप से क्यों सामना करना पड़ रहा है। रेड्डी ने कहा कि उन्होंने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को अपना इस्तीफा सौंपा है और इसे स्वीकार कर लिया गया है।

इससे पहले, शुक्रवार को रेड्डी ने कहा था कि वह किसी भी राजनीतिक पार्टी में शामिल नहीं होंगे और कृषि क्षेत्र में अपना भविष्य बनाएंगे। नायडू ने हाल में दावोस की अपनी यात्रा के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, हमारे पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि उनकी पार्टी के सदस्य क्यों छोड़कर जा रहे हैं।

अगर उन्हें विश्वास है, तो वे बने रहेंगे, अन्यथा वे अपने रास्ते तलाश लेंगे। मैं कह सकता हूं कि यह उस पार्टी (वाईएसआर कांग्रेस पार्टी) की स्थिति को दशार्ता है। नायडू ने कहा, मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, यह उनका आंतरिक मामला है।

जानकारी

कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है बाजरे की खिचड़ी

आजकल कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, हाई ब्लड प्रेशर और वजन का बढ़ना बहुत ही आम बात हो गई है। ऐसे में आपको अपने खानपान में सावधानी बरतनी बेहद जरूरी होती है। यही कारण है कि डाक्टर प्रोसेस्ड और जंक फूड के सेवन से दूर रहने की सलाह देते हैं। आप अपनी डाइट में इन सब चीजों के बजाय ऐसे खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थों को शामिल करें, जो कि आपके लिए स्वस्थ हों और आपको बीमारियों से दूर रखें। साबुत अनाज को बहुत ही स्वस्थ माना जाता है। ऐसे में आप अपने आहार में बाजरा जैसे साबुत अनाज, जो कि फाइबर से भरपूर होते हैं, उन्हें शामिल करें। इसमें विटामिन और खनिज जैसे पोषक तत्व होते हैं और यह मोटापे को कम करने के साथ मधुमेह के रोगियों के लिए यह बेहतर आहार है। अगर बाजरे से बनी खिचड़ी को अपनी डाइट में शामिल किया जाए, तो यह आपके बेहद फायदेमंद होगी।

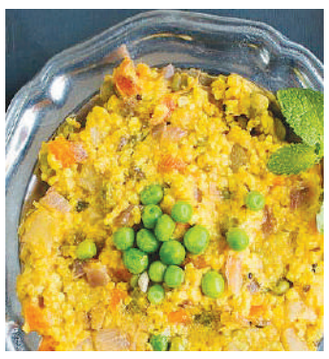

बाजरे की खिचड़ी की रेसिपी

- सफेद चावल की तुलना में यह अधिक फाइबर युक्त अनाज है, जो कि खिचड़ी के रूप में पकाया जाने पर, मधुमेह रोगियों के लिए एक अच्छा और स्वस्थ व्यंजन माना जाता है। बाजरे की खिचड़ी और दाल प्रोटीन व फाइबर से समृद्ध है।
- इसके लिए आप सबसे पहले 2 कप बाजरे को साफ कर इसका भूसा निकालकर धो लें।
- अब 1 कप धुली हुई मूंग दाल लें और बाजरें के साथ डालकर पर्याप्त पानी के साथ पकाने रख दें। 4 सीटी आने तक प्रेशर कुकर में कुक करें।
- अब आप एक पैन में 2 चम्मच घी डालें और गर्म करें। अब इसमें जीरा, हींग, धनिया पाउडर, गरम मसाला और मिर्च पाउडर डालें।
- जब जीरा भुन जाए, तो बाजरे और दाल का उबला हुआ मिश्रण डालें और अच्छे से मिलाएं। इसको 2-3 मिनट तक उबालें और फिर हरा धनिया डाल कर परोसें।

कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए फायदेमंद है बाजरा

फाइबर से भरपूर बाजरा आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद कर सकता है, जिससे आप दिल संबंधी बीमारियों से दूर रहते हैं। यह शरीर मे बैड कोलेस्ट्रॉल को दूर करके कोलेस्ट्रोल के स्तर को नियंत्रित करने और धमनियों के अवरुद्ध होने से रोकने में मदद करता है। जिससे आप हार्ट अटैक जैसी दिल की घातक बीमारियों से दूर रहते हैं। इसके अलावा बाजरा कई और बीमारीयों से बचाने में भी मदद करता है।

पाचन को दुरूस्त व एनर्जी

बाजरा ऐसा अनाज है, जो कि आपको एनर्जी देने के साथ आपके वजन को कम करने में भी मददगार है। इसलिए यदि आप बाजरे से बनी खिचड़ी का सेवन करते हैं, तो यह आपके वजन को कंट्रोल रखेगा। बाजरे की खिचड़ी से आपकी भूख शांत रहेगी, जिससे वजन कंट्रोल करने में मदद मिलती है.

ब्लड प्रेशर व ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रखे

बाजरा आपके लेवल ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। यह मौजूद मैग्नीशियम और पोटैशियम का भी अच्छा स्त्रोत है,जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मददगार है। इसके अलावा, बाजरा में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति के कारण, यह ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मददगार है। यह आपकी आंत के लिए भी लाभकारी है। इसमें धीरे-धीरे पचने वाले स्टार्च की उपस्थिति के कारण यह डायबिटीज में सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसके अलावा, बाजरा मैग्नीशियम से समृद्ध है, जो कि मधुमेह खतरे को कम करने में मदद कर सकता है।

अंधेपन का कारण न बन जाए ट्रेकोमा

आंखों की कुछ गंभीर बीमारियों में शामिल ट्रेकोमा कई बार अंधेपन का कारण बन जाता है। इसमें साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। आखिर क्या है यह बीमारी और इससे बचाव के क्या हैं उपाय, विशेषज्ञ से बातचीत कर आधारित

आंखों की होने वाली बीमारियों में एक ट्रेकोमा भी है। यह कंजंक्टिवाइटिस की तरह होने वाली संक्रामक बीमारी है, जो क्लैमाइडिया ट्रेकोमैटिस बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होती है। अगर समुचित इलाज न किया जाए या संक्रमण लंबे समय तक बना रहे, तो इससे आंखों की रोशनी भी जा सकती है। तभी इसे दुनियाभर में संक्रामक अंधेपन या नजर कमजोर होने का प्रमुख कारण माना जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, आज दुनियाभर में लगभग 14 करोड़ लोग ट्रेकोमा संक्रमण का शिकार हैं और ट्रेकोमा ब्लाइंडनेस के रिस्क पर हैं। हालांकि भारत में ट्रेकोमा के शिकार लोगों का प्रतिशत 0.7 से भी कम है। 2017 में भारत को ट्रेकोमा मुक्त घोषित कर दिया गया था, लेकिन इसकी अनदेखी बिल्कुल भी उचित नहीं है।

कैसे होती है पहचान

प्रभावित व्यक्ति की आंखों में किसी भी तरह की समस्या होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। नेत्ररोग विशेषज्ञ डॉक्टर अपने मरीज की केस हिस्ट्री जानने के साथ आंखों और पलक झपकने की जांच करते हैं।

लक्षण को जानें

बैक्टीरियल संक्रमण होने के बाद ट्रेकोमा के लक्षण

5-10 दिन के भीतर शुरू होते हैं। बैक्टीरिया आमतौर पर दोनों आंखों को प्रभावित करते हैं। हल्की खुजली और आंखों में जलन, पलकों खासकर ऊपरी पलक और लिम्फोमा नोड में सूजन, पलक के अंदर की ओर छोटी-सी सफेद गांठ, हल्का दर्द, लालिमा आ जाती है। पानी डिस्चार्ज होता है, रगड़ने पर निशान पड़ते हैं।

क्या हैं कारण

ट्रेकोमा बैक्टीरिया संक्रमित व्यक्ति की आंख, नाक और गले से निकलने वाले डिस्चार्ज के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फैलने के कारण होता है। यह एक व्यक्ति से दूसरे में आसानी से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने, कपड़े या निजी चीजें शेयर करने और संपर्क में आने पर बैक्टीरिया दूसरे व्यक्ति के शरीर में पहुचते हैं। यह पीड़ित व्यक्ति के डिस्चार्ज पर बैठी मक्खियों के माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक फैल सकता है। खासतौर पर ट्रेकोमा बैक्टीरिया की चपेट में खराब वातावरण में रहने, सामुदायिक स्वच्छता के अभाव, साफ पानी की कमी, शौचालय की समुचित व्यवस्था न होने, पर्सनल हाइजीन का ध्यान न रखने वाले व्यक्ति ज्यादा आते हैं। छोटे बच्चे इसके सबसे ज्यादा शिकार होते हैं। ट्रेकोमा बैक्टीरिया संक्रमण पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में चार गुना ज्यादा मिलता है, क्योंकि वे संक्रमित बच्चे के संपर्क में ज्यादा रहती हैं। कई मामलों में नवजात शिशु में होने वाला कंजंक्टिवाइटिस रोग ट्रेकोमा संक्रमित मां के कारण होता है।

इसमें क्या होता है

ट्रेकोमा बैक्टीरिया आंखों की ऊपरी पलक की अंदरूनी सतह कंजंक्टाइवा और कॉर्निया को प्रभावित करता है। संक्रमण होने पर आंखों की पलकों में धीरे-धीरे घाव होने लगता है और वह अंदर की तरफ मुड़ जाता है, जिसे ट्राइकियासिस कहा जाता है। अंदर मुड़ी पलकें कॉर्निया की सतह से रगड़ खाती हैं, जिससे आंखों में डिस्चार्ज के साथ तेज दर्द भी रहता है। दर्द से बचने के लिए मरीज अपनी पलकें बाहर निकालने की कोशिश करता है। समुचित उपचार न कराए जाने पर संक्रमण बढ़ता जाता है, जो कॉर्निया को नुकसान पहुंचाता है। इसमें कॉर्निया सिकुड़ने लगता है, जिससे नजर कमजोर होती जाती है और अंधेपन की स्थिति भी आ जाती है।

क्या हैं उपचार

- डब्ल्यूएचओ ने 2025 तक दुनियाभर में ट्रेकोमा की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य रणनीति विकसित की है। इसे उन्होंने सेफ नाम दिया है। इसके तहत एस यानी सर्जिकल देखभाल, ए यानी एंटीबायोटिक्स, एफ यानी चेहरे की सफाई और ई यानी साफ-सफाई युक्त अच्छा पर्यावरण या वातावरण ।
- मरीज की स्थिति के हिसाब से एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक की सिंगल ओरल डोज दी जाती है, जिसे कम से कम 3 साल तक ।
- 6 महीने में दोहराया जाता है। यह मेडिसिन बैक्टीरिया को नष्ट करने, संक्रमण के उपचार और बीमारी के प्रसार को कम करने के लिए दी जाती है। एंटीबायोटिक्स केवल मरीज को ही नहीं, परिवार के दूसरे सदस्यों को भी दी जाती है। जिन क्षेत्रों में ट्रेकोमा के मरीज ज्यादा हैं, वहां बड़ेपैमाने पर इलाज की जरूरत होती है। पूरे समुदाय के लोगों पर नजर रखी जाती है।
- पलक में ज्यादा विकृति आने पर सर्जरी करके पलक को ठीक किया जाता है, ताकि पलकों के रगड़ने से आई-बॉल को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे।
- ट्रेकोमा संक्रमण के जोखिम और पुनः संक्रमण को कम करने के लिए मरीज को ही नहीं, पूरे समुदाय के लिए समुचित कदम उठाने की योजना बनाई जाती है।

(नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. निखिल सेठ)

सुझाव

ब्लड शुगर लेवल को तुरंत कंट्रोल करती है लाल प्याज

डायबिटीज रोगियों को ब्लड शुगर लेवल को बनाए रखना मुश्किल होता है। ऐसे में आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना जरूरी है कि क्या खाएं और क्या नहीं। आपको अपने ब्लड शुगर लेवल की समय-समय पर जांच जरूर करनी चाहिए। क्योंकि इससे आपके खानपान के प्रभावों का पता चलता है। मधुमेह को स्वाभाविक रूप से नियंत्रित करने के लिए, अपने आहार में ऐसे भोजन को शामिल करने की सलाह दी जाती है जो ब्लड शुगर को कम कर सकते हैं। रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना आवश्यक है क्योंकि अगर इसे अनुपचारित छोड़ दिया जाए तो गंभीर स्थिति पैदा हो सकती हैं।

यदि आप ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने के लिए सर्वोत्तम खाद्य पदार्थों की तलाश कर रहे हैं, तो आप इसके लिए प्याज की मदद ले सकते हैं। प्याज आपकी रसोई का घटक है जो आपको मधुमेह से प्रभावी रूप से लड़ने में मदद कर सकता है। प्याज हर भारतीय रसोई का एक अनिवार्य हिस्सा है जिसे लगभग हर कोई अपने भोजन में शामिल करता है। अब आपको बस इतना करना है कि अपने आहार में प्याज को शामिल करें।

लो-ग्लाइसेमिक इंडेक्स

प्याज लो-ग्लाइसेमिक फूड है जिसे आप अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स रक्त शर्करा के स्तर पर कंज्यूम किए गए भोजन के प्रभाव का वर्णन करता है। जिन खाद्य पदार्थों में 55 से कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, उन्हें मधुमेह के लिए अच्छा माना जाता है क्योंकि वे रक्त में बहुत अधिक शर्करा नहीं छोड़ते हैं। प्याज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 10 से कम है जो डायबिटिक के लिए बहुत अच्छा है।

कार्ब्स में कम

प्याज में बहुत कम कार्ब्स होते हैं। बहुत अधिक कार्ब्स का सेवन किसी के ब्लड शुगर लेवल के लिए अच्छा नहीं है। यदि आप बहुत अधिक कार्ब्स खाते हैं, तो आपको टाइप-2 डायबिटीज होने का अधिक खतरा है। आधा कप कटा हुआ प्याज में केवल 5.9 ग्राम कार्ब्स होते हैं। तो Lo-carb आपको प्रभावी ढंग से मधुमेह का प्रबंधन करने में मदद कर सकती है।

फाइबर में अधिक

डायबिटीज के लिए फाइबर बेहद फायदेमंद है। यह ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। प्याज भी फाइबर से भरपूर होते हैं जो उन्हें मधुमेह रोगियों के लिए एक आदर्श घटक माना जाता है। फाइबर आंत के स्वास्थ्य को बढ़ावा देगा और पेट से संबंधित आपकी सभी समस्याओं को दूर रखेगा। प्याज का नियमित सेवन आपको कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने और हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में भी मदद करेगा।

मधुमेह के लिए प्याज का सेवन कैसे करें

बेहतर ब्लड शुगर लेवल के लिए आपको कच्चा प्याज खाना चाहिए। इसके अलावा, सुनिश्चित करें कि आप लाल प्याज चुनते हैं। आप कच्चा प्याज अपने लंच के साथ-साथ रात के खाने में भी खा सकते हैं। यदि आपको सलाद पसंद है तो आप इसे अपने सलाद में शामिल कर सकते हैं। कच्चा प्याज आपके सैंडविच में भी मिलाया जा सकता है।

क्या आप सही तरह से कर रहे हैं शैंपू का प्रयोग

बालों की गंदगी निकालने और उसे साफ रखने के लिए हम सप्ताह में 2 से 3 दिन शैंपू करते हैं, लेकिन फिर भी बालों की समस्याएं बढ़ रही हैं, इसका प्रमुख कारण है कि हम अपने शैंपू का प्रयोग सही तरीके से नहीं कर रहे, क्या आप भी अपने शैंपू का प्रयोग सही तरीके

शैंपू लगाने का सही तरीका

बालों की सुंदरता बनाए रखने के लिए उसकी देखभाल जरूरी है। इसलिए बालों की प्रकृति के अनुसार ही शैंपू की चयन किया जाना चाहिए। साथ ही शैंपू लगाने की तरीके का भी विशेष ख्याल रखें। जैसे शैंपू को बालों पर सीधे न लगायें, पहले बालों को गीला करें, फिर थोड़े पानी में घोलने के बाद शैंपू को बालों पर लगाएं। झाग बनाते या बालों को रगड़ते समय उन्हें उलझाएं नहीं, न ही ज्यादा रगड़ें। शैंपू 3-4 मिनट तक लगाकर रखना चाहिए, न इससे कम न ज्यादा। इससे गंदगी साफ होने के लिए वक्त मिल जाता है। शैंपू को अच्छी तरह साफ करने के बाद कंडीशन लगाएं। एक मिनट तक लगाए रखने के बाद कंडिशनर को अच्छी तरह से धो लें।

सामान्य बालों के लिए

अगर आपके बाल सामान्य हैं तो आप कोई भी अच्छी क्वालिटी की पोषण देने वाले शैंपू का चुनाव कर सकते हैं। शैंपू हेयर टेक्स्चर के आधार पर प्रयोग करें। सामान्य बालों को सप्ताह में दो बार शैंपू करना चाहिए। प्रोटीन युक्त शैंपू में मौजूद कैराटिन कोलेजन और सिल्क प्रोटीन बालों को चमक प्रदान करने के साथ ही सुरक्षा कवच भी प्रदान करते हैं।

घने बालों के लिए

कई महिलाओं के बाल प्राकृतिक रूप से घने और सुंदर होते है। इस तरह के बालों की चिकनाई को रोकने के लिए रोजाना या हर दूसरे दिन शैंपू करना जरूरी होती है। घने बालों में आप अगर रोजाना शैंपू नहीं कर सकते हो तो ड्राई शैंपू का प्रयोग करें। ये आपके स्कल्प को भी पोषित करता है। आपके बाल खराब ना हो या झड़ें ना इसके लिए आप अच्छी क्वालिटी के शैंपू का ही प्रयोग करें। जिससे आपके बालों का घनापन बना रहें।

ऑयली बालों के लिए

ऑयली बाल आमतौर पर सीधे और सिल्की होते हैं। इनकी देखभाल के लिए शैंपू का चुनाव करते वक्त ध्यान रहे कि शैंपू क्रीम बेस कतई न हो। आप लेमन, टी ट्री ऑयल, साइट्रस फ्रूट्स वाले शैंपू इनके लिए अच्छा विकल्प हैं। आमतौर पर इनके लिए कंडीशनर की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है लेकिन अगर आप इसका प्रयोग भी करते हैं तो कंडीशनर लगाने के बाद तुरंत धो लें। ध्यान रहे कि ऑयली बालों के लिए जितना महत्वपूर्ण शैंपू का चुनाव है, उतना ही तवज्जो अधिक से अधिक बालों को साफ रखने पर भी देना चाहिए।

रूखे बालों के लिए

ड्राई बालों के लिए क्रीम बेस शैंपू ही सटीक है। यह बालों को मुलायम बनाते हैं, जिससे बाल उलझते नहीं हैं। शैंपू खरीदते वक्त यह देख लें कि उसमें ग्लीसरिन या कोलेजन हो, जिससे शैंपू के दौरान बालों की नमी बरकरार रहे। इसके अलावा इनके लिए अल्ट्रा मॉश्चराइजिंग कंडीशनर का इस्तेमाल करें।

कलर किए बालों के लिए

अगर आप हेयर कलर का इस्तेमाल करते हैं या बालों पर कोई केमिकल ट्रीटमेंट करवाया है तो शैंपू या कंडीशनर का चुनाव करने से पहले अपने बालों की जरूरत को समझना और भी जरूरी है। ऐसे में बालों को रिपेयर करने वाले शैंपू पर जोर देना चाहिए जो कलर वाले बालों को कमजोर होने से बचा सकें। इनके लिए प्रोटीन बेस शैंपू देखें जिनमें सोया, मिल्क या सिल्क अमीनो एसिड जैसे तत्व मौजूद हों। इसके अलावा, बाजार में कलर प्रोटेक्शन शैंपू भी उपलब्ध हैं जो लंबे समय तक आपके बालों का कलर बरकरार रखते हैं। लेकिन अगर ये आपके बजट पर भारी हैं तो इनकी जगह आप माइल्ड बेबी शैंपू का इस्तेमाल करें। इनकी उपयोगिता में खास फर्क नहीं है।

घुंघराले बालों के लिए

आमतौर पर घुंघराले बाल रूखे होते हैं, क्योंकि उनके सिर की त्वचा से निकलने वाला तेल बालों तक आसानी से पहुंच नहीं पाता है। ऐसे में उनके लिए शैंपू का चुनाव करते वक्त यह ध्यान रखना चाहिए कि वह क्रीमी और मॉइश्चराइजर युक्त हों। इसके अलावा, आप बादाम, बटर, ग्लीसरिन या सिलिकॉन वाले शैंपू का चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा, घुंघराले बालों के लिए एक्स्ट्रॉ मॉइश्चराइजर कंडीशनर बेहद जरूरी है जिससे बालों को संभाला जा सके।

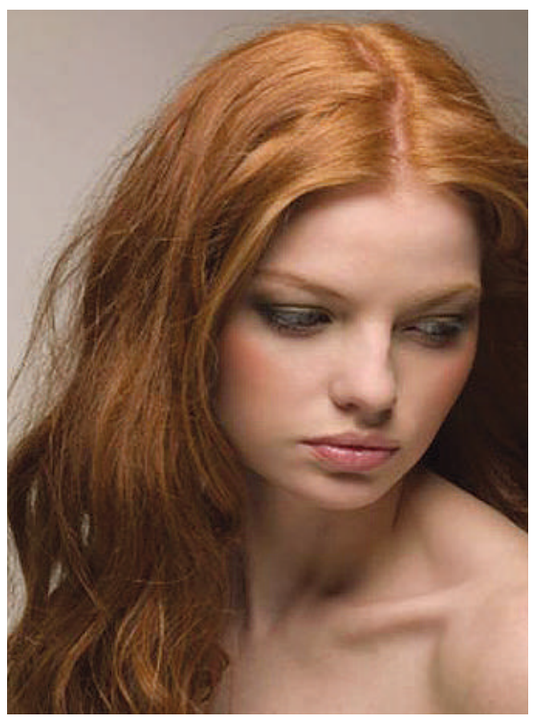

इन बातों का रखें खयाल

शैंपू खरीदते समय इस बात का खयाल रहे कि उसमें केमिकल्स की मात्रा ज्यादा ना हो। अच्छी ब्रांड के उत्पाद अक्सर गुणवत्ता की कसौटी पर खरे होते हैं। लेकिन ब्रांड के साथ-साथ अपने बालों की जरूरत का भी ध्यान दें। केवल महंगी ब्रांड का प्रोडक्ट लेने के बजाय आप यह समझें कि आपकी जरूरत के हिसाब से क्या सही है। हमेशा एक्सपायरी डेट देखकर ही प्रोडक्ट खरीदें। बालों की किसी खास समस्या से परेशान हैं और बाजार में मिलने वाले एंटी-डैंड्रफ या हेयर फाल शैंपू और कंडिशनर ही काफी नहीं है, ऐसे में डॉक्टर से मिलें और मेडिकल ट्रीटमेंट लें।

रेसिपी

मसाला सेवई

सामग्री

- भुनी सेवई- 1 कप
- प्याज- 1 (बारीक कटी)
- टमाटर- 1 (बारीक कटा)
- अदरक-लहसुन पेस्ट- 1 चम्मच
- उबली मटर- 1/2 कप
- शिमला मिर्च- 1/2 कप
- जीरा- 1/2 चम्मच
- लाल मिर्च पाउडर- 1/2 चम्मच
- हल्दी- 1/2 चम्मच
- धनिया पाउडर- 1/2 चम्मच
- कसूरी मेथी- 1 चम्मच
- गरम मसाला- 1/2 चम्मच
- नींबू का रस- 1 चम्मच
- पानी- 1 कप
- धनिया पत्ती- बारीक कटी (गॉर्निशिंग के लिए)

विधि

कढ़ाही में तेल गर्म करें। अब उसमें जीरा डाल तड़काएं। फिर इसमें प्याज डालकर भुनें। अब इसमें शिमला मिर्च, मटर डालें। इसी के साथ इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट भी डालकर मिलाएं। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर डालकर मिक्स करें। अब मसाले हल्के भुन जाएं तब इसमें भुनी सेवइयां डालें। अब पानी डाल इसे अच्छे से पका लें। गैस बंद करने से पहले इसमें गरम मसाला, कसूरी मेथी और हरा धनिया डालें। गरमा गरम नाश्ता तैयार है।

पुदीना पराठा

सामग्री

- आटा- 2 कप
- नमक- स्वादानुसार
- पुदीना पत्ती- 1/2 कप (बारीक कटी)
- पानी- आवश्यकतानुसार

मसाले के लिए

- जीरा- 1 चम्मच
- काली मिर्च- 1/2 चम्मच
- चाट मसाला- 1/2 चम्मच
- तेल- 2 चम्मच

विधि

आटे में नमक, तेल और पुदीना पत्ती मिक्स कर पानी मिलाकर अच्छे से इसे गूंथ लेंगे। अब इसे सेट होने के लिए 15-20 मिनट रख दें। तब तक हम मसाला तैयार कर लेंगे। इसके लिए जीरा और काली मिर्च के दाने को भुनकर उसे मिक्सी में पीस लेंगे और इसमें चाट मसाला भी डाल देंगे।

अब आटे की लोई बनाएंगे। इसे बेल लेंगे और उसके ऊपर मसाला छिड़ककर उसका रोल बना लेंगे। रोल को एक बार फिर बेलेंगे फिर इसके ऊपर मसाला बुरककर एक बार फिर यही स्टेप दोहराएंगे।

तवे को गर्म कर इस पर पराठे को घी से सेंक लेंगे। तैयार है आपका पुदीना पराठा, जिसे आप आलू की सूखी सब्जी के साथ सर्व करें।

तबादलों के बावजूद इंस्पेक्टर महावीर और श्रीकृष्णा विभाग छोड़ने को तैयार नहीं

प्रवर्तन इंस्पेक्टर के पी डागर का भी तबादला

नवीन खाती

नई दिल्ली। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद में इन दिनों एक बड़ा विवाद खड़ा होता दिखाई दे रहा है, जहां कुछ विभागों के कर्मचारियों के बीच वर्चस्व और राजनीतिक

A-42011/356/2023-Secy-Estt.

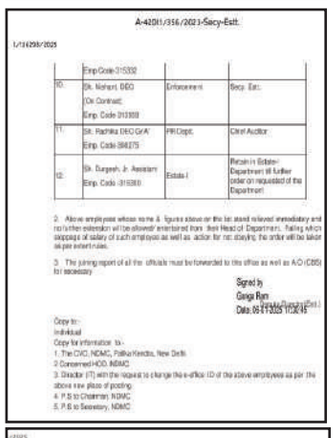

Office Order

A-42011/356/2023-Secy-Estt.

	Emp Code-315332		
10.	Sh. Nishant, DEO (On Contract) Emp. Code 313300	Enforcement	Secy. Estt.
11.	Sh. Radhika DEO Gr'A' Emp. Code-308275	PR Dept.	Chief Auditor
12.	Sh. Durgesh, Jr. Assistant Emp. Code -315380	Estate-I	Retain in Estate-I Department till further order on requested of the Department

2. Above employees whose name & figures above on the list stand relieved immediately and no further extension will be allowed/ entertained from their Head of Department. Failing which stoppage of salary of such employee as well as action for not obeying the order will be taken as per extent rules.

3. The joining report of all the officials must be forwarded to this office as well as A.O (CBS) for necessary

Signed by
Ganga Ram
Date: 05-01-2025 17:36:45

Copy to:-
Individual
Copy for information to:-
1. The CVO, NDMC, Palika Kendra, New Delhi
2. Concerned HOD, NDMC
3. Director (IT) with the request to change the e-office ID of the above employees as per the above new place of posting.
4. P.S to Chairman, NDMC
5. P.S to Secretary, NDMC

NEW DELHI MUNICIPAL COUNCIL
PALIKA KENDRA NEW DELHI
SECRETARY's ESTABLISHMENT BRANCH

OFFICE ORDER

In partial modification office order dated 20.01.2025 and with the approval of Competent Authority, the following staff are transferred and posted with immediate effect:

Sr. No.	Name of Officials & Designation	Emp. Code No.	Previous Place of Posting	New Place of Posting
1.	Smt. Ekta Sharma, Sr. Asstt.	310581	Secretary Establishment	O/o Financial Advisor in addition to her present assignment in Secy. Estt.
2.	Sh. Bhaskar Bhatt, DEO Gr. 'A'	309679	O/o Financial Advisor	CBS
3.	Sh. Srinivas, Palika Sahayak (Sthapana)	308818	Under posting	O/o Financial Advisor
4.	Sh. Radhey Shyam, DEO Gr. 'A'	309610	CPH	O/o Sh. Parag K. Singh, Director
5.	Sh. Deepak, Sr. Asstt.	311003	Law	Enforcement
6.	Sh. Krishan Pal Dagar, Sr. Asstt.	310969	Enforcement	Law

2. Above employees whose names & figures above on the list stand relieved immediately and no further extension will be allowed/entertained from their Head of Department. Failing which stoppage of salary of such employee as well as action for not obeying the order will be taken as per extant rules.

3. The joining report of all the officials must be forwarded to this office as well as A.O. (CBS) for necessary action.

Signed by
Satish Kumar
Date: 21-01-2025 15:04:38

Joint Director (Estt.)

Copy to:-

ट्रांसफर आदेश, जिनकी अवहेलना करते दिख रहे हैं इंस्पेक्टर महावीर और इंस्पेक्टर श्रीकृष्णा

फोटो गवाह हैं कि किस तरह इंस्पेक्टर महेश ने सफदरगंज व एम्स के पास अवैध पटरी बाजार का पूरा मॉल ही सजा डाला है..

तंत्र का गहरा खेल चल रहा है। प्रवर्तन विभाग में हुए हालिया तबादलों के चलते यह मामला चर्चा का विषय बन गया है। विशेष रूप से प्रवर्तन विभाग के इंस्पेक्टर महावीर, जो प्रवर्तन निदेशक के खास बताये जा रहे हैं, के तबादले ने सत्ता और प्रभाव के खेल को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इंस्पेक्टर महावीर लंबे समय से प्रवर्तन विभाग में थे और जिनके खिलाफ अवैध पटरी बाजारों को संरक्षण देने के गंभीर आरोप लग रहे हैं, उनके तबादले को लेकर अधिकारियों के बीच टकराव जारी है। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद में कुछ विभाग ऐसे है जहां कर्मचारी बार-बार आना चाहते हैं और आने के बाद वहां से वापस जाना ही नहीं चाहते! खासकर जनपथ क्षेत्र, जो कि किसी भी प्रवर्तन इंस्पेक्टर के लिए स्वप्निल तैनाती स्थल माना जाता है, इंस्पेक्टर महावीर के पास था। महावीर पहले भी प्रवर्तन विभाग में रह चुके हैं। सूत्रों के अनुसार प्रवर्तन नॉर्थ क्षेत्र में अवैध पटरी बाजारों से और अवैध कब्जे वाले दुकानदारों से वसूलीकरण इनके और इनके चहेतों द्वारा किया जाता है।

हालांकि, 6 फरवरी 2025 को जारी स्थानांतरण आदेश संख्या I/136398/2025 में इंस्पेक्टर महावीर का तबादला किसी अन्य विभाग में कर दिया गया है, लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि अभी तक प्रवर्तन निदेशक ने उन्हें रिलीव नहीं किया है। माना जा रहा है कि इंस्पेक्टर महावीर ने अपने राजनीतिक तंत्र व अधिकारी तंत्र का प्रयोग कर प्रवर्तन विभाग में ही रहने का पक्का इरादा कर लिया है। यहां हम बता दें कि उनकी जगह इंस्पेक्टर टी एन मिश्रा ज्वाइन भी कर चुके हैं। अब देखना है कि इन हालातों में परिषद सचिव की चलती हैं या फिर इंस्पेक्टर महावीर की।

इसी आदेश में एक अन्य इंस्पेक्टर श्रीकृष्णा, जो गोल मार्केट व शिवाजी स्टेडियम में तैनात थे, का भी प्रवर्तन विभाग से किसी अन्य विभाग में स्थानांतरण किया गया है, लेकिन वह भी इंस्पेक्टर महावीर की ही तर्ज में अपना स्थानांतरण रुकवाने की जुगत भिड़ाने में लगे हुए हैं। अब देखना यह है कि कौन कितना कामयाब होता है, वे इस सरकारी आदेश को मानते हैं या फिर इसकी अवहेलना करते हैं।

ये सारा खेल सिर्फ और सिर्फ अवैध पटरी बाजार को संरक्षण देने का माना जा रहा हैं, जिसके तहत ये इंस्पेक्टर सुविधाशुल्क वसूलकर अपना तो भला कर ही रहे हैं बल्कि अपने आलाधिकारियों को भी खुश कर रहे हैं। इंडिया मेल ने अपने पिछले अंक में अवैध पटरी बाजारों को संरक्षण देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों का खुलासा करने का वादा किया था। हालांकि, इसके पूर्व ही या कहें इंडिया मेल के खुलासे से पहले ही इंस्पेक्टर महावीर, श्रीकृष्णा इत्यादि संबंधित अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इन विभागों में कुछ गहरे खेल चल रहे हैं।

इसके साथ ही, सरोजनी नगर के इंस्पेक्टर के. पी. डागर का भी तबादला प्रवर्तन विभाग से किसी अन्य विभाग में कर दिया गया है। सफदरजंग और एम्स क्षेत्रों में तैनात इंस्पेक्टर महेश कथित रूप से अवैध पटरी बाजारों को निर्भीकता से संरक्षण दे रहे हैं जिसकी कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं। इंस्पेक्टर महेश की गतिविधियों को भी लेकर सवाल उठने लगे हैं, उनके खिलाफ भी शीघ्र कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

अब यह देखना दिलचस्प होगा कि ये सभी तबादले क्या सिर्फ प्रशासनिक सुधार का हिस्सा हैं या फिर इस पूरे मामले के पीछे कोई गहरा राजनीतिक तंत्र काम कर रहा है।

इस मामले की पूरी जानकारी जल्द ही इंडिया मेल के आगामी अंक में मिलेगी, जहां हम अवैध वसूली के इस खेल को विस्तृत रूप से उजागर करेंगे।

अगले अंक में :

एनडीएमसी के प्रवर्तन विभाग के चलते क्या एनडीएमसी कर रही हैं किसी बड़े हादसे का इंतजार?

एनडीएमसी की बैठकों में केजरीवाल की अनुपस्थिति पर चहल का हमला

मुकेश टम्टा

एनडीएमसी उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल

नई दिल्ली। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल अपने कार्यकाल के दौरान एनडीएमसी की काउंसिल की बैठकों में केवल 53% उपस्थित रहे, जो उनके नई दिल्ली और वहाँ के लोगों के प्रति लापरवाह रवैये को दशार्ता है।

चहल ने जानकारी दी कि 2014 से 2024 तक कुल 126 एनडीएमसी काउंसिल बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें से केजरीवाल ने केवल 65 बैठकों में भाग लिया और 57 बैठकों में अनुपस्थित रहे।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केजरीवाल बैठक के बीच में अक्सर बाहर चले जाते थे।

चहल ने आगे बताया कि अरविंद केजरीवाल, जो नई दिल्ली के विधायक भी हैं, एनडीएमसी सदस्य के रूप में शपथ लेने से लगातार बचते रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा, ₹नई दिल्ली के लोग उन्हें तीन बार चुन चुके हैं, लेकिन वह अपनी जिम्मेदारियों से बचते रहे।₹

उपाध्यक्ष ने यह भी उजागर किया कि केजरीवाल ने एनडीएमसी कर्मचारियों की समस्याओं को नजरअंदाज किया और उनके कल्याण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। उन्होंने यह भी कहा कि केजरीवाल की अनदेखी के कारण नई दिल्ली के निवासी बुनियादी सुविधाओं, जैसे जल आपूर्ति, जलभराव और प्रदूषण जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। चहल ने यह भी उल्लेख किया कि एनडीएमसी के तहत 4,500 कर्मचारियों का नियमितीकरण प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के समर्थन से हुआ, लेकिन केजरीवाल ने इस मामले में कोई भूमिका नहीं निभाई। चहल ने अंत में कहा कि अब समय आ गया है कि नई दिल्ली के लोग आगामी विधानसभा चुनावों में केजरीवाल को अपना जवाब दें, क्योंकि उनकी नीतियां और विकास योजनाओं के साथ सहयोग की कमी दिल्ली के विकास में रुकावट डाल रही है।

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत द्वारा कम्बल वितरण

मुकेश टम्टा

नई दिल्ली। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, मध्य जिले के कार्यकताओं ने गत दिवस की संध्या को समाज सेवा का एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। कनॉट प्लेस स्थित प्रसिद्ध श्री हनुमान मंदिर परिसर में जरूरतमंदों को ठंड से राहत देने के उद्देश्य से कम्बल वितरित किए गए।

इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के प्रांत कार्यकारिणी सदस्य माननीय दीपक चोपड़ा जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके साथ मध्य जिले की नवगठित कार्यकारिणी के सदस्यों ने भी इस पुनीत कार्य में भाग लिया।

कार्यकारिणी के सदस्यों में अध्यक्ष सुदेश कुमार नायक, उपाध्यक्ष पवन

कुमार चावला, सह सचिव दिनेश पुंज, कोषाध्यक्ष पंडित हरे कृष्ण गोस्वामी, और अन्य सदस्य मुकेश मिश्रा, एडवोकेट कल्पना अग्रवाल, अभिषेक यादव, अजय शर्मा, तथा कपिल मग्गो ने अपनी सक्रिय भागीदारी दर्ज कराई।

कार्यक्रम के दौरान जरूरतमंदों को कम्बल वितरित करते हुए दीपक चोपड़ा जी ने कहा, ठंड के मौसम में गरीबों की मदद करना हम सभी का सामाजिक दायित्व है। ऐसे कार्य समाज में सेवा और सहयोग की भावना को प्रोत्साहित करते हैं।

इस पहल को स्थानीय नागरिकों और भक्तों ने खूब सराहा। यह आयोजन समाज के प्रति सेवा भाव और सामुदायिक एकता का प्रतीक बनकर उभरा।

कजेरीवाल के समर्थन में उतरे अखिलेश, योगी को दी चुनौती, कहा- मथुरा में यमुना से पानी पीने की करें हिम्मत

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा यमुना नदी प्रदूषण को लेकर आप नेता पर हमला करने के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल के बचाव में कूद पड़े हैं।

योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष करते हुए, अखिलेश यादव ने सवाल किया कि क्या उत्तर प्रदेश के सीएम मथुरा में यमुना नदी से पानी का एक घूंट पीने की हिम्मत करेंगे।

सपा प्रमुख ने एक हिंदी पोस्ट में कहा, दूसरों को चुनौती देने से पहले, लोगों को अपने राज्य में मथुरा से बहने वाली यमुना से पानी पीने की हिम्मत करनी चाहिए।

एक्स पर एक पोस्ट में अखिलेश यादव ने सीएम योगी का नाम लिए बिना कहा, जो लोग दूसरों को चुनौती देते हैं उन्हें अपने राज्य में मथुरा से बहने वाली यमुना के पानी से आचमन करना चाहिए। यादव की यह तीखी प्रतिक्रिया तब आई है जब आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में भाजपा के लिए प्रचार करते हुए कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने यमुना को "गंदा नाला" बनाकर पाप किया है।

आदित्यनाथ, जिनके मंत्रियों ने बुधवार को महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में संगम में डुबकी लगाई, ने सवाल किया कि क्या केजरीवाल और उनके मंत्री उनके मंत्रिमंडल की तरह यमुना में स्नान कर सकते हैं।

दिल्ली के किरारी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए, आदित्यनाथ ने आगे आरोप लगाया कि दिल्ली से उत्तर प्रदेश में आने वाले गंदे यमुना पानी के कारण मथुरा-वृंदावन के भक्तों और संतों को परेशानी हो रही है।

दिलचस्प बात यह है कि यादव की समाजवादी पार्टी और केजरीवाल की अअढ विपक्ष के इंडिया ब्लॉक के अभिन्न घटक हैं, जिसकी घोषणा वर्ष 2024 के आम चुनावों से पहले की गई थी। इंडिया ब्लॉक ने भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को चुनौती दी थी।

झारखंड पुलिस की एसआईटी ने सरकारी धन गबन मामले में 1.83 करोड़ रुपये नकदी जब्त की

झारखंड पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने सरकारी धन गबन के मामले में विभिन्न खातों में करीब 47.96 करोड़ रुपये की रकम पर रोक लगा दी है। मामले में 1.83 करोड़ रुपये बरामद किए जाने के साथ 16.70 लाख रुपये के आभूषण जब्त किए गए हैं। एक आधिकारिक बयान में शनिवार को यह जानकारी दी गई।

एक अधिकारी ने बताया कि आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) के पुलिस अधीक्षक ऋषभ झा के नेतृत्व में एसआईटी ऊर्जा और पर्यटन विभागों में राज्य सरकार के उपक्रमों से जुड़े खातों से लगभग 109 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से निकासी के मामलों की जांच कर रही है।

पुलिस के बयान में कहा गया कि अब तक इन मामलों के संबंध में सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

20 जनवरी को एसआईटी ने डोरंडा में रामलखन यादव के आवास पर छापा मारा और 60 लाख रुपये नकद बरामद किए। मामले में एक बैंक के शाखा प्रबंधक को भी गिरफ्तार किया गया था। बयान में कहा गया कि मामले में जांच की जा रही है।

प्रकाशक, मुद्रक, संपादक, स्वामी नवीन खाती द्वारा प्राइमा प्रिंटर्स, वाई-56, ओखला फेज-2, नई दिल्ली -110020 से मुद्रित एवं यू-110, सूर्या आर्केड, उपाध्याय ब्लॉक, विकास मार्ग, शकरपुर, दिल्ली-110 092 से प्रकाशित.
ई- मेल : indiamail2008@gmail.com Mo. 8802226437